II आर्थिक समीक्षा

वर्ष 2025-26 में, निरंतर वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, स्थिर घरेलू मांग और मज़बूत सेवा क्षेत्र के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूत बनी रही। हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी आई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट और अनुकूल आधार प्रभाव रहा। जमाराशि और ऋण दोनों में दोहरे अंकों की वृद्धि देखने को मिली। केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज़ोर देते हुए, अपने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रयासों को जारी रखा। वैश्विक व्यापार में बनी अनिश्चितताओं के बावजूद, बाहरी क्षेत्र आघात -सहनीय बना रहा। चालू खाता घाटा अपने टिकाऊ स्तर के दायरे में ही रहा और विदेशी मुद्रा भंडार भी पर्याप्त स्तर पर बना रहा, जिससे समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बल मिला।

II.1.1 2025 में, व्यापार और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद, वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.4[1] प्रतिशत पर बनी रही; इसमें प्रौद्योगिकी में निवेश, राजकोषीय और मौद्रिक सहायता, तथा अनुकूल वित्तीय स्थितियों का योगदान रहा। वैश्विक मुद्रास्फीति एक साल पहले के 5.8 प्रतिशत से घटकर 4.1[2] प्रतिशत पर आ गई, हालाँकि सेवाओं की लागत अभी भी ऊँची बनी हुई है। जहाँ एक ओर, अग्रिम-भारण और प्रौद्योगिकी निर्यात के चलते व्यापार में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 5.1[3] प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, वहीं दूसरी ओर, राजकोषीय परिदृश्य कमज़ोर पड़ा। भू-राजनीतिक जोखिमों और मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के कारण बाज़ार में अस्थिरता बनी रही, लेकिन मार्च 2026 के अंत में पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के बाद इसमें और तेज़ी आई। 2025 में लगातार कमज़ोरी के बाद, 2026 में भू-राजनीतिक जोखिमों के बढ़ने के साथ ही अमेरिकी डॉलर में मज़बूती आने लगी। इसके अलावा, राष्ट्रिक बॉन्ड प्रतिफल, जो 2025 में काफी हद तक कम रहे थे, उनमें चालू वर्ष के दौरान ऊपरी दबाव देखा गया; इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण उत्पन्न ऊर्जा-जनित मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएँ थीं।

II.1.2 वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि के बावजूद, मांग पक्ष पर स्थिर निजी उपभोग और मजबूत निवेश तथा आपूर्ति पक्ष पर सेवाओं में तेजी और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। मजबूत कृषि उत्पादन और वैश्विक पण्य कीमतों में नरमी के कारण खाद्य कीमतों में तीव्र गिरावट से हेडलाइन मुद्रास्फीति 2025-26 के दौरान और कम हुई। तथापि, कीमती धातुओं के कारण मूल मुद्रास्फीति पर दबाव बना रहा। भारतीय वित्तीय बाजारों ने आघात -सहनीयता दिखाया, जहां मुद्रा बाजार दरें नीतिगत रेपो दर और मौजूदा चलनिधि स्थितियों के अनुरूप विकसित हुईं। 2025-26 में शेयर बाजारों में द्विदिशात्मक उतार-चढ़ाव देखा गया, क्योंकि सहायक मौद्रिक और राजकोषीय नीति उपायों ने बाजार भावना में सुधार किया, जबकि भू-राजनीतिक और टैरिफ अनिश्चितताओं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित चिंताओं से उत्पन्न नकारात्मक वैश्विक संकेतों ने जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश डाला। 2025-26 के दौरान, केंद्र सरकार ने अपने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और पूंजीगत व्यय पर जोर देना जारी रखा, जबकि उसका कुल व्यय बजटीय लक्ष्य के भीतर ही रहा। राज्यों ने भी राजस्व व्यय को नियंत्रित करते हुए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी, जिससे व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ। वर्ष के दौरान पूंजी प्रवाह में कमी के बावजूद, मामूली चालू खाता घाटे और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार ने बाह्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान की।

[1,2,3] विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), अप्रैल 2026, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)।

II.1.3 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय के शेष भाग को छह खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में वास्तविक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसके बाद खंड 3 में मुद्रास्फीति और उसके कारकों का विश्लेषण किया गया है। मौद्रिक समुच्चयों और वित्तीय बाजारों में हुए घटनाक्रमों को क्रमशः खंड 4 और 5 में प्रस्तुत किया गया है। खंड 6 में सरकारी वित्त (केंद्र और राज्यों) के विकास पर चर्चा की गई है, और खंड 7 में बाह्य क्षेत्र की गतिशीलता को शामिल किया गया है।

II.2 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.2.1 2025-26 में बढ़े हुए बाह्य आघातों, विशेष रूप से अप्रैल 2025 में अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाने के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत और स्थिर संवृद्धि पथ पर बनी रही। मजबूत समष्टि-आर्थिक मूल-तत्वों (मैक्रोइकॉनोमिक फंडामेंटल्स) और सक्रिय नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली वृहत अर्थव्यवस्था बनी रही। मांग पक्ष में उपभोग और निवेश में स्थिर वृद्धि, एवं सेवा क्षेत्र में उछाल तथा आपूर्ति पक्ष में औद्योगिक गतिविधि में सुधार से आर्थिक गतिविधि को बल मिला।

समग्र मांग

II.2.2 समग्र मांग - स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा मापी जाती है – वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 7.1 प्रतिशत थी (सारणी II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 1)[4]। जीडीपी में वृद्धि का मुख्य आधार निम्न घरेलू चालक थे - निजी अंतिम उपभोग व्यय और निश्चित निवेश (चार्ट II.2.1 और परिशिष्ट सारणी 2)।

II.2.3 अमेरिका द्वारा अपने व्यापारिक भागीदारों पर भारी प्रशुल्क (टैरिफ) लगाने से प्रारंभ में बाह्य क्षेत्र और समग्र जीडीपी वृद्धि पर संभावित अवरोध के बारे में चिंताएं बढ़ गई थीं। हालांकि, प्रतिकूल प्रभाव-विस्तार (स्पिलओवर) सीमित

सारणी II.2.1. वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(प्रतिशत)

घटक	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4
I. कुल उपभोग व्यय	**4.9**	**5.9**	**7.5**
निजी	5.8	5.8	7.7
सरकारी	0.6	6.5	6.6
II. सकल पूंजी निर्माण	**8.7**	**6.1**	**6.5**
सकल निर्धारित पूंजी निर्माण	7.3	6.4	7.1
शेयरों में बदलाव	116.9	1.7	10.4
मूल्यवान आस्तियाँ	-9.3	1.9	-15.8
III. निवल निर्यात			
निर्यात	0.7	6.6	6.5
आयात	-1.0	5.3	6.4
IV. जीडीपी	**7.2**	**7.1**	**7.6**

टिप्पणी: आँकड़े 2022-23 आधार श्रृंखला पर आधारित हैं।
स्रोत: एनएसओ।

ही रहे, और 2025-26 में निवल निर्यात में केवल 0.1 प्रतिशत अंक का मामूली अवरोध हुआ।

उपभोग

II.2.4 वर्ष 2025-26 के दौरान, निजी अंतिम उपभोग व्यय - जो समग्र मांग का मुख्य आधार है - में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि

चार्ट II.2.1: जीडीपी संवृद्धि में भारित योगदान

(प्रतिशत अंक)

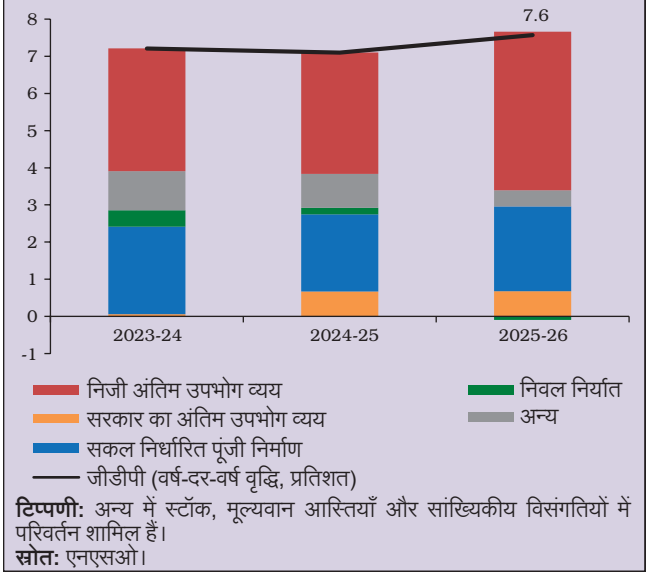

टिप्पणी: अन्य में स्टॉक, मूल्यवान आस्तियाँ और सांख्यिकीय विसंगतियों में परिवर्तन शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ।

[4] इस रिपोर्ट के अध्याय 1 के फुटनोट 3 का संदर्भ लीजिए।

हुई, जो एक वर्ष पहले के 5.8 प्रतिशत के स्तर से मजबूत हुआ। इस वृद्धि की गति को ग्रामीण उपभोग में स्थिरता और शहरी मांग में सुधार से बल मिला, जिसका श्रेय आंशिक रूप से आयकर में कटौती और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के युक्तिकरण को दिया जा सकता है।[5] सरकार का अंतिम उपभोग व्यय 6.6 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा।

निवेश और बचत

II.2.5 सकल घरेलू निवेश दर, जिसे मौजूदा कीमतों पर जीडीपी की तुलना में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के अनुपात से मापा जाता है, 2024-25 में मोटे तौर पर 34.3 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही।[6] सकल निर्धारित पूंजी निर्माण – जो जीसीएफ का एक मुख्य घटक है - 2025-26 में 7.1 प्रतिशत की मजबूत गति से बढ़ा (एक वर्ष पहले 6.4 प्रतिशत), जैसा कि इसके प्रमुख संयोग संकेतकों के निरंतर निष्पादन में परिलक्षित होता है (चार्ट II.2.2)। सरकार के नेतृत्व में पूंजीगत व्यय ने एक प्रति-चक्रीय भूमिका निभाना जारी रखा, जिससे

चार्ट II.2.2: निश्चित निवेश मांग के संकेतक

(वृद्धि, प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

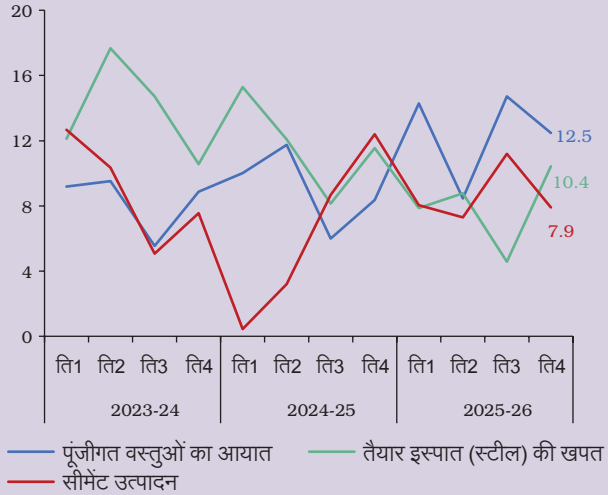

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, एनएसओ, एवं वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)।

निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिली। अगस्त 2025 में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार ने निवेशकों के विश्वास को और मजबूत किया। वर्ष के दौरान कॉरपोरेट आय में भी सुधार हुआ।[7] जहाँ वर्ष 2025-26 की शुरुआत में कॉरपोरेट बिक्री वृद्धि कम हो गई थी, वहीं मजबूत मांग के बीच तीसरी तिमाही तक इसमें गति आयी।

II.2.6 सकल घरेलू बचत वर्ष 2023-24 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के 32.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 34.2 प्रतिशत हो गई। निवल घरेलू वित्तीय बचत 2024-25 में बढ़कर जीएनडीआई का 7.0 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 5.8 प्रतिशत थी; क्योंकि घरेलू वित्तीय देयताओं में आई गिरावट का प्रभाव, सकल वित्तीय बचत में आई कमी से कहीं अधिक रहा (परिशिष्ट सारणी 3)। सकल घरेलू वित्तीय बचत 2023-24 के 12.1 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में जीएनडीआई का 11.8 प्रतिशत हो गई, जबकि घरेलू वित्तीय देयताएँ पिछले वर्ष के 6.4 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में जीएनडीआई के 4.8 प्रतिशत पर आ गईं। लिखत-वार देखें तो, घरेलू वित्तीय बचत में जमाराशियों का प्रभुत्व है, इसके बाद भविष्य निधि और पेंशन निधियों, बीमा का स्थान है, साथ ही शेयरों और डिबेंचरों में निवेश में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है (सारणी II.2.2)।

II.2.7 वर्ष 2024-25 के दौरान बचत-निवेश अंतर कम हुआ, जिसमें घरेलू क्षेत्र, निधियों का प्रमुख निवल आपूर्तिकर्ता बना रहा; इसकी अधिशेष निधियाँ 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में जीडीपी का 7.8 प्रतिशत हो गईं (चार्ट II.2.3)। अधिक बचत और कम निवेश के चलते निजी निगमों का संसाधन अंतर कम हो गया, जबकि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण ने सामान्य सरकार की बचत में कमी को पिछले वर्ष की जीडीपी के 5.3 प्रतिशत से घटाकर जीडीपी का 4.6 प्रतिशत कर दिया। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के

[5] ट्रैक्टर और यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट, उच्च खरीफ उत्पादन और स्थिर वैयक्तिक ऋण वृद्धि जैसे कई उच्च आवृत्ति संकेतकों ने पूरे वर्ष मांग को बनाए रखने में मदद की।

[6] यहां रिपोर्ट की गई सकल घरेलू निवेश दर, पण्य प्रवाह (आस्ति-आधारित) दृष्टिकोण पर आधारित है।

[7] 2025-26 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही के दौरान, निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र का औसत परिचालन लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के 5.7 प्रतिशत से निरंतर बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गया।

सारणी II.2.2: घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए. सकल वित्तीय बचत	**10.7**	**10.4**	**11.9**	**11.8**	**11.4**	**15.2**	**10.9**	**11.2**	**12.1**	**11.8**
जिनमें से:										
1. मुद्रा	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4	1.9	1.1	-	-	-
2. जमाराशियाँ	4.6	6.3	3.0	4.2	4.3	6.2	3.5	-	-	-
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	-	-	-
4. सरकार पर दावे	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	-	-	-
5. बीमा निधियाँ	1.9	2.3	2.0	2.0	1.7	2.8	2.0	-	-	-
6. भविष्य निधि एवं पेंशन निधियाँ	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5	2.3	-	-	-
बी. वित्तीय देयताएं	**2.7**	**3.0**	**4.3**	**4.0**	**3.8**	**3.7**	**3.8**	**6.0**	**6.4**	**4.8**
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	**7.9**	**7.3**	**7.5**	**7.8**	**7.6**	**11.6**	**7.2**	**5.2**	**5.8**	**7.0**

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। -: उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणियाँ: 1. संभव है कि संख्याओं के पूर्णांकन (राउंडिंग ऑफ) के कारण आँकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

2. 2022-23 के बाद के डेटा संशोधित आधार वर्ष 2022-23 के अनुसार हैं।

स्रोत: एनएसओ एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

स्तर पर बचत-निवेश के अंतर का कम होना, बाह्य पूंजी पर निर्भरता में कमी और बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशीलता का संकेत देता है।

चार्ट II.2.3: बचत-निवेश अंतर को कम करना

(जीडीपी का प्रतिशत)

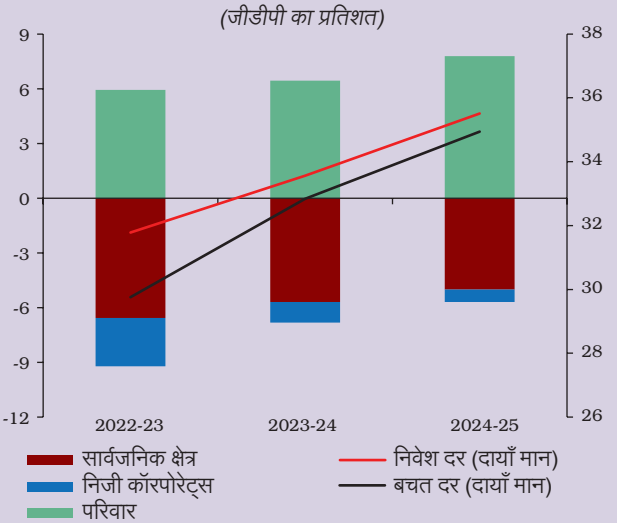

टिप्पणी: निवेश दर निधियों के प्रवाह (वित्तपोषण-आधारित) दृष्टिकोण पर आधारित है।

स्रोत: एनएसओ एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

समग्र आपूर्ति

II.2.8 समग्र आपूर्ति – जो मूल कीमतों पर वास्तविक योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी जाती है – में 2025-26 में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले यह 7.3 प्रतिशत थी)। जीवीए वृद्धि का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में आई तेजी और औद्योगिक गतिविधि में उल्लेखनीय सुधार था, भले ही कृषि क्षेत्र में कुछ नरमी देखी गई (सारणी II.2.3)।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

II.2.9 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि की गति धीमी रही, जो खरीफ फसलों में मौसम संबंधी व्यवधानों को दर्शाता है, हालांकि अनुकूल रबी परिस्थितियों ने कुछ राहत प्रदान की। सामान्य से अधिक[8] दक्षिण-पश्चिम मानसून (चार्ट II.2.4.ए) ने जलाशय के स्तर की सर्वकालिक उच्च स्तर पर पुनःपूर्ति करने में सहायता की (चार्ट II.2.4.बी)[9,10]। उच्च जलाशय स्तर[11] और मानसून के बाद सामान्य से अधिक

[8] भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सामान्य वर्षा सीमा, दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) का 96-104 प्रतिशत है।

[9] मानसून ने 24 मई 2025 को केरल में दस्तक दी, जो अपने सामान्य आगमन की तारीख (1 जून) से आठ दिन पहले आ गया, यह 2009 के बाद से शीघ्रतम आगमन को चिह्नित करता है।

[10] जलाशय का जलस्तर 9 अक्टूबर 2025 को उसकी पूर्ण क्षमता के 91.4 प्रतिशत तक पहुंच गया।

[11] जलाशय का जलस्तर 27 मार्च 2026 तक पूर्ण क्षमता का 47 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.5 प्रतिशत और दस वर्षीय औसत से 21.0 प्रतिशत अधिक था।

सारणी II.2.3: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र		2023-24	2024-25	2025-26
1		2	3	4
I.	**कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य पालन**	**2.6**	**4.2**	**2.4**
II.	**उद्योग**	**11.3**	**8.7**	**9.5**
	II.1 खनन और उत्खनन	2.4	11.7	4.1
	II.2 विनिर्माण	12.7	9.3	11.5
	II.3 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	10.7	2.9	1.5
III.	**सेवाएँ**	**7.4**	**7.8**	**8.7**
	III.1 निर्माण	9.9	7.3	7.1
	III.2 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ, भंडारण	10.1	6.6	10.1
	III.3 वित्तीय, स्थावर संपदा, आईटी, पेशेवर सेवाएँ एवं आवासों का स्वामित्व	5.5	10.0	9.9
	III.4 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	6.8	5.0	5.8
IV.	**आधार कीमतों पर जीवीए**	**7.2**	**7.3**	**7.7**

टिप्पणी: आँकड़े 2022-23 आधार श्रृंखला पर आधारित हैं।

स्रोत: एनएसओ एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वर्षा[12] होने के कारण, इस वर्ष रबी की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक क्षेत्र में हुई[13]। साथ ही, ग्रीष्म (जायद) मौसम के लिए बुवाई भली-भांति जारी है।

II.2.10 द्वितीय अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार, 2025-26 में कुल खाद्यान्न (खरीफ और रबी) उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान है। इस वर्ष खरीफ चावल, गेहूँ, मक्का, खरीफ मूंगफली, रेपसीड और सरसों तथा गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहा (सारणी II.2.4)।

II.2.11 प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2025-26 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया, जो मुख्य रूप से केला, टमाटर और बागान फसलों द्वारा संचालित रहा[14]।

II.2.12 सरकार ने प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों [15] में वृद्धि की घोषणा की, जिससे उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का रिटर्न सुनिश्चित हुआ[16]। रबी विपणन मौसम 2025-26 में गेहूँ की खरीद चार

चार्ट II.2.4: वर्षा एवं जलाशय स्तर

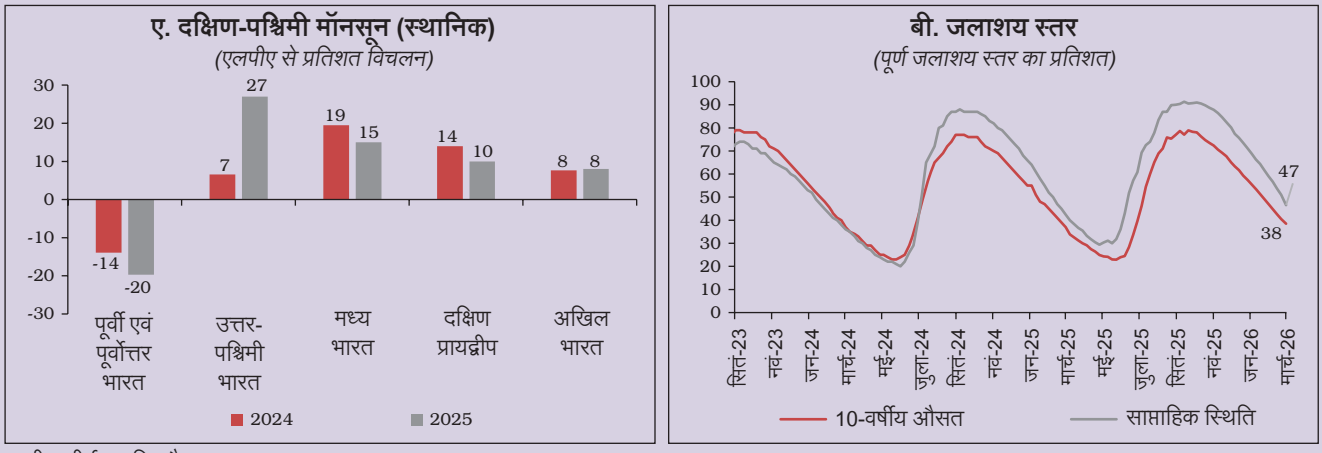

एलपीए: दीर्घ अवधि औसत।

स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) एवं केंद्रीय जल आयोग (सीडबल्यूसी), भारत सरकार।

[12] 2025 में मॉनसून के बाद की वर्षा (1 अक्टूबर - 31 दिसंबर) अपने एलपीए से 11 प्रतिशत अधिक थी।

[13] रबी फसलों के तहत बोया गया अंतिम क्षेत्र (30 जनवरी 2026 तक) पिछले वर्ष की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक था। सभी प्रमुख फसलों का एकड़ में क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा है।

[14] 2025-26 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 3,708 लाख टन रहने का अनुमान है जो 2024-25 के अंतिम अनुमानों की तुलना में थोड़ा अधिक (0.03 प्रतिशत) है।

[15] यह वृद्धि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए 1.0-13.9 प्रतिशत और रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए 4.0-10.1 प्रतिशत की सीमा में है।

[16] वास्तविक भुगतान की गई लागत एवं पारिवारिक श्रम का मूल्य (ए2+एफएल)।

सारणी II.2.4: कृषि फसल उत्पादन 2025-26*

(लाख टन)

फसलें	2024-25 अंतिम अनुमान	2025-26 द्वितीय अग्रिम अनुमान (एसएई)	2024-25 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 2025-26 एसएई घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. खाद्यान्न	3,386.3	3,486.6	3.0
चावल	1,389.0	1,406.5	1.3
गेहूँ	1,179.5	1,202.1	1.9
मोटे अनाज	588.2	639.3	8.7
दालें	229.7	238.7	3.9
तूर	36.2	34.6	-4.7
चना	111.1	117.9	6.1
मसूर	16.5	17.3	4.8
उड़द	18.9	17.1	-9.5
मूँग	18.7	20.7	10.4
2. तिलहन	416.6	410.0	-1.6
3. गन्ना (केन)	4,546.1	5,002.0	10.0
4. कपास #	297.2	290.9	-2.1
5. जूट और मेस्ता ##	88.0	83.4	-5.2

*: *खरीफ* और *रबी फसलें* (ग्रीष्म ऋतु की फसलें छोड़कर)।
#: प्रत्येक 170 किलोग्राम की लाख गठरियाँ (बेल)।
##: प्रत्येक 180 किलोग्राम की लाख गठरियाँ (बेल)।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वर्षों के उच्चतम स्तर पर रही है और खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में चावल की खरीद भी मजबूत रही है।

II.2.13 मार्च 2026 के अंत तक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा धारित खाद्यान्न का कुल सार्वजनिक भंडार, बफर आवश्यकता के चार गुना से भी अधिक रहा; इसका मुख्य कारण चावल का उच्च भंडार है (चार्ट II.2.5)[17]। सरकार ने इस अतिरिक्त भंडार में से 52 लाख टन चावल इथेनॉल मिश्रण (ब्लेंडिंग) के लिए आबंटित किया है। इसी तरह, गेहूँ और गेहूँ से तैयार उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी गई है[18]। आगे चलकर, आगामी खरीफ मौसम के दौरान *अल नीनो*[19] की संभावना पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है।

औद्योगिक क्षेत्र

II.2.14 औद्योगिक क्षेत्र की जीवीए वृद्धि 2025-26 में बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण गतिविधि, जो औद्योगिक क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा है, ने 2025-26 में तेजी हासिल की, जैसा कि 2025-26 की पहली छमाही में बिक्री

चार्ट II.2.5: स्टॉक और बफर नॉर्म की पर्याप्त मासिक स्थिति

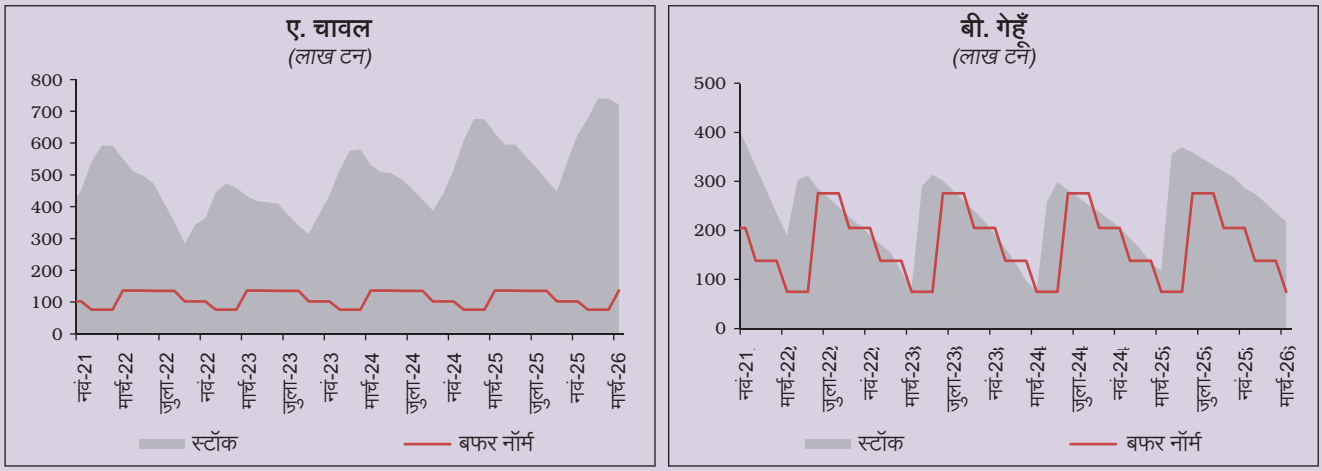

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

[17] कुल स्टॉक 939 लाख टन रहा, जिसमें चावल का स्टॉक 721.2 लाख टन (बफर मानदंडों का 5.3 गुना) और गेहूँ का स्टॉक 217.9 लाख टन (बफर आवश्यकता का 2.9 गुना) था।

[18] 'सरकार गेहूँ के निर्यात को मंजूरी देती है और अतिरिक्त गेहूँ उत्पाद और चीनी निर्यात की अनुमति देती है', पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), 13 फरवरी 2026।

[19] नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के अनुसार, मई-जुलाई 2026 में, अल नीनो के उभरने की संभावना है (82 प्रतिशत संभावना) और यह कम-से-कम 2026 के अंत तक बना रहेगा।

चार्ट II.2.6: संगठित विनिर्माण फर्म

(वृद्धि, प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

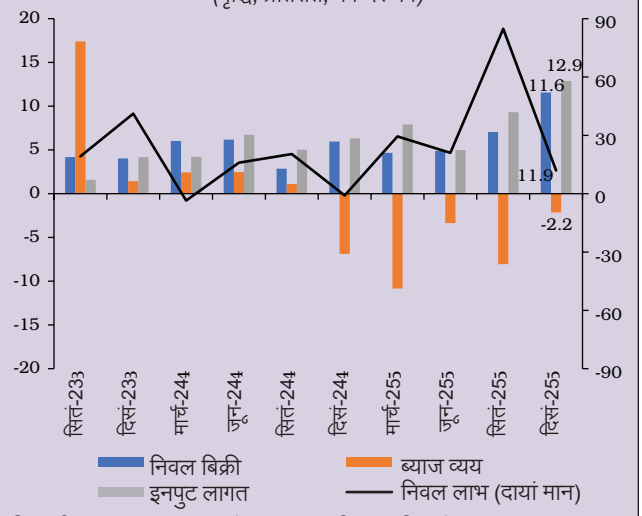

टिप्पणी: कुल नमूना आकार में 1,799 कंपनियां शामिल हैं।
स्रोत: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) इंडस्ट्री आउटलुक।

में हुई अधिक वृद्धि और लाभप्रदता से परिलक्षित होता है (चार्ट II.2.6)।

II.2.15 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में, 2025-26 की पहली छमाही के दौरान खनन और विद्युत क्षेत्रों के कारण कुछ नरमी देखी गई (चार्ट II.2.7ए)। 2025-26 की दूसरी छमाही में, खनन गतिविधि में तेजी तथा विनिर्माण क्षेत्र के और मजबूत होने से आईआईपी में सुधार हुआ। कुल मिलाकर, विनिर्माण क्षेत्र ने 2025-26 में विस्तार दर्ज करने वाले 23 उद्योग समूहों में से 16 में मजबूत वृद्धि दर्ज की। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, उद्योगों की सभी श्रेणियों में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.2.7बी)।

II.2.16 नवीकरणीय ऊर्जा (वृहत जल विद्युत सहित), जो विद्युत उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा है, वह 2025-26 में 18.4 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी (चार्ट II.2.8)। मार्च 2026 के अंत तक, भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 283 गीगावाट (कुल संस्थापित विद्युत क्षमता का 53.2 प्रतिशत) तक पहुंच गई - जिससे भारत वर्ष 2030 से पहले 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता के अपने सीओपी26 लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हो गया है[20]। निवेश का रुख नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मुड़ गया है, अधिकांश नवीन परियोजना व्यय अब पारंपरिक क्षमता के बजाय इस क्षेत्र में केंद्रित हैं।

II.2.17 2025-26 की पहली छमाही के दौरान शिथिल रहने के बाद, क्षमता उपयोग और निजी पूंजीगत व्यय, दोनों में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत दिखे, जो वर्ष की दूसरी छमाही में कारोबारी विश्वास और मांग की उत्साहजनक स्थितियों

चार्ट II.2.7: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

ए. क्षेत्रवार संवृद्धि

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

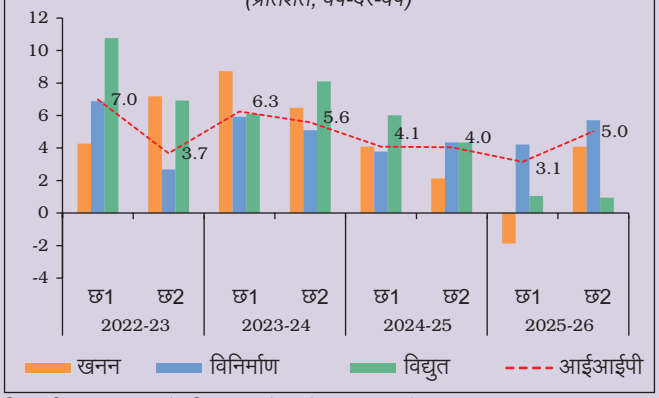

बी. उपयोग आधारित वर्गीकरण - संवृद्धि

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

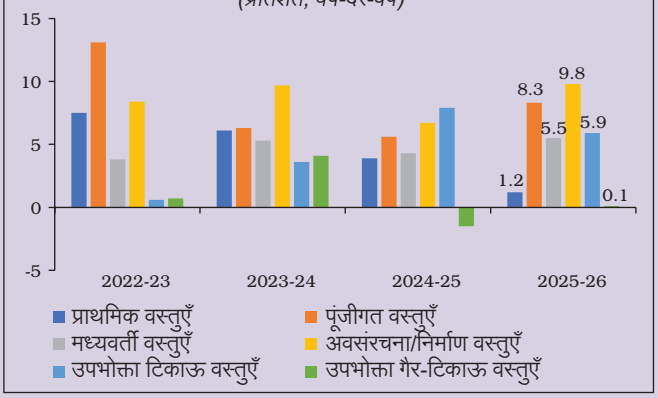

टिप्पणी: मार्च 2026 के लिए आँकड़े त्वरित अनुमान हैं।
स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

[20] गैर-जीवाश्म ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा (वृहत जल विद्युत सहित) और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं।

चार्ट II.2.8: नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

(हजार गीगावाट-प्रति घंटा, बायाँ मान; प्रतिशत, दायां मान)

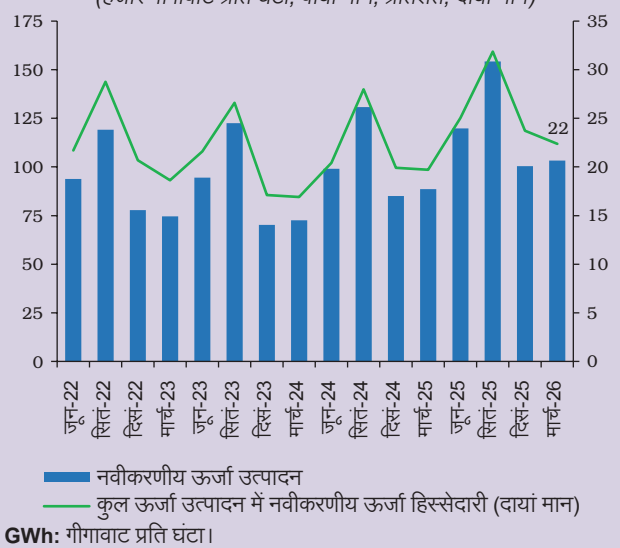

GWh: गीगावाट प्रति घंटा।

स्रोत: केंद्रीय बिजली प्राधिकरण।

चार्ट II.2.9: विनिर्माण क्षमता उपयोग

(प्रतिशत)

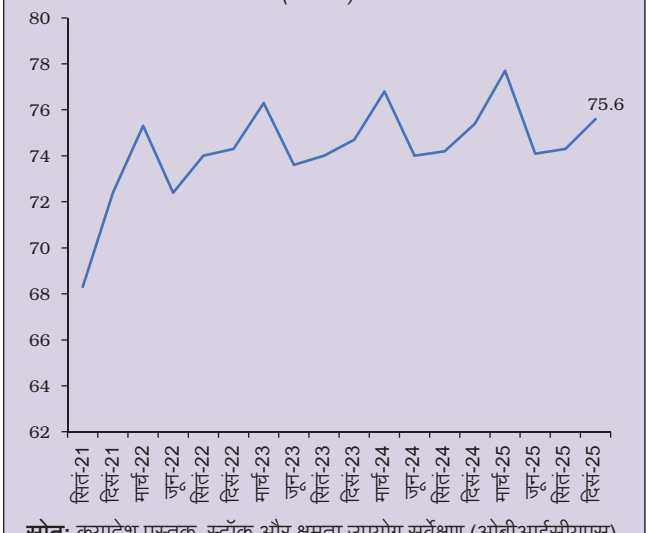

स्रोत: क्रयादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस), आरबीआई।

में सुधार का संकेत देते हैं। 2025-26 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षमता उपयोग बढ़कर 75.6 प्रतिशत हो गया, ऐसा विस्तार लगातार दूसरी तिमाही हुआ, जो नए ऑर्डर में अनुक्रमिक वृद्धि और स्थिर इन्वेंट्री स्तरों द्वारा समर्थित रहा (चार्ट II.2.9)।

II.2.18 2025-26 में निजी क्षेत्र की निवल अचल आस्ति वृद्धि में सुधार हुआ, और 2025-26 की पहली छमाही में यह बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गई; इस वृद्धि में दूरसंचार, धातु, निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों का मुख्य योगदान रहा। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया, इस योजना ने ₹2.2 लाख करोड़ से अधिक के वास्तविक निवेश को आकर्षित किया, जिससे दिसंबर 2025 के अंत तक ₹20.4 लाख करोड़ से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन/बिक्री हुई और 14.4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए[21]।

सेवा क्षेत्र

II.2.19 सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2025-26 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण व्यापार, परिवहन एवं होटल और रेस्तरां; तथा वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाओं में व्यापक आधार पर विस्तार था। सेवा क्षेत्र के उच्च आवृत्ति संकेतकों ने 2025-26 में मिश्रित तस्वीर दर्शाई। 2025-26 की दूसरी छमाही में, जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद, वाणिज्यिक वाहन बिक्री और वाहन पंजीकरण में वृद्धि हुई। 2024-25 की दूसरी छमाही की तुलना में खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री (यात्री वाहन, ट्रैक्टर, दोपहिया और तिपहिया वाहन), घरेलू हवाई कार्गो, पोर्ट कार्गो, रेलवे माल यातायात, विदेशी पर्यटकों का आगमन और जीएसटी ई-वे बिल-अंतर्राज्यीय जैसे अन्य संकेतक भी बेहतर हुए। जहाँ एक ओर हवाई यात्री यातायात और टोल संग्रहण (मूल्य) में कमी आई, वहीं इसी अवधि के दौरान होटल अधिभोग संकेतक में संकुचन देखने को मिला (सारणी II.2.5)।

II.2.20 भारत के निर्माण क्षेत्र में 2025-26 में मिश्रित रुझान देखने को मिले; 2024-25 की तुलना में इस्पात (स्टील) की खपत में कमी आई, जबकि सीमेंट उत्पादन में सुधार हुआ (सारणी II.2.5)। 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान, जीएसटी के कारण लागत में हुई कमी के चलते आवास

[21] 'पीएलआई योजना ₹1.9 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 14 रणनीतिक क्षेत्रों में उद्योग की मजबूत भागीदारी को बढ़ावा देती है', पीआईबी, 20 फरवरी 2026।

सारणी II.2.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: संवृद्धि दर

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

संकेतक	2024-25				2025-26			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
घरेलू हवाई यात्री यातायात	5.6	7.3	11.4	12.0	5.3	-1.9	1.7	0.6
परिवहन								
वाणिज्यिक वाहन बिक्री	3.7	-10.6	1.3	1.8	-0.6	8.4	21.8	19.0
वाहन कुल पंजीकरण	10.1	3.1	11.7	0.7	5.2	2.0	19.9	23.4
टोल संग्रहण-मात्रा	5.6	7.6	9.8	15.1	16.2	10.7	2.6	-4.9
टोल संग्रहण-मूल्य	9.5	10.3	12.7	17.2	19.7	17.5	12.2	6.7
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	14.2	10.3	10.0	8.6	7.0	6.8	7.6	-2.5
घरेलू हवाई कार्गो	7.1	7.7	4.6	3.5	6.6	4.9	6.8	12.5
अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो	18.4	21.8	15.0	1.5	4.7	3.6	7.3	5.7
रेलवे माल यातायात: फ्रेट उत्पत्ति*	5.1	-0.4	1.5	0.1	2.4	4.0	3.2	2.9
पोर्ट कार्गो	3.9	6.2	-1.6	7.9	5.6	5.9	13.0	4.3
घरेलू व्यापार								
जीएसटी ई-वे बिल	16.0	16.8	16.9	19.4	20.5	23.1	19.4	15.7
जीएसटी ई-वे बिल अंतर्राज्यीय	17.5	17.0	13.8	19.5	20.9	25.9	23.7	19.3
जीएसटी ई-वे बिल अंतर-राज्यीय	13.2	16.5	23.0	19.1	19.7	18.0	11.5	9.2
जीएसटी राजस्व	10.2	9.2	8.7	10.7	12.4	8.4	4.8	7.7
निर्माण								
इस्पात (स्टील) की खपत	15.3	12.1	8.1	11.6	7.9	8.8	4.6	10.4
सीमेंट उत्पादन	0.5	3.2	8.7	12.4	8.1	7.3	11.2	8.2
पर्यटन और आतिथ्य								
होटल अधिभोग दर	-2.4	2.1	1.8	1.2	1.4	-2.0	0.8	-3.6
विदेशी पर्यटकों का आगमन*	5.5	1.6	-0.3	-10.0	-18.3	-10.8	-1.4	5.2
पीएमआई								
सेवाएं पीएमआई	60.5	59.6	58.7	58.0	59.3	61.4	58.9	58.0
सेवाओं का भविष्य परिदृश्य	63.2	62.2	63.8	62.2	59.4	60.1	57.1	62.8
संयुक्त पीएमआई	61.0	59.9	59.0	58.7	60.0	61.8	59.3	58.1
संयुक्त भविष्य परिदृश्य	63.8	62.3	63.6	63.1	60.6	60.4	57.6	62.0

संकुचन ← → विस्तार

पीएमआई: क्रय प्रबंधक सूचकांक।

***:** 2025-26 की चतुर्थ तिमाही के लिए आँकड़े जनवरी 2026 तक हैं।

टिप्पणी: सभी पीएमआई मान सूचकांक प्रपत्र में रिपोर्ट किए गए हैं (>50: विस्तार; <50: संकुचन; और = 50: कोई परिवर्तन नहीं)।

स्रोत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए); सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम); भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम; वाहन पंजीकरण पोर्टल; रेल मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय बंदरगाह संघ; वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन); संयुक्त संयंत्र समिति, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार; एचवीएस एनालॉक, और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और एसएंडपी ग्लोबल।

परियोजनाओं के शुभारंभ (लॉन्च) में तेजी आई, जबकि पिछली तिमाही में मामूली वृद्धि दर्ज करने के बाद बिक्री में गिरावट देखने को मिली। बिक्री समायोजित प्रलंबित अतिरिक्त स्टॉक (इन्वेंट्री ओवरहैंग)[22], जो हाल की तिमाहियों में स्थिर होने के

[22] वर्तमान इन्वेंट्री को बेचने में महीनों में समय लगेगा।

बाद 2025-26 की तीसरी तिमाही में बढ़ गया, हालाँकि, यह कोविड-19 से पहले के दो वर्षों के 32 महीनों के औसत स्तर से नीचे ही रहा (चार्ट II.2.10)।

II.2.21 सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)[23], जो निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में गतिविधि की निगरानी करता है तथा सेवा क्षेत्र में जीवीए वृद्धि के एक संयोग संकेतक के रूप में कार्य करता है [लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) को छोड़कर], पिछली तीन तिमाहियों में अनुक्रमिक सुधार दर्शाने के बाद मार्च 2026 में मंद हो गया। एसएससीआई में यह कमी 2025-26 की चतुर्थ तिमाही में व्यापार और परिवहन संकेतकों में कमजोर वृद्धि से प्रेरित रही (चार्ट II.2.11)।

रोजगार

II.2.22 वर्ष 2025 में रोजगार स्थितियाँ स्थिर रहीं। जनवरी-दिसंबर 2025 के लिए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), और बेरोजगारी दर (यूआर) में मामूली गिरावट देखी गई (चार्ट II.2.12ए)[24]। ग्रामीण क्षेत्रों में एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में कमी आई, जबकि शहरी एलएफपीआर अपरिवर्तित रहा और डब्ल्यूपीआर में वृद्धि हुई (चार्ट II.2.12बी)। कुल रोजगार में नियमित मजदूरी/वेतनभोगी और दिहाड़ी श्रम की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, जबकि स्व-नियोजित लोगों की हिस्सेदारी में गिरावट आई (चार्ट II.2.12सी)।

II.2.23 हाल ही में लागू किए गए श्रम सुधारों से श्रम बाजार में लचीलापन बढ़ने और अनुपालन का बोझ कम होने की उम्मीद है, साथ ही ये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, सांविधिक न्यूनतम वेतन और स्वास्थ्य और सुरक्षा के बेहतर प्रावधान भी सुनिश्चित करेंगे; जिससे औपचारिक रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण और उद्यम विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

चार्ट II.2.10: रिहायशी आवास क्षेत्र

(माह, बायाँ मान; व-द-व, प्रतिशत, दायां मान)

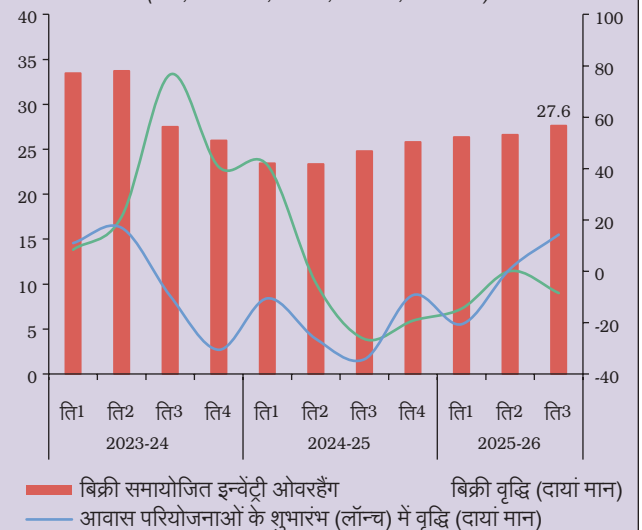

स्रोत: Housing.com.

चार्ट II.2.11: सेवा क्षेत्र में संवृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) और एसएससीआई

(प्रतिशत, व-द-व, बायाँ मान; एसएससीआई, दायां मान)

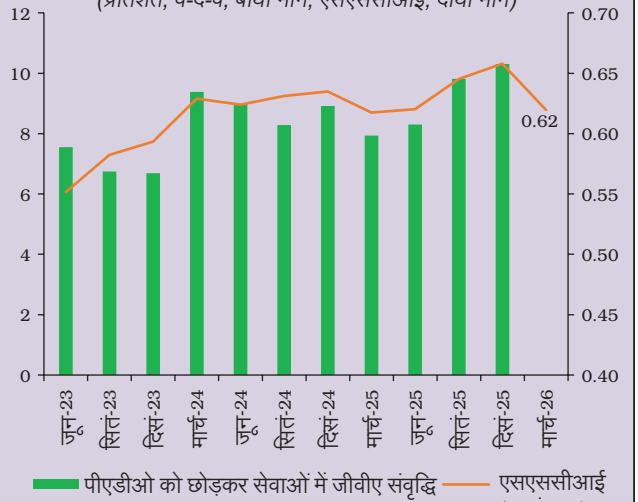

स्रोत: एनएसओ एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[23] एसएससीआई का सृजन सेवा क्षेत्र के तीन प्रमुख उप-क्षेत्रों, यथा निर्माण; व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं; और वित्तीय, स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाओं - में प्रमुख संकेतकों से उच्च-आवृत्ति डेटा को प्राप्त कर और संयोजित करके किया जाता है। इन संकेतकों को अंतिम सूचकांक उत्पन्न करने के लिए एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके संयोजित किया जाता है।

[24] सभी पीएलएफएस संकेतक सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) में हैं तथा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए हैं।

चार्ट II.2.12: श्रम बाजार संकेतक – पीएलएफएस

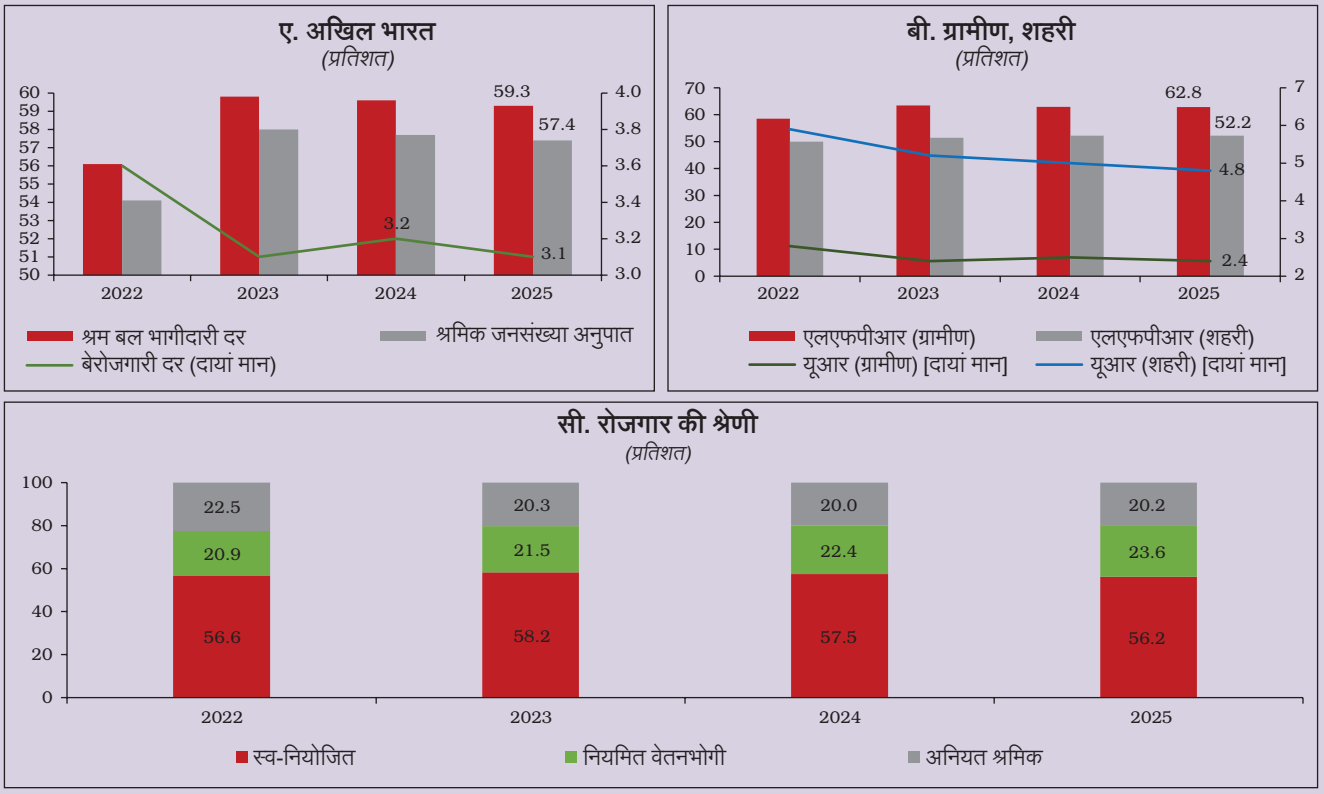

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

निष्कर्ष

II.2.24 भारत की आर्थिक गतिविधियों ने 2025-26 में उल्लेखनीय सुदृढ़ता प्रदर्शित की, जो निजी उपभोग में स्थिर गति, निश्चित निवेश में वृद्धि, विनिर्माण गतिविधि के मजबूत निष्पादन और सेवाओं में उत्साहजनक प्रदर्शन से प्रेरित रही। इसके अतिरिक्त, हाल ही में संपन्न हुए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के साथ-साथ कई अन्य व्यापार समझौतों पर चल रही चर्चाओं से मध्यम अवधि में निर्यात का बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, मौसम से संबंधित आकस्मिकताओं के कारण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में नरमी के साथ-साथ लगातार बने भू-राजनीतिक तनाव, अनिश्चित व्यापार माहौल और वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के कारण संवृद्धि परिदृश्य के समक्ष गिरावट संबंधी जोखिम बने हुए हैं।

II.3 कीमतों की स्थिति

II.3.1 2025-26 के दौरान मुद्रास्फीति की गतिशीलता में एक लंबे समय तक नरमी बनी रही, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक स्पष्ट बदलाव था। 2025-26 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई, इसमें खाद्य पदार्थों की कीमतों में अपस्फीति और मजबूत अनुकूल आधार प्रभाव का योगदान रहा (चार्ट II.3.1)[25]। सितंबर 2025 में जीएसटी दरों

[25] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने जनवरी 2025 से सीपीआई आधार 2024=100 श्रृंखला जारी की है, जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए लिंकिंग फैक्टर 0.53 है। हालांकि, कार्यप्रणाली, नमूना आकार और संग्रहण तकनीकों में बदलाव के कारण, यह नई श्रृंखला, पुरानी श्रृंखला के साथ पूरी तरह से तुलनीय नहीं है। इसलिए, इस खंड में दिसंबर 2025 तक सीपीआई मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा आधार 2012=100 के साथ सीपीआई श्रृंखला से संबंधित है, और उसके बाद के महीनों के लिए यह आधार 2024=100 पर आधारित है।

चार्ट II.3.1: हेडलाइन मुद्रास्फीति के रुझान

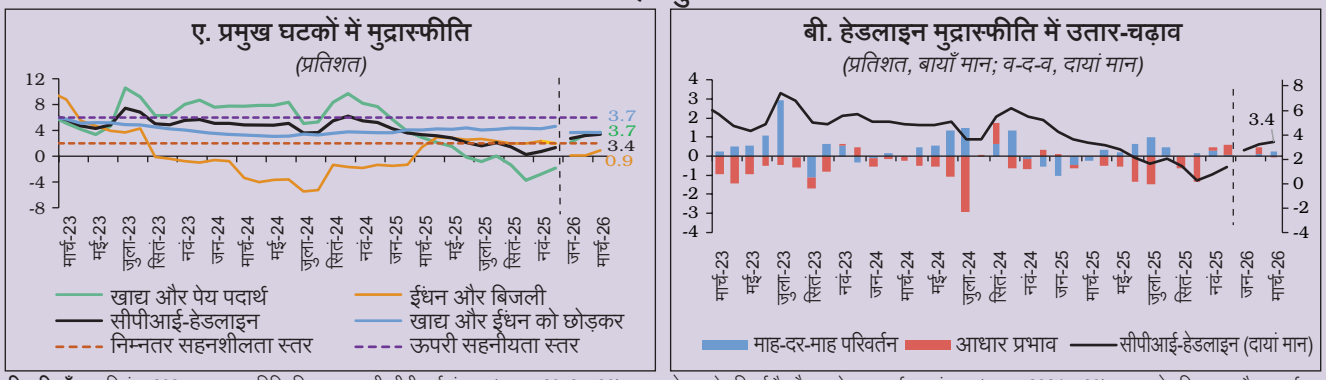

टिप्पणियाँ: 1. दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई श्रृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान श्रृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई श्रृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

2. सीपीआई 2024=100 (2012=100) में, सीपीआई-संयुक्त में श्रेणी-वार भार इस प्रकार हैं: खाद्य और पेय पदार्थ: 36.8 (45.9), ईंधन और बिजली: 10.2 (6.8), खाद्य और ईंधन को छोड़कर: 53.0 (47.3)।

3. वर्तमान श्रृंखला (2024=100) में ईंधन और बिजली दो श्रेणियों को दर्शाते हैं, यथा 'बिजली, गैस और अन्य ईंधन'; और 'व्यक्तिगत परिवहन साधन के लिए ईंधन और स्नेहक' जिनमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं। विवरण के लिए, अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में बॉक्स संख्या IV.2 देखें।

स्रोत: एनएसओ एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

के युक्तिकरण और सरलीकरण ने भी कई वस्तुओं और सेवाओं पर मूल्य दबाव को सीमित करने में मदद की। दूसरी ओर मूल मुद्रास्फीति, यानी खाद्य और ईंधन को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को मूल्यवान धातुओं से उत्पन्न होने वाले ऊर्ध्वगामी दबावों का सामना करना पड़ा। हालांकि, वर्ष के अंत में, जैसे ही पश्चिमी एशिया में संघर्ष छिड़ गया, घरेलू तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलपीजी) की कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन और बिजली घटक में मुद्रास्फीति बढ़ गई।

II.3.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार (जीओआई) ने 12 फरवरी 2026 को आधार वर्ष 2024=100 के साथ एक नई सीपीआई श्रृंखला जारी की। संशोधित संरचना संयुक्त राष्ट्र के 'क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविडुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पज (सीओआईसीओपी)' 2018 का अनुसरण करती है, जिसमें घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 से भार प्राप्त किए गए हैं। नई संरचना के तहत, सीपीआई आधार वर्ष 2012 = 100 के अनुसार पहले के छह समूहों को अब 12 वर्गों में पुनर्गठित किया गया है। विशेष रूप से, नई श्रृंखला में 'खाद्य और पेय पदार्थों' का भार 45.9 प्रतिशत से घटकर 36.8 प्रतिशत हो गया, यह उपभोक्ताओं के उपभोग के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें वे अब अधिक गैर-खाद्य वस्तुओं की ओर बढ़ रहे हैं; साथ ही, यह तैयार खाद्य घटक का पुनर्वर्गीकरण 'रेस्तरां और आवास सेवाओं' वर्ग में करने को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 'आवास' और 'ईंधन और बिजली' समूहों को 'आवास, जल, बिजली, गैस और अन्य ईंधनों के वर्ग' में रखा गया है, जबकि 'परिवहन और संचार' समूह को 'परिवहन' और 'सूचना और संचार' वर्गों में विभाजित किया गया है (सारणी II.3.1)।

II.3.3 जहाँ औसत मुद्रास्फीति में तेजी से कमी आई, वहीं मानक विचलन द्वारा मापी गई अस्थिरता में 2025-26 में मामूली वृद्धि हुई क्योंकि इस दौरान मुद्रास्फीति 0.3 से 3.4 प्रतिशत के बीच रही (सारणी II.3.2)। मुद्रास्फीति के वर्ष-वार वितरण में थोड़ी ऋणात्मक विषमता (नेगेटिव स्क्यूनेस) देखने को मिली, जो यह संकेत देती है कि कम मुद्रास्फीति वाले परिणामों की ओर इसका विस्तार थोड़ा अधिक था।

सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

खाद्य पदार्थ

II.3.4 खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर 2025) में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2025-26 की चतुर्थ तिमाही

सारणी II.3.1: सीपीआई भार संरचना में परिवर्तन

क्र.सं.	वर्ग	सीपीआई 2024 = 100	क्र.सं.	समूह	सीपीआई 2012 = 100
1	खाद्य और पेय पदार्थ	36.8	1	खाद्य और पेय पदार्थ	45.9
2	पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	3.0	2	पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	2.4
3	कपड़े और जूते	6.4	3	कपड़े और जूते	6.5
4	आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन	17.7	4	आवास	10.1
5	फर्नीचर, घरेलू उपकरण और नियमित घरेलू रखरखाव	4.5	5	ईंधन और बिजली	6.8
6	शिक्षा सेवाएँ	3.3	6	विविध	28.3
7	स्वास्थ्य	6.1		*जिनमें से:*	
8	सूचना और संचार	3.6	6.1	घरेलू सामान और सेवाएँ	3.8
9	परिवहन	8.8	6.2	स्वास्थ्य	5.9
10	मनोरंजन, खेल और संस्कृति	1.5	6.3	परिवहन और संचार	8.6
11	व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा एवं विविध वस्तुएँ और सेवाएँ	5.0	6.4	मनोरंजन और मन-बहलाव	1.7
12	रेस्तरां और आवास सेवाएँ	3.3	6.5	शिक्षा	4.5
			6.6	व्यक्तिगत देखभाल और उससे जुड़ी वस्तुएँ	3.9
	कुल	**100**		**कुल**	**100**

टिप्पणी: प्रत्येक सीपीआई श्रृंखला उस वर्गीकरण का अनुसरण करती है जिसके साथ इसे प्रकाशित किया गया था, और समान श्रेणियों में भार संरचना पूरी तरह से से तुलनीय नहीं है।
स्रोत: एनएसओ; एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

में, खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति औसतन 3.1 प्रतिशत (सीपीआई 2024=100) पर अधिक थी। अक्टूबर 2025 में, सीपीआई खाद्य और पेय पदार्थों की श्रेणी में सीपीआई श्रृंखला में सबसे तेज अपस्फीति दर्ज की गई, जो दिसंबर में 1.8 प्रतिशत तक पहुंचने से पहले 3.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी। अक्टूबर 2024 में 9.7 प्रतिशत के उच्च स्तर से मुद्रास्फीति में हुई निरंतर गिरावट का मुख्य कारण सब्जियों, दालों और अनाजों की कीमतों में दबाव का कम होना और एक मजबूत अनुकूल आधार प्रभाव था (चार्ट II.3.2)। आपूर्ति पक्ष के अनुकूल कारकों, अर्थात् उच्च घरेलू और थोक बाज़ार में स्थिर आवक के कारण खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार, सहायक व्यापार नीतियाँ, सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन और बड़े

सारणी II.3.2: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
माध्य	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	5.5	6.7	5.4	4.6	2.1
मानक विचलन	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	0.9	0.7	0.9	0.9	1.0
स्क्यूनेस	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7	-0.1	-0.1	1.5	0.0	-0.3
कर्टोसिस	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7	-1.0	-0.6	1.6	-1.2	-1.0
माध्यिका	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5	5.6	6.7	5.1	4.8	2.1
अधिकतम	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6	7.0	7.8	7.4	6.2	3.4
न्यूनतम	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1	4.2	5.7	4.3	3.3	0.3

टिप्पणी: 1. स्क्यूनेस और कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दरों का औसत है और इसलिए, यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से गणना की गयी वार्षिक मुद्रास्फीति से भिन्न हो सकती है।
2. दिसंबर 2025 तक, मासिक मुद्रास्फीति दरें पुरानी सीपीआई श्रृंखला (आधार 2012=100) से संबंधित हैं, उसके बाद से वर्तमान श्रृंखला (आधार 2024=100) से संबंधित हैं।
स्रोत: एनएसओ; एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.2: हाल की अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी

(प्रतिशत अंकों में योगदान)

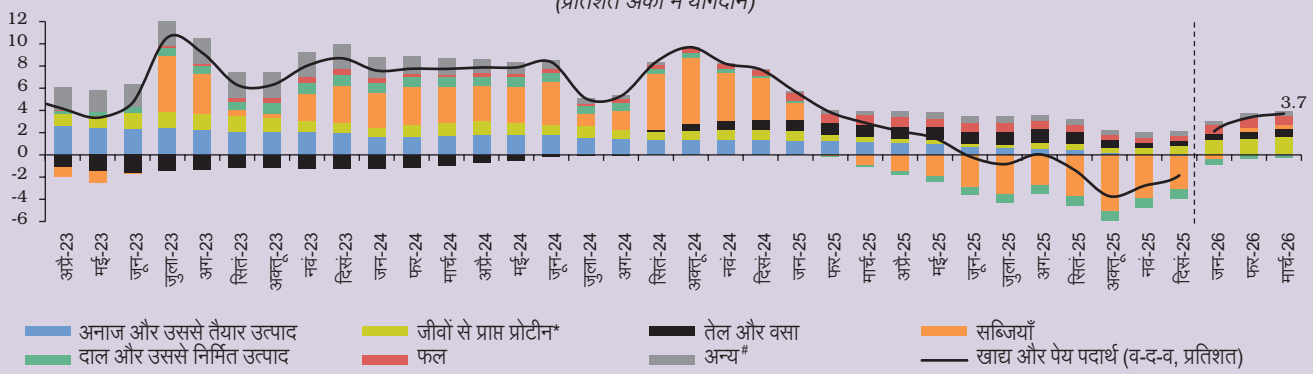

*: इसमें अंडे, दूध और उससे तैयार उत्पाद एवं मांस और मछली शामिल हैं।

#: चीनी, मिठान्न, मिठाई (डेसर्ट); तैयार भोजन और अन्य खाद्य उत्पाद; पेय पदार्थ; और खाद्य के लिए प्राथमिक वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए सेवाएं शामिल हैं।

टिप्पणी: दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई श्रृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान श्रृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई श्रृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

स्रोत: एनएसओ; एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पैमाने पर अनुकूल मौसम की स्थितियों ने भी खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में योगदान दिया।

II.3.5 मौसमी और ऐतिहासिक रुझानों के विपरीत, सब्ज़ियों की कीमतों में सर्दियों के दौरान नरमी की विस्तारित अवधि के बाद, गर्मियों में होने वाली बढ़ोतरी असामान्य रूप से निम्न और विलंबित रही। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान सब्जियों की कीमतों में 19.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट दर्ज की गई, इसके बाद 2025-26 की चतुर्थ तिमाही में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली (चार्ट II.3.3ए)।

II.3.6 टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की कीमतों में पूरे वर्ष नरमी बनी रही। गर्मियों में कीमतों की कम वृद्धि के बाद सितंबर-अक्टूबर 2025 में तीव्र गिरावट हुई क्योंकि उत्पादन और बाजार उपलब्धता मजबूत बनी रही। इस श्रेणी में, 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान 31.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही के दौरान 12 प्रतिशत की मूल्य गिरावट दर्ज की गई थी, जो विशेष रूप से प्याज द्वारा संचालित रही; इसके मुख्य कारण थे: 2024-25 में अधिक उत्पादन (2023-24 की तुलना में 26.7 प्रतिशत अधिक) के कारण बाज़ार में लगातार आवक, निर्यात में कमी, और आपूर्ति-पक्ष के उपाय—जिनमें सरकार के बफर स्टॉक से लक्षित खुदरा बिक्री शामिल है (चार्ट 11.3.3बी)। टीओपी को छोड़कर अन्य सब्जियों की कीमतों में भी अप्रैल-दिसंबर 2025 (वर्ष-दर-वर्ष) में 11.4 प्रतिशत

चार्ट II.3.3: सीपीआई में मौसमी प्रभाव - सब्जी की कीमतें

ए. सीपीआई-सब्जियां - संचयी गति

(प्रतिशत)

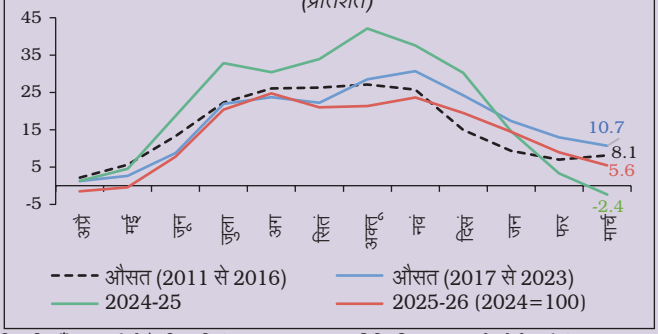

बी. सब्जी संबंधी मुद्रास्फीति के चालक

(प्रतिशत अंकों में योगदान)

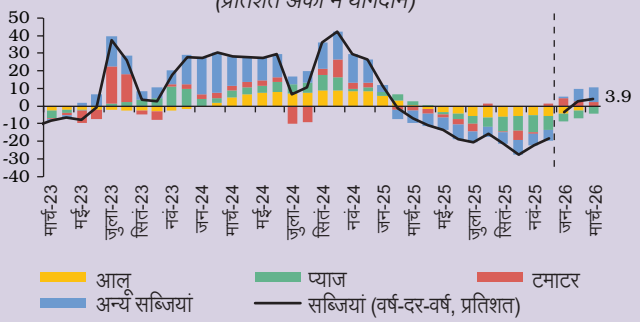

टिप्पणियाँ: 1. चार्ट बी के लिए, दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई श्रृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान श्रृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई श्रृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

2. सीपीआई 2024=100 (2012=100) में, सीपीआई-सब्जियों में श्रेणी-वार भार इस प्रकार हैं: आलू: 14.8 (16.3), प्याज: 13.8 (10.7), टमाटर: 9.7 (9.5), और अन्य सब्जियां: 61.6 (63.5)।

स्रोत: एनएसओ, एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

का संकुचन दर्ज किया गया, इसके बाद 2025-26 की चतुर्थ तिमाही में 8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) अधिक कीमतें दर्ज की गईं, जिनका मुख्य कारण प्रतिकूल आधार प्रभाव थे।

II.3.7 दालें, जो वनस्पति-आधारित प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं, उनमें पहली तीन तिमाहियों के दौरान 13 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष कीमतों में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; इसके बाद 2025-26 की चतुर्थ तिमाही में 7.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। अक्टूबर 2025 तक लगातार 17 महीनों तक दालों की महंगाई में क्रमिक रूप से नरमी आई। इसके प्रमुख कारण थे: 2024-25 में मजबूत उत्पादन (2023-24 की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक) से बढ़ी हुई उपलब्धता, प्रमुख दालों (पीली मटर, अरहर और उड़द) का बड़े पैमाने पर आयात, स्टॉक प्रकटीकरण अनिवार्यताएँ, और केंद्र सरकार द्वारा 'भारत दाल' की खुदरा बिक्री[26] (चार्ट II.3.4)।

II.3.8 अनाज ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2.4 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष में यह 7.6 प्रतिशत थी, जो चावल, गेहूँ एवं अन्य अनाजों और उनसे तैयार उत्पादों की कीमतों में बड़े पैमाने पर गिरावट से प्रेरित थी। 2025-26 की चतुर्थ तिमाही में, गेहूँ की कीमतों में आई गिरावट के कारण अनाज की कीमतें 0.2 प्रतिशत कम हो गईं (चार्ट II.3.5)। दिसंबर 2025 में, 50 महीनों के बाद गेहूँ में अपस्फीति दर्ज की गई, जिसका कारण रिकॉर्ड उत्पादन (2024-25 में 4.1 प्रतिशत अधिक), पर्याप्त बफर स्टॉक (16 मार्च 2026 तक निर्धारित मानक से 1.7 गुना अधिक) और फरवरी 2026 तक जारी निर्यात प्रतिबंध थे। रिकॉर्ड चावल उत्पादन (2024-25 में 9 प्रतिशत अधिक) और उच्च बफर स्टॉक (16 मार्च 2026 तक निर्धारित मानक से 9.7 गुना अधिक) ने चावल की कीमतों में मुद्रास्फीति को कम रखा।

II.3.9 प्रमुख खाद्य पदार्थों द्वारा संचालित वर्ष के दौरान समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के विपरीत, 'फल' और 'तेल और वसा' की कीमतों में ऊर्ध्वगामी दबाव देखे गए। 2024-25 में उच्च तापमान और बेमौसम बारिश के कारण नारियल उत्पादन में 5 प्रतिशत की गिरावट के कारण नारियल की कीमतें बढ़ गईं। इसके चलते अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान फलों की औसत मुद्रास्फीति 10.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही के दौरान 7.9 प्रतिशत रही। तेल और वसा संबंधी मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 तक लगातार 12 महीनों तक दहाई अंकों में बनी रही तथा 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) में कीमतों में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यह वृद्धि एक वर्ष पहले इसी अवधि में 1.9 प्रतिशत थी; इसके बाद 2025-26 की चतुर्थ

चार्ट II.3.4: सीपीआई-दालें - अरहर चालित अपस्फीति

(प्रतिशत अंकों में योगदान)

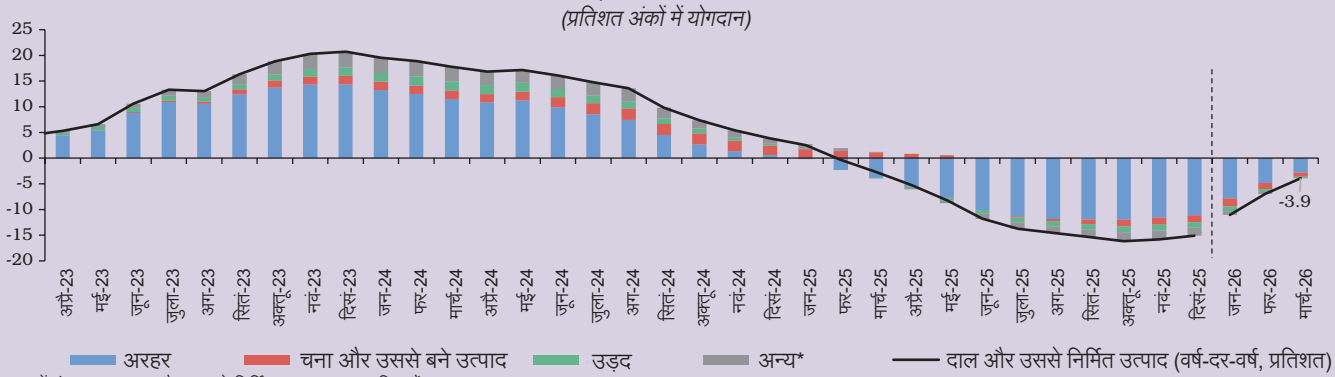

*: इसमें मूंग, मसूर, मटर और दाल से निर्मित अन्य उत्पाद शामिल हैं।

टिप्पणियाँ: 1. दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई श्रृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान श्रृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई श्रृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

2. सीपीआई 2024=100 (2012=100) में, सीपीआई-दालों और उनसे बने उत्पादों में अलग-अलग श्रेणी-वार भार इस प्रकार हैं: अरहर: 32.4 (33.4), चना और उससे बने उत्पाद: 19.9 (13.3), उड़द: 11.2 (11.5), और अन्य: 36.4 (41.8)।

स्रोत: एनएसओ; एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[26] अप्रैल 2024 में, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निदेश दिया कि वे पाँच प्रमुख दालों – अरहर (तूर), उड़द, चना, मसूर और मूँग तथा आयातित पीली मटर के लिए, स्टॉक रखने वाली सभी संस्थाओं द्वारा साप्ताहिक स्टॉक की जानकारी देने और उसके सत्यापन को अनिवार्य रूप से लागू करें।

चार्ट II.3.5: सीपीआई-अनाज की महंगाई कम रही

(प्रतिशत अंकों में योगदान)

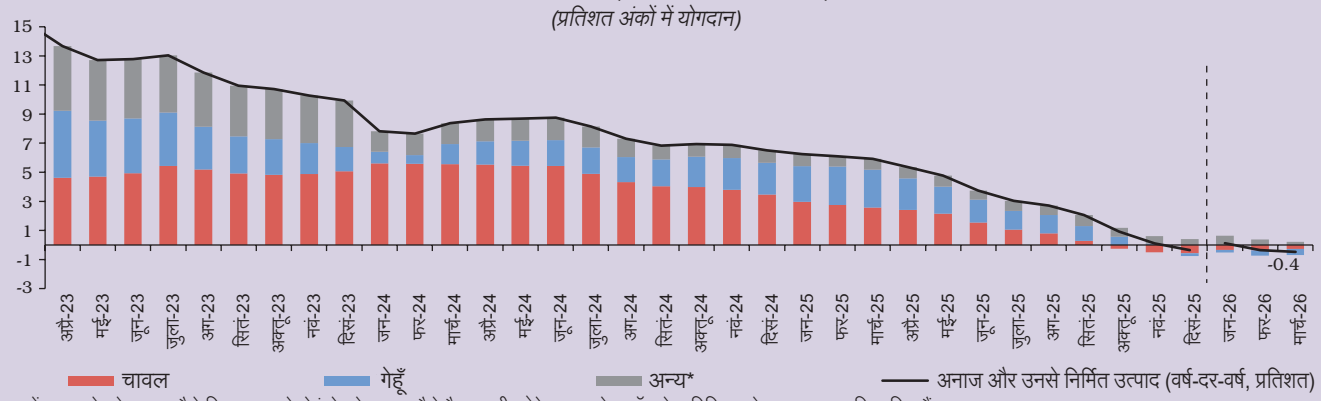

*: इसमें चावल से बने उत्पाद जैसे चिउड़ा, मुरमुरे; गेहूं से बने उत्पाद जैसे मैदा, सूजी; मोटे अनाज, ब्रेड, चॉकलेट, बिस्किट, केक, नूडल्स आदि शामिल हैं।

टिप्पणियाँ: 1. दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई श्रृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान श्रृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई श्रृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

2. सीपीआई 2024=100 (2012=100) में, सीपीआई-अनाज और उनसे बने उत्पादों के श्रेणी-वार भार इस प्रकार हैं: चावल: 34.2 (49.1), गेहूं: 12.9 (28.3), और अन्य: 52.9 (22.6)।

स्रोत: एनएसओ; एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तिमाही में कीमतों में 7.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा प्रमुख उत्पादक देशों में अंतरराष्ट्रीय बायो-डीज़ल अनिवार्यताओं में वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय पाम तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, 2024-25 में घरेलू उत्पादन में कमी के कारण सरसों के तेल में कीमतों का दबाव बढ़ गया, जिसने अगस्त 2025 में 41 महीने की उच्च मुद्रास्फीति 24.2 प्रतिशत पर दर्ज की। सरसों और रेपसीड के उच्च रबी उत्पादन (2025-26 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार) के बावजूद, 2025-26 के खरीफ मौसम के दौरान सोयाबीन के उत्पादन में कमी के चलते कुछ ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। घी और मक्खन जैसे वसा की कीमतें पूरे वर्ष काफी सीमा तक स्थिर रहीं और खुदरा कीमतों पर जीएसटी दरों में कमी के कारण अक्टूबर 2025 में गिरावट दर्ज की गई।

II.3.10 अन्य खाद्य वस्तुओं में, मसालों की कीमतें दिसंबर 2025 तक लगातार 18 महीनों तक अपस्फीति (कीमतों में गिरावट) में रहीं, जो मुख्य रूप से जीरा और सूखी मिर्च द्वारा संचालित थीं। 2025-26 में जीव आधारित प्रोटीन में मुद्रास्फीति कम रही क्योंकि मवेशियों और मुर्गी पालन के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल रही, हालांकि जनवरी-मार्च 2026 के दौरान मांस और मछली की कीमतों में वृद्धि हुई।

ईंधन

II.3.11 अप्रैल 2025 में प्रति एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹50 की वृद्धि के कारण, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान ईंधन मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान के 3.2 प्रतिशत की अपस्फीति से बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई। इसके परिणामस्वरूप, हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन समूह का योगदान अप्रैल-दिसंबर 2025 में बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले (-) 4.3 प्रतिशत था (चार्ट II.3.6)। मार्च 2026 में, ईंधन मुद्रास्फीति बढ़कर 0.9 प्रतिशत हो गई, जबकि जनवरी और फरवरी, दोनों में यह 0.1 प्रतिशत थी; इसका कारण मार्च 2026 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹60 की बढ़ोतरी थी।

मूल मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति)[27]

II.3.12 मूल मुद्रास्फीति एक सीमित दायरे में बनी रही और अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान इसका औसत 4.3 प्रतिशत रहा; जबकि एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में यह 3.4 प्रतिशत थी (परिशिष्ट सारणी 4)। संशोधित श्रृंखला (2024=100) के तहत, जनवरी से मार्च 2026 के दौरान मूल मुद्रास्फीति मोटे तौर पर 3.7 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही। मूल मुद्रास्फीति में दृढ़ता मुख्य

[27] सीपीआई 2012 = 100 श्रृंखला में, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई का अनुमान 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और बिजली' समूहों को छोड़कर लगाया गया था। सीपीआई 2024=100 श्रृंखला में, 'ईंधन और बिजली' दो श्रेणियों को दर्शाता है, यथा 'बिजली, गैस और अन्य ईंधन'; और 'व्यक्तिगत परिवहन साधनों के लिए ईंधन और स्नेहक', जिसमें 'पेट्रोल', 'डीजल' और 'अन्य प्राकृतिक गैस (सीएनजी)' शामिल हैं।

चार्ट II.3.6: एलपीजी चालित ईंधन मुद्रास्फीति

(प्रतिशत अंकों में योगदान)

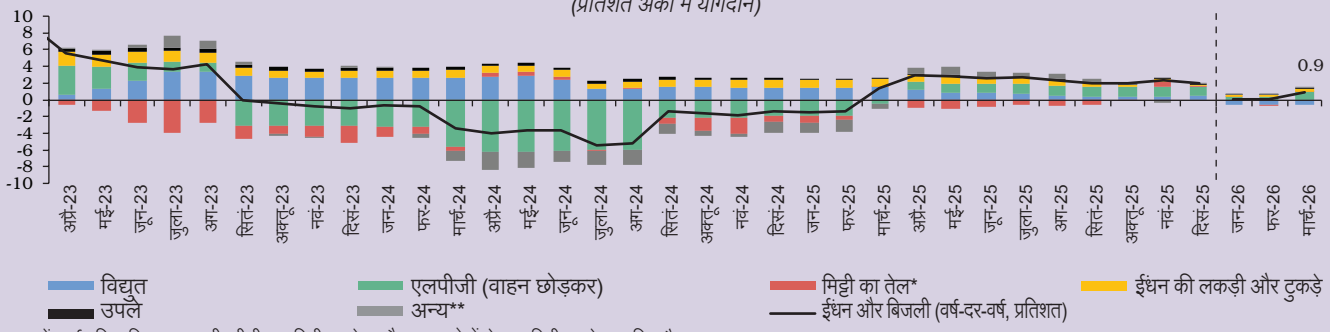

*: इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल और अन्य स्रोतों से प्राप्त मिट्टी का तेल शामिल है।

**: इसमें दिसंबर 2025 तक पुरानी सीपीआई शृंखला (आधार 2012=100) पर डीज़ल (परिवहन को छोड़कर), कोयला, चारकोल और कोक शामिल हैं; जबकि जनवरी-मार्च 2026 के लिए संशोधित (आधार 2024=100) पर इसमें कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, बायोगैस और गोबर गैस शामिल हैं।

टिप्पणियाँ: 1. दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई शृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान शृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई शृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों शृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

2. सीपीआई 2024=100 (2012=100) में, सीपीआई-ईंधन के अंतर्गत श्रेणी-वार भार इस प्रकार हैं: विद्युत: 43.4 (33.0), एलपीजी: 37.0 (18.8), मिट्टी का तेल: 0.2 (8.0), ईंधन की लकड़ी और टुकड़े: 16.3 (30.2), गोबर के उपले: 2.7 (6.5), और अन्य: 0.4 (3.5)।

स्रोत: एनएसओ, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

रूप से स्वर्ण और चांदी की मूल्यवान धातुओं सहित 'व्यक्तिगत देखभाल और उससे जुड़ी वस्तुओं' में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से प्रेरित थी, इसी श्रेणी का 2025-26 की दूसरी छमाही में मूल मुद्रास्फीति में लगभग आधा योगदान था (चार्ट II.3.7)।

II.3.13 व्यक्तिगत देखभाल और उससे जुड़ी वस्तुओं में मुद्रास्फीति बढ़ने का मुख्य कारण मूल्यवान धातुओं - स्वर्ण और चांदी की कीमतों में वृद्धि थी। यह तेजी भू-राजनीतिक अनिश्चितता और बदलती वैश्विक मौद्रिक नीति की दिशा और अपेक्षाओं के बीच, वैश्विक 'सेफ-हेवन' (सुरक्षित निवेश) की बढ़ी हुई मांग को दर्शाती है। स्वर्ण और चांदी को छोड़कर, 2025-26 की दूसरी छमाही में मूल मुद्रास्फीति में कमी आई। इसका कारण जीएसटी के युक्तिकरण के उपाय थे, जिनसे कीमतों में सुधार हुआ - विशेषकर मोटर वाहनों और उनसे जुड़े पुर्जों के मामले में (चार्ट II.3.8)। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान, कपड़े और जूते-चप्पलों में मुद्रास्फीति दर घटकर 2.2 प्रतिशत रह गई, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 2.7 प्रतिशत थी। यह गिरावट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की कम कीमतों तथा वस्त्रों और परिधानों के लिए निर्यात की सुस्त मांग को दर्शाती है। 2025-26 के दौरान घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, स्वास्थ्य

चार्ट II.3.7: व्यक्तिगत देखभाल चालित खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई

(प्रतिशत अंकों में योगदान)

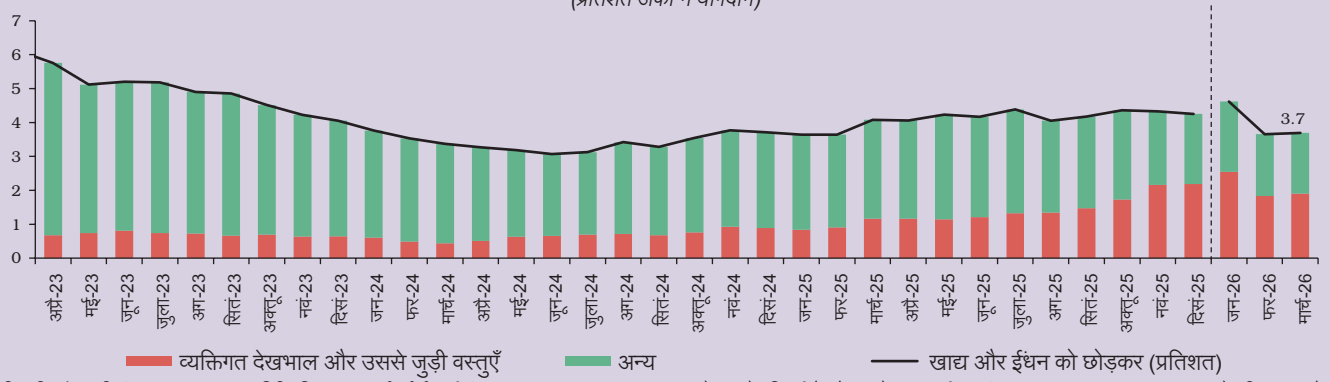

टिप्पणियाँ: 1. दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई शृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान शृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई शृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों शृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

2. सीपीआई 2012=100 शृंखला में 'व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव' समूह का नाम परिवर्तित कर सीपीआई 2024=100 शृंखला में "व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा एवं विविध वस्तुएँ और सेवाएं" प्रभाग कर दिया गया है।

स्रोत: एनएसओ; एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.3.8: स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई मूल (कोर) मुद्रास्फीति में नरमी बनी रही

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

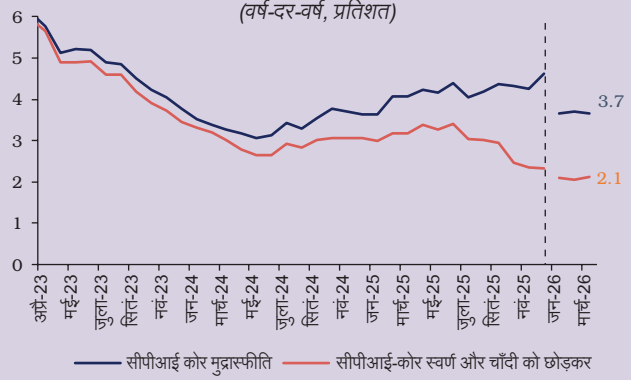

टिप्पणियाँ: 1. दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई श्रृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान श्रृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई श्रृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

2. सीपीआई 2024=100 (2012=100) में, श्रेणी-वार भार इस प्रकार हैं: सीपीआई कोर: 53.0 (47.3), और सीपीआई-कोर (स्वर्ण और चाँदी को छोड़कर): 52.1 (46.11)।

स्रोत: एमओएसपीआई; एवं आरबीआई स्टाफ अनुमान।

और शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर मोटे तौर पर स्थिर बनी रही।

मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.3.14 एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य से, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति 2025-26 के दौरान घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 3.4 प्रतिशत थी; इसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति में आई कमी थी। सीपीआई-कृषि श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक (एएल/आरएल) श्रृंखला के आधार को जुलाई 2025 में संशोधित किया गया, जिसे 1986-87 से परिवर्तित कर 2019=100 कर दिया गया। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2011-12) पर आधारित संशोधित सीपीआई समूह में खाद्य और गैर-मादक पेय-पदार्थ समूह के भार में उल्लेखनीय कमी तथा विविध समूह में भारी वृद्धि दिखाई देती है, जो ग्रामीण परिवारों के उपभोग स्वरूप में आए बदलावों का संकेत है[28]।

II.3.15 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति 2025-26 के दौरान घटकर 0.7 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 2.3 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण प्राथमिक वस्तुओं एवं ईंधन और बिजली की कीमतों में आई गिरावट (अपस्फीति) थी। डब्ल्यूपीआई प्राथमिक वस्तुओं (22.6 प्रतिशत का भारांक) ने 2025-26 के दौरान 1.1 प्रतिशत की अपस्फीति का अनुभव किया; यह मुद्रास्फीति दर एक वर्ष पहले 5.2 प्रतिशत थी, जो अनुकूल आपूर्ति और मौसम की स्थितियों से प्रेरित थी। इसके अलावा, ईंधन और बिजली की अपस्फीति 2025-26 के दौरान 2.9 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो एक वर्ष पहले 1.3 प्रतिशत थी। यह वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई नरमी को दर्शाता है। विनिर्मित उत्पादों (जिनका भार 64.2 प्रतिशत है) में मुद्रास्फीति 2025-26 के दौरान बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 1.7 प्रतिशत थी। इसमें रसायन, गढ़े हुए धातु, कागज और खाद्य उत्पादों के विनिर्माण क्षेत्र की मुख्य भूमिका रही। मुद्रास्फीति में समग्र गिरावट को दर्शाते हुए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) डिफ्लेटर-आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान घटकर 0.9 प्रतिशत रह गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2.5 प्रतिशत थी[29]। यद्यपि अतीत में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच विचलन के दौर देखे गए हैं, लेकिन हाल की अवधि में ये दोनों सूचकांक एक साथ आगे बढ़े हैं (चार्ट II.3.9)।

चार्ट II.3.9: सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में रुझान

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

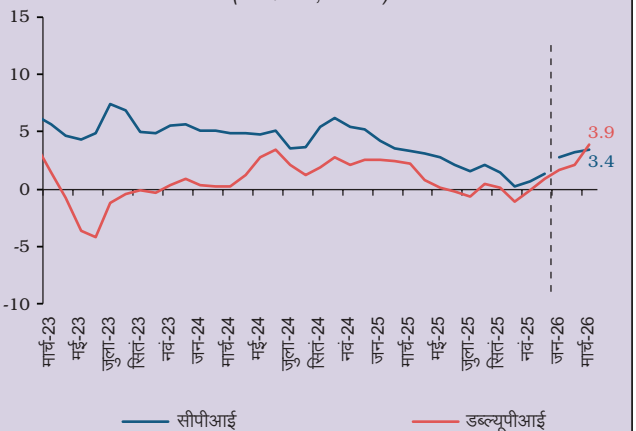

टिप्पणी: दिसंबर 2025 तक सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना पुरानी सीपीआई श्रृंखला (आधार 2012=100) का उपयोग करके की गई है और उसके बाद, वर्तमान श्रृंखला (आधार 2024=100) का उपयोग किया गया है। ऊर्ध्वाधर डैश वाली रेखा पुरानी और वर्तमान सीपीआई श्रृंखलाओं के बीच के अंतराल को दर्शाती है, क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में मुद्रास्फीति आँकड़ों की तुलना ठीक से नहीं की जा सकती है।

स्रोत: एमओएसपीआई; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय।

[28] सीपीआई-एएल श्रृंखला में खाद्य और गैर-मादक पेय पदार्थ समूह का भार 69.2 प्रतिशत से घटकर 57.9 प्रतिशत हो गया। सीपीआई-आरएल श्रृंखला में उनका भारांक सीपीआई-आरएल श्रृंखला में 66.8 प्रतिशत से घटाकर 56.6 प्रतिशत कर दिया गया था। नए आधार 2019=100 में, मई 2025 से मार्च 2026 तक सीपीआई-एएल और आरएल श्रृंखला की औसत मुद्रास्फीति क्रमशः 1.0 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत रही।

[29] जीडीपी डिफ्लेटर-आधारित मुद्रास्फीति अनुमान, जीडीपी डेटा 2022-23 श्रृंखला पर आधारित हैं।

II.3.16 2025-26 में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 1.0-13.9 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 4.0-10.1 प्रतिशत की सीमा में वृद्धि की गई। खरीफ फसलों में रागी में सर्वाधिक एमएसपी वृद्धि देखी गई, जबकि रबी फसलों में कुसुम (सैफ्लावर) में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

निष्कर्ष

II.3.17 2025-26 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी बनी रही, जिसके मुख्य कारण मजबूत खाद्यान्न उत्पादन, वैश्विक पण्य वस्तुओं की कीमतों (विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा) में नरमी और सरकार द्वारा किए गए आपूर्ति प्रबंधन उपाय थे। वित्तीय वर्ष के अंत में, पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के कारण कुछ मूल्य दबाव उभरने लगे। भविष्य में, लंबे समय तक चलने वाले भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न अनिश्चितताओं, बढ़ती ऊर्जा कीमतों, इनपुट लागतों, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, बदलती व्यापार नीतियों और मौसम की स्थितियों - विशेष रूप से अल नीनो की संभावना और सामान्य से कम मानसून - के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के लिए निरंतर सतर्कता और बदलती परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।

II.4 मुद्रा एवं ऋण[30]

II.4.1 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का विस्तार हुआ, जिसका मुख्य कारण रुपए के अवमूल्यन और स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि से उत्पन्न पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व थे। प्रचलन में मौजूद मुद्रा (सीआईसी) में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई, जिसने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)[31] में बदलावों के प्रथम-चरण के प्रभाव को समायोजित करने के बाद, आरक्षित मुद्रा (रिज़र्व मुद्रा) में उच्च वृद्धि में योगदान दिया। वर्ष की पहली छमाही में बैंक ऋण में वृद्धि धीमी रही, जिसका कारण वाणिज्यिक क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए गैर-बैंकिंग माध्यमों पर बढ़ती निर्भरता थी। जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ा, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वृद्धि ने काफी गति पकड़ी, और अंततः जमा वृद्धि को पीछे छोड़ते हुए ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि का कारण बनी।

आरक्षित मुद्रा

II.4.2 आरक्षित मुद्रा, केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र में मौद्रिक देयताओं के स्टॉक को दर्शाता है (चार्ट II.4.1)। जोखिम बफर और पुनर्मूल्यांकन खाते [जो निवल गैर-मौद्रिक देयताओं (एनएनएमएल) का बड़ा हिस्सा निर्मित करते हैं], साथ ही बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो/स्थायी जमाराशि सुविधा (एसडीएफ़) के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखी गई अतिरिक्त चलनिधि, तुलनपत्र के अन्य प्रमुख घटक हैं। मार्च 2026 के अंत तक, रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र का आकार जीडीपी[32] का 25.9 प्रतिशत था (एक वर्ष पहले यह 23.7 प्रतिशत था)।

चार्ट II.4.1: रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के घटक (देयताएं) [मार्च अंत तक]

(तुलन पत्र के आकार का प्रतिशत, बायां मान, सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत, दायां मान)

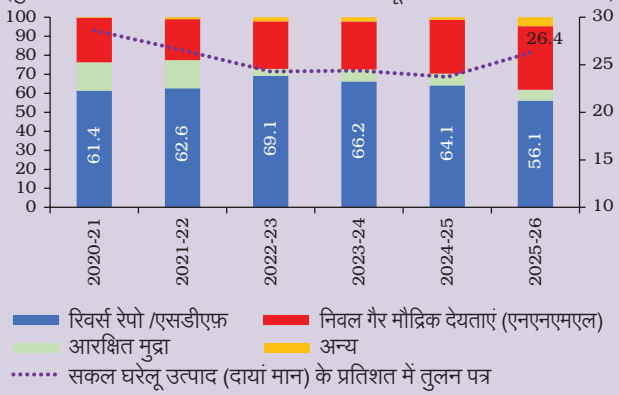

एनएनएमएल: इसमें पूंजी, रिज़र्व, आकस्मिक निधि, आस्ति विकास निधि , मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि खाता और आईएमएफ़ कोटा अंशदान तथा अन्य भुगतान से अन्य आस्तियों को घटाकर शामिल किया गया है।

स्रोत: आरबीआई।

[30] 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी, बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत, 'पिछली रिपोर्टिंग पखवाड़े' की परिभाषा को बदलकर 'महीने का आखिरी दिन' कर दिया गया है। तदनुसार, इस अनुभाग में, दिसंबर 2025 से आगे की संवृद्धि और अन्य अनुपात चालू वर्ष के लिए 'माह के अंत' के आंकड़ों पर आधारित हैं, जबकि पिछले वर्ष के इसी माह के आंकड़े 'पिछले शुक्रवार' या 'पिछली रिपोर्टिंग पखवाड़े' (पुरानी परिभाषा के अनुसार) जैसा भी मामला हो, से संबंधित हैं।

[31] वर्ष के दौरान, सीआरआर को चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंकों (बीपीएस) से घटाकर 'निवल मांग और मीयादी देयताओं' (एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत कर दिया गया। यह कटौती 25 बीपीएस की चार बराबर किस्तों में की गई, जो 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी हुई।

[32] 2022-23 से आगे के जीडीपी आंकड़े नई श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) पर आधारित हैं।

II.4.3 सीआरआर में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करने के बाद, रिज़र्व मुद्रा[33] की संवृद्धि एक साल पहले के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 10.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.4.2 और परिशिष्ट सारणी 4)। सीआईसी - जो रिज़र्व मुद्रा का मुख्य हिस्सा है और जिसकी हिस्सेदारी 81.4 प्रतिशत है - 2025-26 के दौरान 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि एक साल पहले यह 5.8 प्रतिशत था। इसकी मुख्य वजह कई राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों (जैसे, फसल खराब होने पर मुआवज़ा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के कारण नकद निकासी में बढ़ोतरी, हाल ही में जीएसटी और आयकर दरों में कटौती के बाद खपत-आधारित नकद निकासी में बढ़ोतरी, और साथ ही ब्याज दरों में नरमी तथा कीमती धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच नकद की मांग में वृद्धि थी। रिज़र्व बैंक के पास बैंकरों की जमाराशियों (रिज़र्व मुद्रा में 15.8 प्रतिशत हिस्सा) – अर्थात, बैंकों द्वारा अपनी सीआरआर ज़रूरतों और निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए रखी गई अधिशेष राशि में इस वर्ष के दौरान 18.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जो सीआरआर में 100 बीपीएस की कटौती को दर्शाता है।

II.4.4 डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ मुद्रा-जीडीपी अनुपात में आंशिक वृद्धि हुई। 2025-26 के दौरान, खुदरा डिजिटल भुगतानों में मूल्य के हिसाब से 15.1 प्रतिशत और मात्रा के हिसाब से 26.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.4.3)।

II.4.5 स्रोतों (आस्तियों) की तरफ, रिज़र्व मुद्रा में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए)[34] और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफ़ए)[35] शामिल होती हैं। 2025-26 के दौरान, एनएफ़ए में ₹8.2 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण एफ़सीए और स्वर्ण , दोनों में हुई वृद्धि थी। हालाँकि अधिकृत डीलरों को हुई निवल बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी, फिर भी पुनर्मूल्यांकन लाभों के कारण एफ़सीए में बढ़ोत्तरी हुई। एनएफ़ए में स्वर्ण की हिस्सेदारी, एक साल पहले के 12.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2026 के

चार्ट II.4.2: आरएम-घटक (देयताएं)

(संवृद्धि, प्रतिशत)

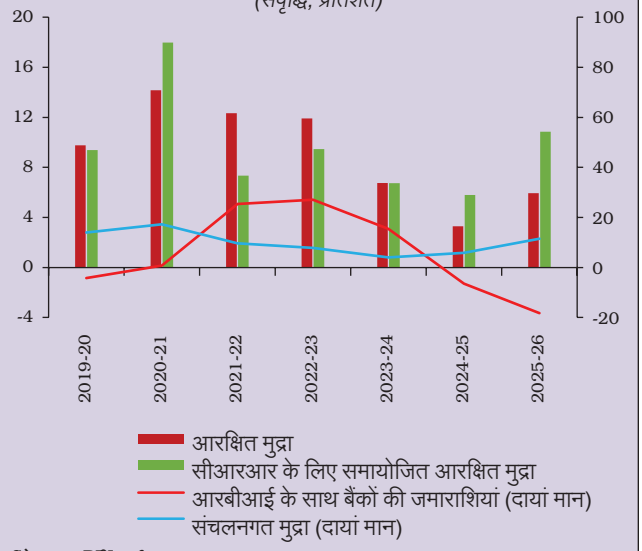

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट II.4.3: संचलनगत मुद्रा और डिजिटल भुगतान

(वॉल्यूम हज़ार करोड़ में, बायां मान; प्रतिशत, दायां मान)

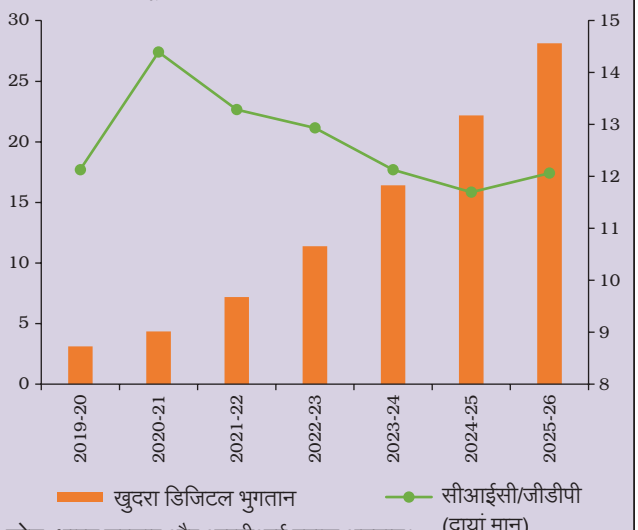

स्रोत: भारत सरकार और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[33] देयताओं में प्रचलन में मुद्रा, रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियां और रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमाराशियां शामिल हैं।

[34] इसमें बैंकों, सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्य रूप से प्राथमिक डीलर) को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण शामिल है।

[35] इसमें स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए) शामिल हैं। एफ़सीए में भारत सरकार (भारत सरकार) से हस्तांतरित 'विशेष आहरण अधिकार' (एसडीआर) शामिल हैं। भारत सरकार के पास शेष एसडीआर धारिताएँ और आईएमएफ़ में 'रिज़र्व ट्रेंच स्थिति' (आरटीपी)—जो आईएमएफ़ में भारत के विदेशी मुद्रा कोटे के योगदान का प्रतिनिधित्व करती है, रिज़र्व बैंक के तुलन -पत्र का हिस्सा नहीं हैं।

अंत तक 17.2 प्रतिशत हो गई; इसका मुख्य कारण स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि से प्राप्त पुनर्मूल्यांकन लाभ थे। वर्ष के दौरान, सरकार को रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण में वृद्धि हुई, जिसका कारण खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से सरकारी -प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा चलनिधि का प्रवाह था [चार्ट II.4.4]।

मुद्रा आपूर्ति

II.4.6 मुद्रा आपूर्ति - व्यापक मुद्रा ($एम_3$) के संदर्भ में - मुख्य रूप से जनता के पास मौजूद मुद्रा (सीडबल्यूपी) और बैंकों की कुल जमा (एडी) से मिलकर निर्मित होती है (देयता)। 31 मार्च 2026 तक $एम_3$ में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 9.4 प्रतिशत थी (चार्ट II.4.5)। घटकों के लिहाज़ से, $एम_3$ का विस्तार मुख्य रूप से एडी (कुल जमा) के कारण हुआ, जो इसका सबसे बड़ा घटक है (86.6 प्रतिशत हिस्सा); ब्याज दरों में काफी कमी के बावजूद, सावधि जमा (सावधि जमाराशियां) में लगातार वृद्धि (एक वर्ष पहले के 9.8 प्रतिशत की तुलना में 10.6 प्रतिशत) देखने को मिली। मांग जमा में उतार-चढ़ाव बना रहा, जो काफी हद तक जनता के पास मौजूद मुद्रा में होने वाले बदलावों को दर्शाता है; 2025-26

चार्ट II.4.5: मुद्रा आपूर्ति (एम3) घटक - संवृद्धि

(प्रतिशत)

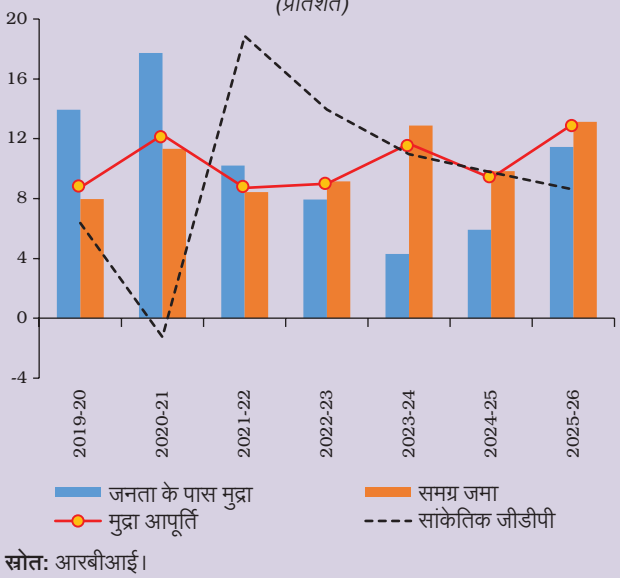

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट II.4.4: आरक्षित मुद्रा - स्रोत (आस्तियां)

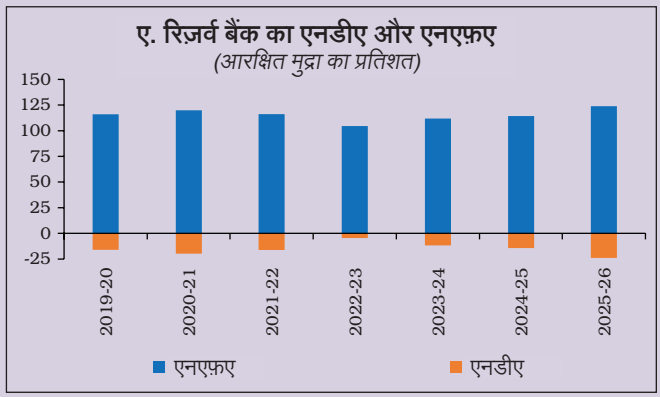

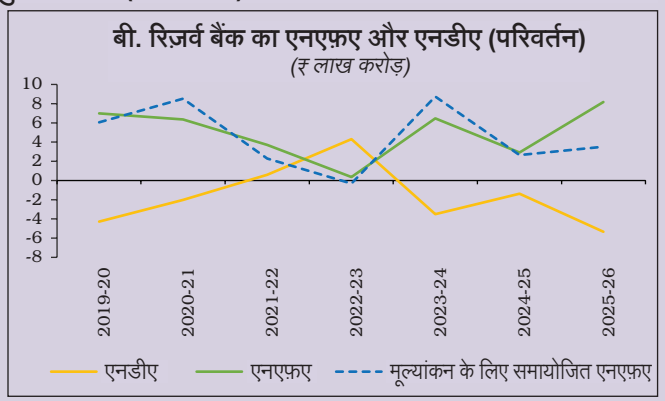

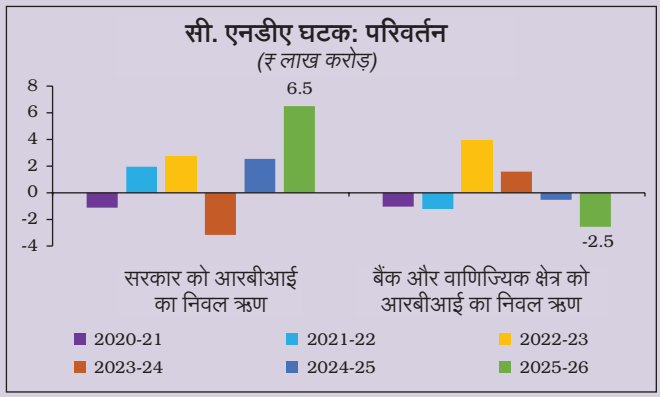

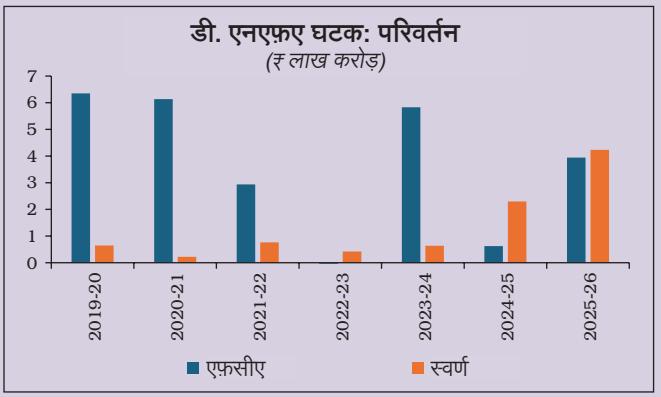

स्रोत: आरबीआई।

में इस मुद्रा में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 5.9 प्रतिशत थी।

II.4.7 स्रोतों (आस्तियों) की तरफ, एम$_3$ में विस्तार मुख्य रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण (एम$_3$ का सबसे बड़ा घटक) के कारण हुआ, जो पिछले वर्ष के 10.8 प्रतिशत की तुलना में 2025-26 में 15.7 प्रतिशत बढ़ा (चार्ट II.4.6)। सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण में 2025-26 में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले यह 10.5 प्रतिशत थी), जिसका कारण रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी -प्रतिभूतियों की खरीद थी। तदनुसार, एससीबी की सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों[36] की अतिरिक्त धारिता 31 मार्च 2026 को निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 8.2 प्रतिशत तक कम हो गई (एक वर्ष पहले यह 10.3 प्रतिशत थीं)। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियों में वृद्धि हुई, जो इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र में एनएफ़ए के विस्तार को दर्शाती है।

चार्ट II.4.6: मुद्रा आपूर्ति स्रोत-संवृद्धि

(प्रतिशत)

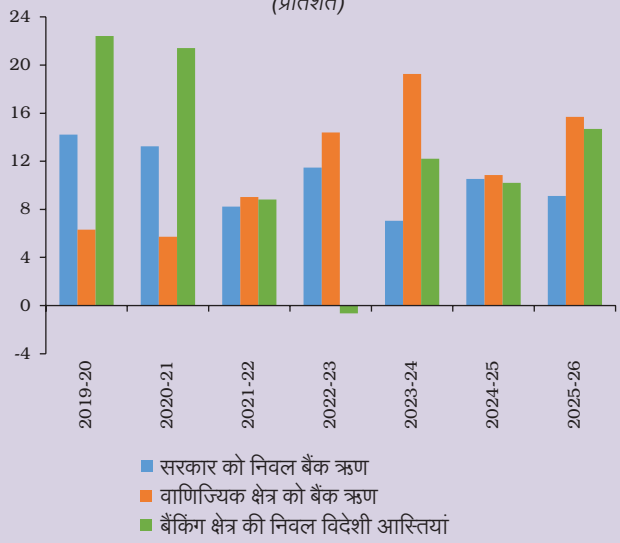

स्रोत: आरबीआई।

मुख्य मौद्रिक अनुपात

II.4.8 मुद्रा के लेन-देन की स्थिति, यानी सांकेतिक जीडीपी और एम$_3$ का अनुपात, 2025-26 के दौरान स्थिर रहा। मुद्रा-जमाराशि अनुपात 21 मार्च, 2025 के 15.4 प्रतिशत से और कम होकर 31 मार्च, 2026 को 14.9 प्रतिशत हो गया; यह, अन्य बातों के अलावा, यह दिखाता है कि लोगों की पसंद डिजिटल भुगतान के तरीकों की ओर ज़्यादा उन्मुख हो रही है। सीआरआर में कमी के कारण इस साल आरक्षित-जमाराशि अनुपात में गिरावट आई (चार्ट II.4.7ए)। मुद्रा-जमाराशि

चार्ट II.4.7 : मौद्रिक अनुपात

ए. व्यवहारगत अनुपातों में अंतर्निहित मुद्रा बहुगुणक

(प्रतिशत)

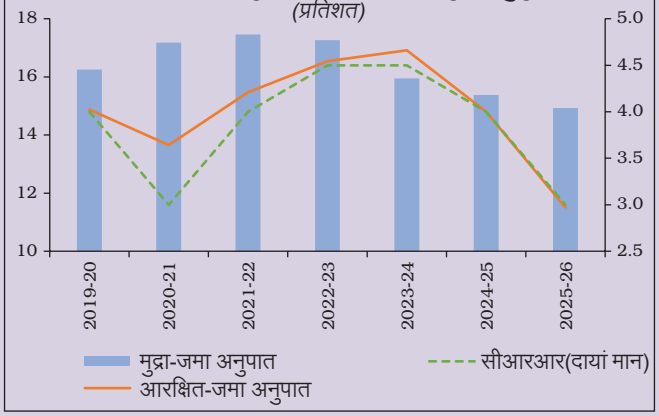

बी. मुद्रा संवेग और मुद्रा बहुगुणक

(अनुपात)

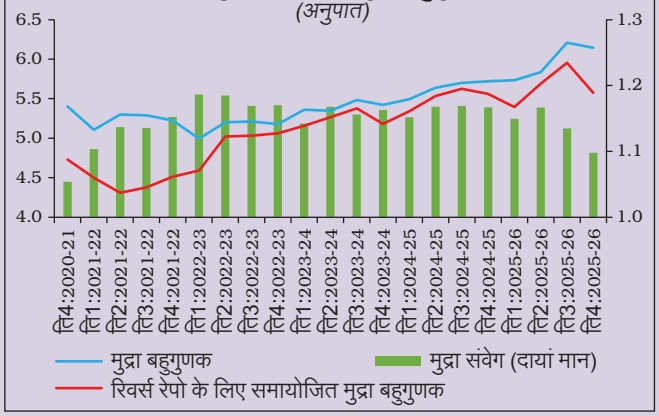

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[36] एसएलआर प्रतिभूतियों की अतिरिक्त धारिताएँ बैंकों को 'चलनिधि समायोजन सुविधा' (एलएएफ़) के तहत धनराशि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक बफर प्रदान करती हैं, और ये 'चलनिधि कवरेज अनुपात' (एलसीआर) का भी एक घटक हैं।

चार्ट II.4.8 : बैंक समूह-वार ऋण वृद्धि

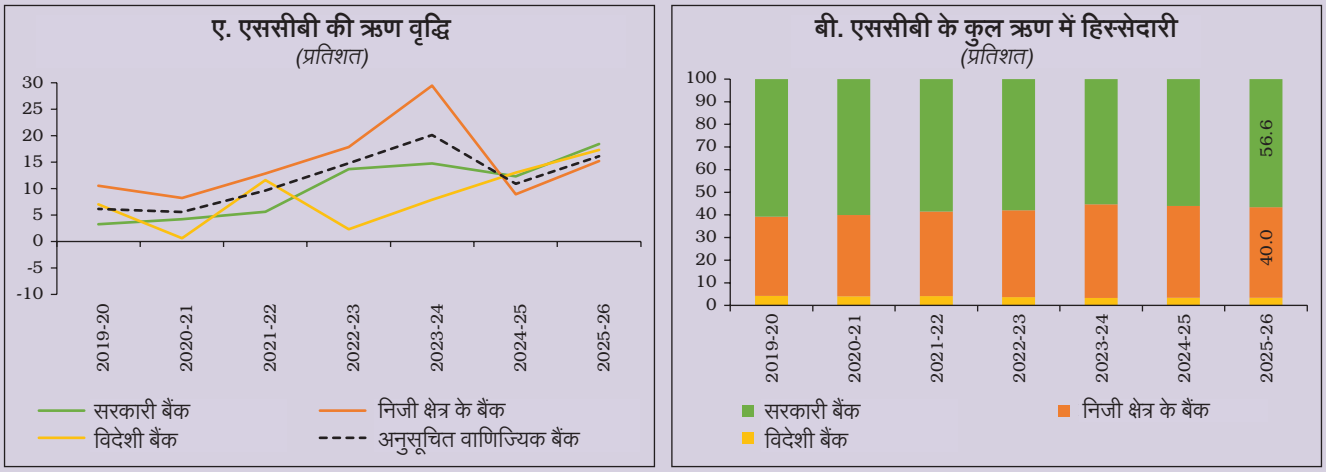

स्रोत: आरबीआई।

अनुपात और आरक्षित -जमाराशि अनुपात दोनों में आई कमी के मिले-जुले असर से मुद्रा -गुणक में सुधार हुआ; यह 21 मार्च, 2025 के 5.7 से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को 6.1 हो गया (चार्ट II.4.7बी)।

ऋण

II.4.9 वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ऋण में दोहरे अंकों की वृद्धि बनी रही, जिसमें सर्वाधिक योगदान सेवा और खुदरा क्षेत्रों ने किया (चार्ट II.4.8ए)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने लगातार दूसरे वर्ष निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में अधिक ऋण वृद्धि दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप कुल ऋण में पीएसबी की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई (चार्ट II.4.8बी)।

II.4.10 प्रमुख क्षेत्रों में ऋण संवृद्धि में तेज़ी देखी गई, और मार्च 2026 के आखिर तक कुल गैर- खाद्य ऋण[37] संवृद्धि 15.9

चार्ट II.4.9 : एससीबी की खाद्येतर ऋण वृद्धि

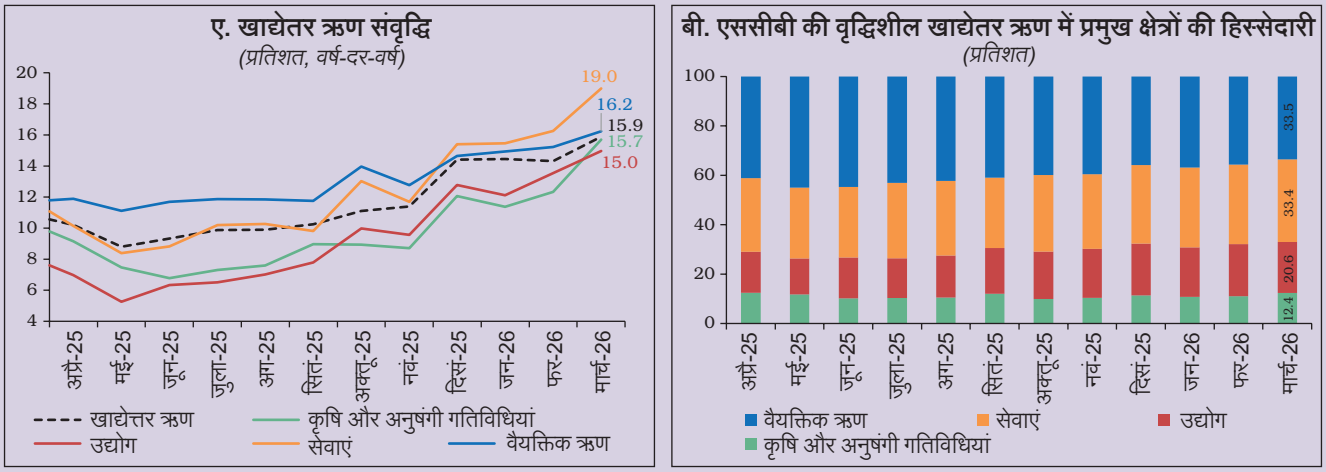

स्रोत: आरबीआई।

[37] गैर-खाद्य ऋण के आंकड़े पखवाड़ेवार 'धारा 42 विवरणी ' पर आधारित हैं और इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं। क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण के आंकड़े 'क्षेत्र-वार और उद्योग-वार बैंक ऋण' (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें 41 चुनिंदा बैंक शामिल हैं; ये बैंक सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। कृपया इस अनुभाग के फुटनोट 1 देखें।

प्रतिशत रही (चार्ट II.4.9)। मई 2025 से औद्योगिक ऋण में मज़बूत गति से बढ़ोतरी जारी रही, जिसका मुख्य कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में ऋण संवृद्धि का मज़बूत होना था। 'अवसंरचना ', 'सभी इंजीनियरिंग', 'मूल धातुएं और धातु उत्पाद, 'रसायन और रसायन उत्पाद', और 'पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और न्यूक्लियर ईंधन' जैसे औद्योगिक उप-क्षेत्रों में साल-दर-साल (वर्ष -दर -वर्ष) मज़बूत संवृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्र के ऋण में मज़बूत दोहरे अंकों की संवृद्धि बनी रही, जिसे मुख्य रूप से 'व्यापार', 'वाणिज्यिक रियल एस्टेट' में अच्छी ऋण संवृद्धि और सितंबर 2025 से एनबीएफ़सी[38] को ऋण की तेज़ बहाली से समर्थन मिला। वैयक्तिक ऋण कुल गैर- खाद्य ऋण संवृद्धि के मुख्य चालक बने रहे। आवासीय ऋण, जो वैयक्तिक ऋण का लगभग आधा हिस्सा हैं, में अच्छी संवृद्धि दर्ज की गई, और वाहन ऋण तथा स्वर्ण जैसे क्षेत्रों में भी बेहतर संवृद्धि देखने को मिली (सारणी II.4.1)।

सारणी II.4.1: क्षेत्रीय ऋण वृद्धि- एससीबी

(प्रतिशत, वर्ष दर वर्ष)

क्षेत्र	2024-25#	2025-26											
		अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्तू	नवं	दिसं	जन	फर	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
खाद्येतर ऋण	**10.9**	**10.2**	**8.8**	**9.3**	**9.9**	**9.9**	**10.2**	**11.1**	**11.4**	**14.4**	**14.4**	**14.3**	**15.9**
I. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	**10.4**	**9.2**	**7.5**	**6.8**	**7.3**	**7.6**	**9.0**	**8.9**	**8.7**	**12.1**	**11.4**	**12.3**	**15.7**
II. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और वृहत)	**8.2**	**7.0**	**5.3**	**6.3**	**6.5**	**7.0**	**7.8**	**10.0**	**9.6**	**12.8**	**12.1**	**13.5**	**15.0**
II.1. सूक्ष्म और लघु	8.9	9.2	13.7	19.2	20.9	20.8	22.0	25.9	24.6	30.4	31.2	30.4	33.1
II.2. मध्यम	18.5	18.1	16.9	13.2	15.0	13.3	14.5	17.6	15.7	20.4	22.3	21.0	21.7
II.3. वृहत	6.9	5.0	1.5	2.0	1.6	2.4	3.0	4.6	4.6	6.9	5.5	7.8	8.9
II.3.1 इंफ्रास्ट्रक्चर	2.8	0.3	-1.3	0.8	3.4	3.5	5.0	4.6	4.3	7.2	6.4	7.9	9.5
II.3.2 मूल धातु और धातु उत्पाद	12.8	14.3	10.6	11.0	9.5	8.9	9.1	13.1	11.8	14.2	13.8	15.2	19.4
II.3.3 रसायन और रसायनिक उत्पाद	7.4	6.0	4.7	6.3	5.5	6.7	8.3	12.2	11.1	14.8	15.1	19.1	14.9
II.3.4 वस्त्र	8.3	8.5	6.8	8.6	6.0	6.4	7.1	9.1	8.1	11.8	10.0	8.2	8.9
II.3.5 सभी इंजीनियरिंग	22.0	21.7	20.4	22.1	23.0	19.8	22.4	25.1	22.6	30.4	35.9	36.0	32.2
II.3.6 खाद्य प्रसंस्करण	5.1	6.5	7.8	8.1	5.2	6.1	7.7	10.2	6.5	11.7	9.6	10.2	14.0
III. सेवाएं	**12.0**	**10.1**	**8.4**	**8.8**	**10.2**	**10.3**	**9.8**	**13.0**	**11.7**	**15.4**	**15.5**	**16.3**	**19.0**
III.1. व्यापार	15.6	13.9	10.4	10.7	12.8	12.3	11.7	13.8	14.2	17.5	16.1	14.4	16.2
III.2. वाणिज्यिक रियल स्टेट	13.7	17.3	14.8	14.9	15.7	13.2	15.5	14.1	12.6	15.4	16.2	17.4	19.9
III.3. एनबीएफसी	7.4	4.5	1.0	3.1	3.0	3.7	3.9	10.9	9.5	15.1	17.8	20.9	26.3
IV. वैयक्तिक ऋण	**11.7**	**11.9**	**11.1**	**11.7**	**11.9**	**11.9**	**11.8**	**14.0**	**12.8**	**14.6**	**14.9**	**15.2**	**16.2**
IV.1. उपभोक्ता वस्तुएँ	-1.0	-1.0	-3.7	-2.8	-5.8	-5.8	-6.1	1.0	-5.9	-5.1	-4.0	-9.8	-5.3
IV.2. आवास	10.7	9.8	9.0	9.6	9.6	9.7	10.1	11.0	9.9	11.1	11.1	11.0	11.5
IV.3. क्रेडिट कार्ड बकाया	10.6	10.6	8.5	7.2	5.6	4.4	3.7	7.7	2.4	1.0	1.5	1.7	3.5
IV.4. वाहन ऋण	8.6	8.8	8.7	9.2	8.9	8.7	7.3	12.5	12.4	16.7	17.1	17.1	18.6
IV.5. स्वर्ण एवं आभूषण के बदले ऋण	121.1	138.0	132.7	140.9	136.4	130.2	125.6	128.5	125.3	126.1	128.8	127.9	123.1
IV.6. अन्य वैयक्तिक ऋण	7.5	8.5	7.2	7.1	7.6	7.6	7.4	9.9	8.9	11.5	11.6	12.1	13.0

#: मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025
टिप्पणी: डेटा अनंतिम है।
स्रोत: आरबीआई।

[38] एनबीएफ़सी को दिए गए बैंक ऋण के लिए जोखिम भार को नवंबर 2023 में अतिरिक्त 25 प्रतिशत अंकों तक बढ़ाया गया था, जिसे बाद में अप्रैल 2025 से प्रभावी करते हुए वापस पिछली स्थिति पर बहाल कर दिया गया।

चार्ट II.4.10 : एससीबी की जमाराशियां एवं ऋण

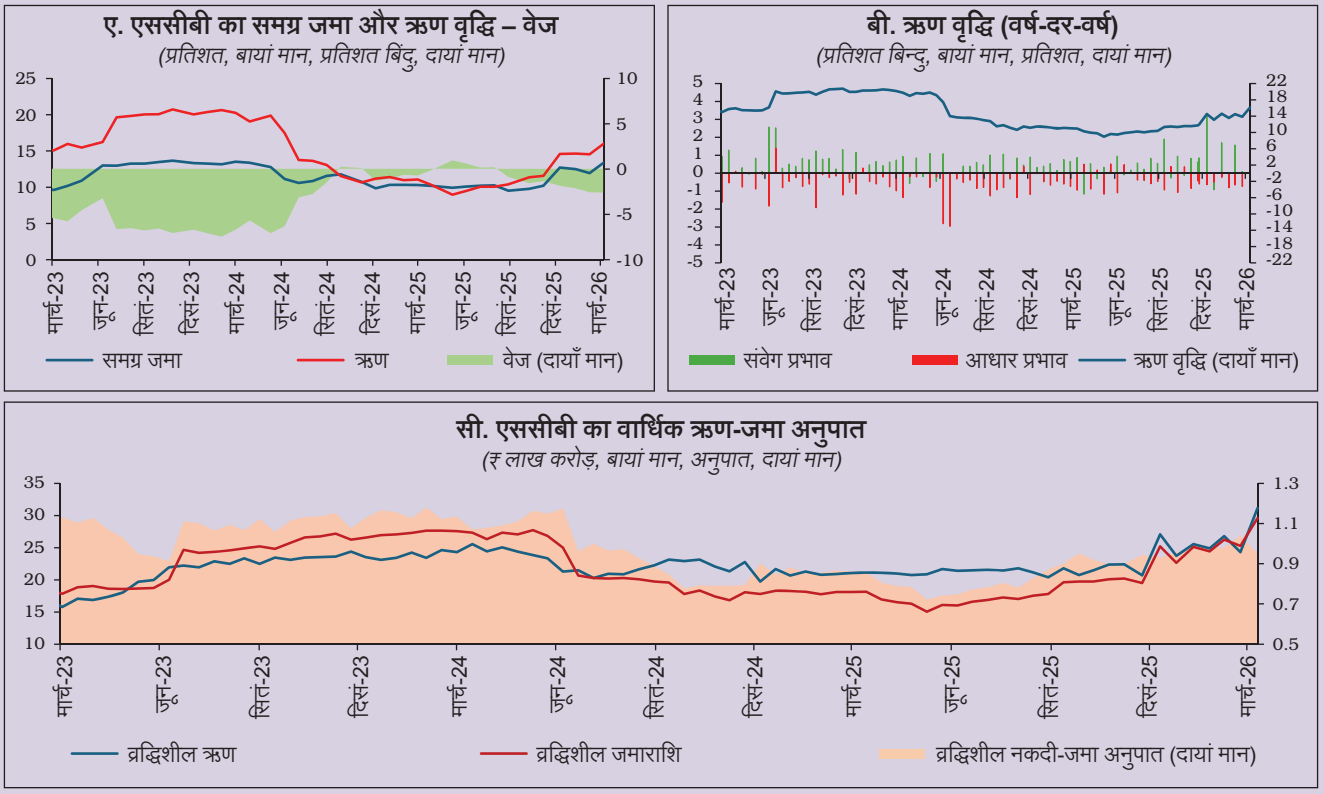

स्रोत: आरबीआई।

II.4.11 2025-26 के दौरान, एससीबी की जमा वृद्धि मुख्य तौर पर ऋण वृद्धि से कम रही। हालाँकि, हाल के महीनों में जमा वृद्धि में कुछ सुधार देखने को मिला, फिर भी जमा और ऋण वृद्धि के बीच का अंतर बना रहा (चार्ट II.4.10)। परिणामस्वरूप, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात ऊँचा बना रहा। निधीयन के अंतर को पाटने के लिए, बैंकों ने बड़ी मात्रा में जमा प्रमाणपत्र[39] जारी करने का सहारा लिया। निधीयन के लगातार बने दबाव के इस संदर्भ में, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड जैसे वैकल्पिक बचत लिखतों के बीच बदलते समीकरणों की जाँच की गई है (बॉक्स II.4.1)।

बॉक्स II.4.1

बैंक सावधि जमा और म्यूचुअल फंड प्रवाह की गतिशीलता - तुलनात्मक विश्लेषण

बैंकों में सावधि जमाराशियां और और म्यूचुअल फंड्स, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश हेतु घरेलू बचत जुटाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करते हैं। जहाँ बैंकों में सावधि जमाराशि को सुरक्षित और पूँजी-सुरक्षित लिखत माना जाता है, वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स बाज़ार-आधारित निश्चित आय प्रदान करते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अधिक बाज़ार जोखिम के साथ दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ दे सकते हैं। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि भारत में म्यूचुअल फंड्स एक प्रमुख वैकल्पिक निवेश माध्यम के रूप में उभरे हैं (गुप्ता एट अल., 2025)। उदाहरण के लिए, 2020-21 से 2024-25 के दौरान, औसतन, बकाया बैंक सावधि जमाराशि में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई,

(जारी)

[39] विवरण के लिए इस अध्याय के अनुभाग II.5 को देखें।

चार्ट 1: बैंक सावधि जमाओं और म्यूचुअल फंड निवेश में संवृद्धि

(प्रतिशत, बायां मान, ₹ लाख करोड़, दायां मान)

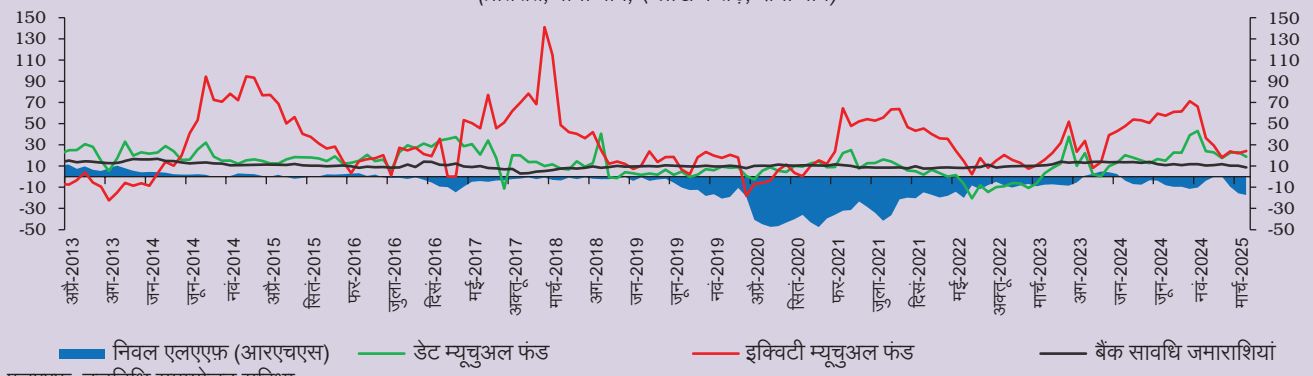

एलएएफ़: चलनिधि समायोजन सुविधा

स्रोत: आरबीआई, सेबी, सीईआईसी और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स के प्रबंधन के तहत आस्तियों (एयूएम) में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एयूएम में 32.4 प्रतिशत का विस्तार हुआ (चार्ट 1)।

इस पृष्ठभूमि में, यह सवाल उठता है कि क्या बैंक सावधि जमाराशि और म्यूचुअल फंड (डेट और इक्विटी) लिखत एक-दूसरे के पूरक (या विकल्प) के तौर पर काम करते हैं, और निवेशकों की पसंद तय करने में चलनिधि की स्थिति की क्या भूमिका होती है। इस सवाल की जाँच 2013-14 से 2024-25 की सैंपल अवधि के लिए मासिक डेटा का उपयोग करके, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन विश्लेषण [एलएम एट अल (2025) के समान] लागू करके की गई है। डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एयूएम में बढ़ोतरी को बकाया बैंक सावधि जमाराशि में बढ़ोतरी से समझाया गया है; इसमें सापेक्ष प्रतिलाभ और स्वर्ण की कीमतों में बढ़ोतरी, बीएसई सेंसेक्स प्रतिलाभ, 3-माह की ट्रेजरी प्रतिफल , इंडिया वीआईएक्स , बकाया छोटी बचत में बढ़ोतरी, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में बढ़ोतरी अंतराल को नियंत्रित किया गया है।

विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक सावधि जमाराशि और डेट म्यूचुअल फंड, चलनिधि की कमी और अधिकता, दोनों ही स्थितियों में एक-दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं (सारणी 1)। इस पूरकता का एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि भारत के बैंक-केंद्रित और विकसित हो रहे डेट बाज़ार में, बैंक सावधि जमाराशि और डेट म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से निवेशकों के अलग-अलग वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यह संरचनात्मक विभाजन इन दोनों लिखतों के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा को कम करता है, जिससे एक-दूसरे का विकल्प बनने के बजाय, दोनों में एक साथ निवेश को बढ़ावा मिलता है। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि बैंक सावधि जमाराशि और इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रवाह के बीच कोई खास संबंध नहीं है।

संदर्भ:

1. गुप्ता, एम., कुमार, एस., बोराड, ए., सीट, एस. के. और केडिया, पी. (2025), 'इक्विटी म्यूचुअल फंड्स: भारत के बचत परिदृश्य में बदलाव', *आरबीआई मासिक बुलेटिन*, अगस्त, 79(8), 81-94.
2. आईएम, जे., एलआई, वाय., और वांग, ए. (2025), 'बैंक जमाराशि और मुद्रा बाजार निधि के बीच प्रतिस्थापन को कौन से कारक संचालित करते हैं?', *फेड्स टिप्पणियां (नवंबर)*, फेडरल रिज़र्व व्यवस्था के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स.

II.4.12 जमा वृद्धि के ऋण विस्तार से पीछे रहने की पृष्ठभूमि में, वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह 2025-26 (31 मार्च, 2026 तक) के दौरान बढ़कर ₹47.0 लाख करोड़ हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में ₹36.2 लाख करोड़ था; इसे बैंकों और गैर-बैंक दोनों स्रोतों से मिले ऋण का समर्थन प्राप्त था (परिशिष्ट सारणी 5)। गैर-बैंक स्रोतों से प्रवाह में वृद्धि मुख्य रूप से कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण हुई। 31 मार्च, 2026 तक, वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल बकाया ऋण में 15.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें गैर-बैंक स्रोतों ने 13.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की।

निष्कर्ष

II.4.13 इस वर्ष के दौरान, मुद्रा-जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई, जबकि मुद्रा की मांग ऊंचे स्तरों पर बनी रही। जमा और ऋण वृद्धि के बीच लगातार बने अंतर के बावजूद, बैंक ऋण में दोहरे अंकों में विस्तार हुआ और यह काफी हद तक व्यापक आधार वाला रहा, जिसका नेतृत्व सेवा और खुदरा क्षेत्रों ने किया।

II.5 वित्तीय बाज़ार

II.5.1 2025-26 में वैश्विक वित्तीय बाज़ार अस्थिर रहे, जिसकी वजहें बढ़ता राजकोषीय घाटा, ऋण भुगतान की चिंताएँ, संवृद्धि और मुद्रास्फीति के अलग -अलग परिणाम, और व्यापार पर लगाए गए टैरिफ थे। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारतीय वित्तीय बाज़ारों ने मज़बूती दिखाई; जिसमें मुद्रा बाज़ार की दरें नीतिग रेपो रेट और बाज़ार में मौजूद चलनिधि की स्थिति के हिसाब से ही बदलती रहीं। पहली तिमाही में गिरावट के बाद, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की अधिक आपूर्ति, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर में देरी और मध्य-पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच राष्ट्रिक बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई। कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड में भी बढ़ोतरी का रुझान दिखा, और साथ ही स्प्रेड्स भी बढ़ा; ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अलग-अलग कंपनियों की आय के नतीजे अलग-अलग रहे। पूरे साल भारतीय शेयर बाज़ार अस्थिर रहे। एक तरफ़ वे वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ़ उम्मीद से ज़्यादा जीडीपी संवृद्धि और सरकार की सहायक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों से उन्हें सहारा मिल रहा था। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और पोर्टफोलियो निवेश के बाहर जाने के कारण, भारतीय रुपया (आईएनआर) अवमूल्यन के साथ कमज़ोर बना रहा।

मुद्रा बाज़ार

II.5.2 2025-26 के दौरान, मुद्रा बाज़ार की दरें नीतिगत रेपो दर और बदलती चलनिधि स्थितियों के साथ-साथ चलीं। भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) रेपो दर के अनुरूप रही, और 2025-26 के दौरान रेपो दर पर इसका औसत स्प्रेड (-) 7 आधार अंक रहा, जबकि 2024-25 में यह 6 आधार अंक था। डबल्यूएसीआर में अस्थिरता, जिसे विचरण गुणांक[40] द्वारा मापा जाता है, पिछले वर्ष के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 4.8 प्रतिशत हो गई।

II.5.3 अप्रैल से जुलाई 2025 के प्रारंभ तक, भारी अधिशेष चलनिधि के कारण, डबल्यूएसीआर स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर, जो नीतिगत दर दायरे का निचला स्तर है, के आस-पास बना रहा। जुलाई 2025 के मध्य से, रिज़र्व बैंक द्वारा परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों के माध्यम से चलनिधि अवशोषित करने के बाद, डबल्यूएसीआर बढ़ा और नीतिगत रेपो दर के करीब कारोबार करने लगा। हालांकि, दिसंबर 2025 के मध्य से जनवरी 2026 तक, चलनिधि अधिशेष में कमी के बीच, डबल्यूएसीआर नीतिगत दायरे की ऊपरी सीमा, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर के करीब पहुंच गया। फरवरी में डबल्यूएसीआर में कमी आई, जबकि मौसमी प्रभाव के बाद मार्च के अंत में यह ऊंचा बना रहा। संपार्श्विक बाजार खंड - त्रिपार्टी रेपो और बाजार रेपो - ने डबल्यूएसीआर उतार-चढ़ाव का अनुसरण किया (चार्ट II.5.1ए)।

II.5.4 वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में लंबी अवधि के मुद्रा बाजार लिखतों के लिए, एकदिवसीय रुझानों के अनुसरण में 3-महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की आय में कमी आई। हालांकि, दूसरी छमाही में, सीडी दरें ऊंची बनी रहीं; इसकी वजह यह थी कि ऋण की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए, बैंकों ने अपनी निधि संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा जमा प्रमाणपत्र जारी किए। दूसरी छमाही में वाणिज्यिक पत्र दरों में भी वृद्धि का रुख रहा (चार्ट II.5.1बी) ।

II.5.5 मुद्रा बाजार[41] में औसत दैनिक कारोबार पिछले वर्ष के ₹5.5 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹6.4 लाख करोड़ हो गया। मांग मुद्रा बाजार में तिमाही कारोबार में दूसरी तिमाही से मुख्य रूप से बढ़ता हुआ रुझान देखा गया, जिसका श्रेय आंशिक रूप से बाजार के समय[42] में विस्तार को दिया जा सकता है।

II.5.6 2025-26 के दौरान भी मुद्रा बाजार में संपार्श्विक खंडों का प्रभुत्व बना रहा, जिसमें त्रिपार्टी रेपो और बाजार रेपो की

[40] विचरण गुणांक को मानक विचलन और माध्य के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

[41] मांग मुद्रा, त्रिपार्टी रेपो और बाजार रेपो (एकदिवसीय और मीयादी, दोनों खंड के), शनिवार को छोड़कर।

[42] मांग मुद्रा बाजार, त्रिपार्टी रेपो और बाजार रेपो के लिए व्यापार का समय 1 जुलाई और 1 अगस्त, 2025 से क्रमशः शाम 7 बजे और शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

चार्ट II.5.1: मुद्रा बाज़ार दरों द्वारा नीतिगत रेपो दर का पालन किया जाना

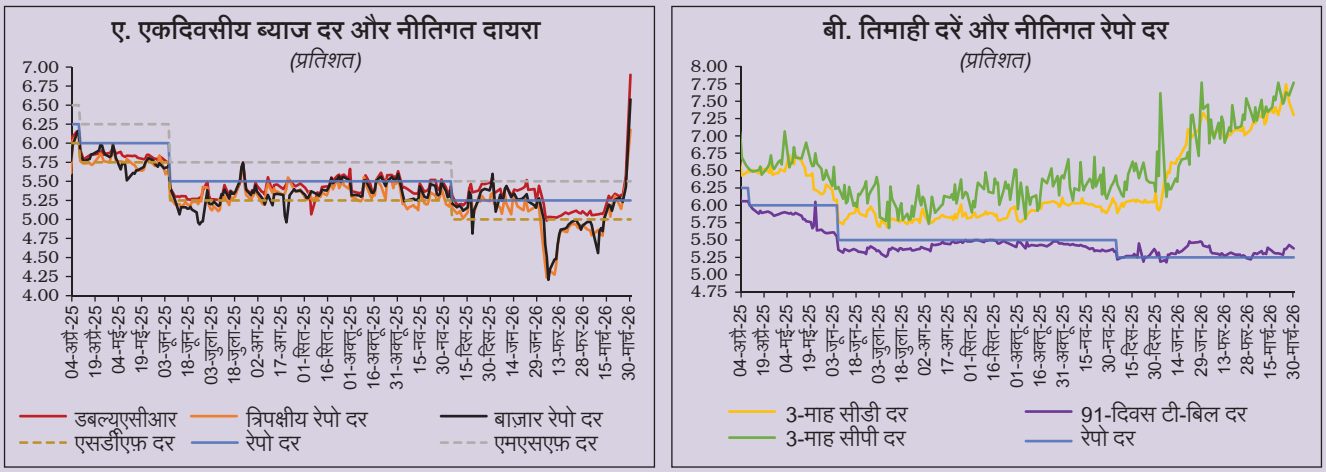

स्रोत: आरबीआई, एफ़बीआईएल, सीसीआईएल-एफ़टीआरएसी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

औसत हिस्सेदारी क्रमशः लगभग 67 प्रतिशत और 30 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान मांग मुद्रा बाजार की हिस्सेदारी आंशिक रूप से बढ़कर 3 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.5.2) ।

II.5.7 लंबी अवधि के खंडों में, ट्रेजरी -बिल दरों पर सीडी दरों और सीपी दरों का औसत दैनिक स्प्रेड सितंबर 2025 तक नीचे की ओर चला गया, जबकि उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.5.3) । प्राथमिक बाजार में, सीडी का निर्गमन पहली तिमाही के ₹2.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 की चौथी तिमाही में ₹5.3 लाख करोड़ हो गया। 2025-26 में कुल सीडी निर्गमन ₹13.5 लाख करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष कुल निर्गमन ₹11.9 लाख करोड़ था।

II.5.8 चूंकि चलनिधि की स्थिति काफी हद तक अधिक रही और ब्याज दरें अनुकूल थीं, इसलिए 2025-26 की पहली छमाही के दौरान सीपी के नए निर्गम में एक स्थिर रुझान देखने को मिला। हालांकि, 2025-26 की दूसरी छमाही में सीपी निर्गम में गिरावट आई, क्योंकि ऊंची दरों के कारण बैंक से ऋण लेने

चार्ट II.5.2: मुद्रा बाजार में संपार्श्विक संवर्ग की अधिकता

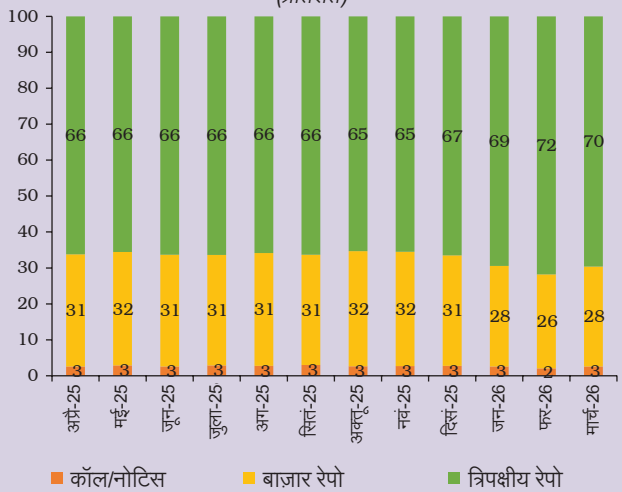

स्रोत: सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

चार्ट II.5.3: 2025-26 की दूसरी छमाही में सीपी और सीडी दर स्प्रेड में संवृद्धि

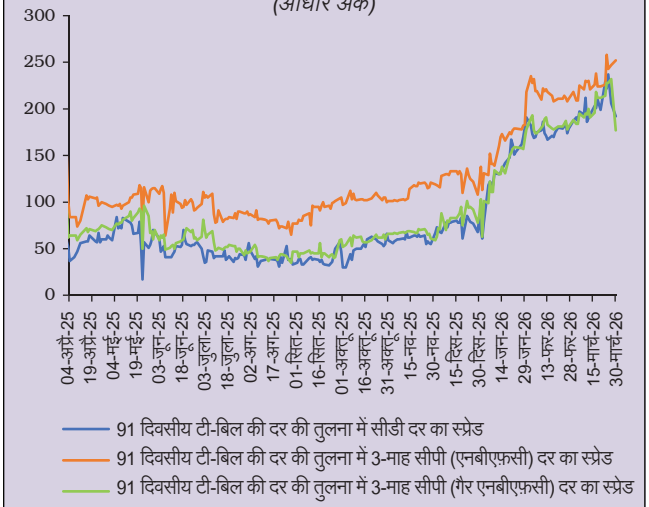

स्रोत: एफ़बीआईएल, कोजेंसिस और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। 2025-26 के दौरान सीपी के कुल निर्गम पिछले साल के ₹15.7 लाख करोड़ से बढ़कर ₹16.9 लाख करोड़ हो गए।

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार

II.5.9 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, घरेलू सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल वक्र (यील्ड कर्व) और ज़्यादा कमी की ओर अग्रसर हो गया, क्योंकि रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति में ढील और चलनिधि बढ़ाने के उपायों के बीच, छोटी और मध्यम अवधि के प्रतिफल में नरमी का रुझान दिखा, जबकि लंबी अवधि के प्रतिफल एक सीमित दायरे में रहीं। इस तिमाही के दौरान कुल ₹2.39 लाख करोड़ की खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) खरीद नीलामी आयोजित की गईं। हालाँकि, जून में मौद्रिक नीति के रुख को बदलकर 'तटस्थ' (न्यूट्रल) किए जाने के बाद प्रतिफल में कमी आई, क्योंकि दरों में और ज़्यादा कटौती की उम्मीदें कम हो गईं (चार्ट II.5.4)।

II.5.10 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में कमी आई। ऐसा 2025-26 की पहली तिमाही जीडीपी डेटा के उम्मीद से बेहतर रहने के बाद हुआ, लेकिन साथ ही अमेरिका द्वारा ऊँचे टैरिफ लागू करने और जीएसटी को तर्कसंगत बनाने से पैदा हुई राजकोषीय चिंताओं के कारण भी ऐसा हुआ। हालाँकि, प्रतिफल में बढ़ोतरी सीमित रही, क्योंकि जब यह स्पष्ट हो गया कि वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) को तर्कसंगत बनाने से होने वाला राजस्व घाटा सीमित होगा और 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए सरकार की बाज़ार से ऋण लेने की योजना काफी हद तक उम्मीद के मुताबिक ही रहेगी, तो ज़रूरत से ज़्यादा आपूर्ति से जुड़ी चिंताएँ कम हो गईं।

चार्ट II.5.4: 10-वर्षीय जी-सेक सामान्य प्रतिफल

(प्रतिशत)

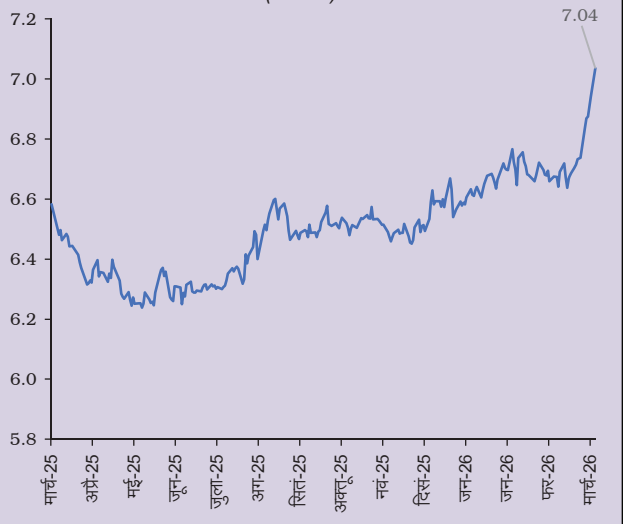

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

II.5.11 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान, प्रतिफल में दोनों तरफ़ उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 2025-26 की दूसरी तिमाही का जीडीपी डेटा उम्मीद से बेहतर रहने और दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक[43] में 25-बीपीएस की दर कटौती के बाद आगे और ढील मिलने की उम्मीदें कम होने से प्रतिफल में बढ़ोतरी का रुझान बना। हालाँकि, रिज़र्व बैंक के चलनिधि बढ़ाने के उपायों ने प्रतिफल पर पड़ रहे इस बढ़ते दबाव को कम करने में मदद की। इस तिमाही के दौरान कुल ₹1.81 लाख करोड़ की ओएमओ खरीद की गई, जिसमें से ₹1.50 लाख करोड़ की खरीद नीलामी के ज़रिए हुई।

II.5.12 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान, प्रतिफल में कमी का रुझान बना रहा। ऐसा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित उम्मीद से ज़्यादा सकल बाज़ार उधार और मध्य-पूर्व में संघर्ष बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेज़ी के कारण हुआ। 2025-26 के आखिरी ट्रेडिंग सत्र में, 10-वर्षीय मूल सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल जुलाई 2024 के बाद पहली बार 7 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई। इस तिमाही के दौरान कुल ₹4.57 लाख करोड़ की ओएमओ खरीद की गई, जिसमें से ₹3.5 लाख करोड़ की खरीद नीलामी के ज़रिए हुई।

II.5.13 1 अप्रैल, 2020 से पूर्ण सुलभ मार्ग (एफ़एआर)[44] की शुरुआत के साथ, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई)

[43] मौद्रिक नीति परिचालन से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय III में दिए गए हैं।

[44] एफ़एआर के अंतर्गत, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियाँ अनिवासी निवेशकों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के पूरी तरह से खुली हैं, और साथ ही वे घरेलू निवेशकों के लिए भी उपलब्ध हैं।

सारणी II.5.1: ऋण लिखतों में एफपीआई निवेश (मार्च अंत)

(राशि ₹ हजार करोड़ में)

निवेश का मार्ग/चैनल	2024			2025			2026		
	सीमा	एफ़पीआई शेयर पूंजी*	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)	सीमा	एफ़पीआई शेयर पूंजी*	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)	सीमा	एफ़पीआई शेयर पूंजी*	उपयोग (सीमा का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य मार्ग ^	1,172.6	187.1	16.0	1,295.3	187.2	14.5	1,470.7	186.6	12.7
वीआरआर ^	250.0	175.4	70.1	250.0	205.2	82.1	250.0	188.8	75.5
एफ़एआर #	3,866.2	173.8	4.5	4,337.0	306.2	7.1	4,751.2	313.3	6.6

^: इसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां (जी-सेक), राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (एसजीएस) और कॉर्पोरेट बांड शामिल हैं।
#: केवल मार्ग के अंतर्गत शामिल निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है।
*: वीआरआर के लिए, यह एफपीआई को आवंटित निवेश सीमा को दर्शाता है।
स्रोत: सीसीआईएल और एनएसडीएल।

के पास निवेश के तीन चैनल हैं - सामान्य मार्ग;[45] स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर); और पूरी तरह से पूर्ण सुलभ मार्ग (एफ़एआर) [सारणी II.5.1] । कुल मिलाकर, एफ़पीआई ने 2025-26 में ऋण लिखतों में ₹16.1 हज़ार करोड़ का निवेश किया।

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार

II.5.14 हालांकि 2025-26 के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट आई, फिर भी वे सुदृढ़ बने रहे (सारणी II.5.2) ।

II.5.15 2025-26 के दौरान, मिश्रित कॉर्पोरेट आय परिणामों के बीच, एएए-रेटेड 3-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और समान परिपक्वता वाले सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल के बीच का अंतर (स्प्रेड) थोड़ा बढ़ गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में

सारणी II.5.2: कॉर्पोरेट बांड प्रतिफल*

(प्रतिशत)

इकाई	मार्च 2025	मार्च 2026	परिवर्तन (बीपीएस)
1	2	3	4 (=3-2)
(i) पीएसयू, एफआई और बैंक	7.48	7.33	-15
(ii) एनबीएफसी	7.70	7.53	-17
(iii) कॉर्पोरेट्स	7.62	7.36	-26

*: एएए-रेटेड 3-वर्षीय बाँड।
टिप्पणी: प्रतिफल की गणना मासिक औसत के रूप में की गयी है।
स्रोत: एफ़आईएमएमडीए।

औसत दैनिक द्वितीयक बाज़ार कारोबार पिछले वर्ष के ₹6.2 हज़ार करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹7.1 हज़ार करोड़ हो गया (चार्ट II.5.5) ।

II.5.16 घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्राथमिक निर्गम पिछले वर्ष के ₹9.9 लाख करोड़ से घटकर 2025-26 में ₹9.1 लाख करोड़ रह गए; इसके साथ ही, विदेशी निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाने की गति में भी नरमी आई। निजी नियोजन (प्राइवेट प्लेसमेंट्स) पसंदीदा चैनल

चार्ट II.5.5: कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में एएए-रेटेड 3-वर्षीय प्रतिफल स्प्रेड और कुल कारोबार

(₹ हजार करोड़, बायां मान; आधार अंक, दायां मान)

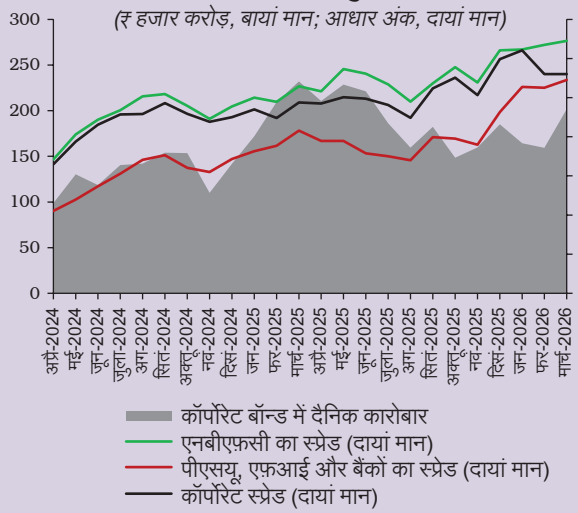

स्रोत: सेबी और एफ़आईएमएमडीए।

[45] पूर्ववर्ती मध्यम-अवधि ढाँचा (एमटीएफ़)।

बना रहा, जिसके माध्यम से घरेलू बॉन्ड बाज़ार से जुटाए गए कुल संसाधनों का 99 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ। इस वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफ़पीआई का निवेश बढ़ा। हालांकि, पूर्ण सीमाओं में वृद्धि के कारण, एफ़पीआई द्वारा अनुमोदित सीमाओं का उपयोग एक वर्ष पहले के 15.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2026 के अंत में 15.0 प्रतिशत रह गया।

इक्विटी बाज़ार

II.5.17 2025-26 में, भारतीय इक्विटी बाज़ार में दोनों तरफ़ हलचल देखने को मिली। साल के पहले छमाही में यह बढ़ा, क्योंकि मौद्रिक और राजकोषीय नीति के सहायक उपायों का साथ मिला; वहीं दूसरे छमाही में इसमें गिरावट आई, क्योंकि मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी चिंताओं का निवेशकों के मन पर बुरा असर पड़ा। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 7.1 प्रतिशत गिरकर मार्च 2026 के आखिर में 71,948 पर बंद हुआ (चार्ट II.5.6)। प्राथमिक बाज़ार में सार्वजनिक और राइट्स निर्गम, अधिमानी आबंटन और अहर्ता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के ज़रिए संसाधन जुटाने की स्थिति मज़बूत बनी रही।

II.5.18 2025-26 की पहली तिमाही में, भारतीय इक्विटी बाज़ार में दोनों तरफ़ हलचल देखने को मिली। इसकी वजह कुछ ऐसे प्रतिकूल कारक थे, जैसे अमेरिका द्वारा टैरिफ़ की घोषणाएँ, भारत-पाकिस्तान संघर्ष का बढ़ना और मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव। वहीं, निवेशकों का मन कुछ सकारात्मक बातों से बेहतर हुआ, जैसे रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार को रिकॉर्ड सरप्लस अंतरित करना और जून में रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में ढील की शुरुआत करना। दूसरी तिमाही में, बाज़ार गिरे, क्योंकि टैरिफ़ को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा एच1 बी वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी जैसी नकारात्मक बातों का असर, निवेशकों के विश्वास पर भारी पड़ गया जो भारत की राष्ट्रिक रेटिंग में एक बड़ी वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किए गए सुधार,जीएसटी सुधारों की घोषणा और मज़बूत मैक्रोइकोनॉमिक डेटा के जारी होने से बना था। तीसरी तिमाही में, बाज़ार बढ़े, क्योंकि दूसरी तिमाही के कॉर्पोरेट कमाई के नतीजों को लेकर आशावाद था, और अमेरिका के फ़ेडरल रिज़र्व द्वारा नीतिगत दरमें कटौती तथा एआई समेत तकनीक में बढ़ते निवेश से वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत मिले थे। चौथी तिमाही में बाज़ार गिरे, क्योंकि टैरिफ़ को लेकर नई अनिश्चितताएँ, मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव का बढ़ना और एआई से जुड़ी लगातार चिंताओं का असर, भारत-ईयू

चार्ट II.5.6: इक्विटी बाजार

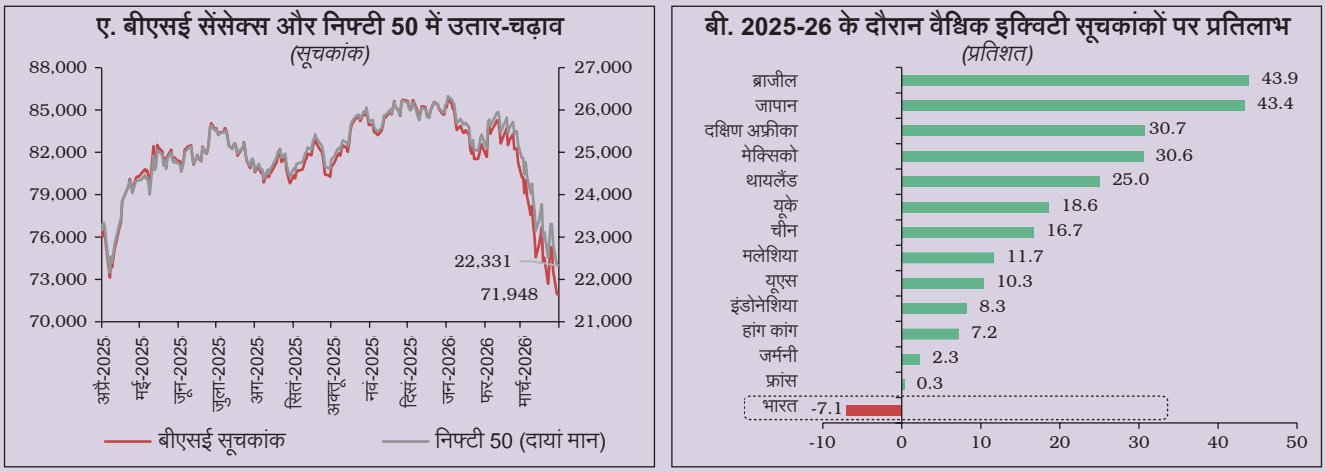

स्रोत: बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग।

व्यापार समझौतों की घोषणा, और मौद्रिक नीति के वक्तव्यों में 2025-26 तथा 2026-27 के पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी संवृद्धि के ऊँचे अनुमानों से बने बेहतर माहौल पर भारी पड़ गया।

II.5.19 कुल मिलाकर, 2025-26 में बीएसई 150 मिडकैप में मामूली 1.0 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि बीएसई 250 स्माल कैप में 6.5 प्रतिशत की गिरावट आई। इस दौरान क्षेत्रवार इंडेक्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा (चार्ट II.5.7ए) । एफ़पीआई ने 2025-26 के दौरान घरेलू इक्विटी बाज़ार में ₹2.7 लाख करोड़ की निवल बिक्री की, जबकि पिछले वर्ष यह निवल बिक्री ₹2.6 लाख करोड़ थी। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2025-26 में ₹8.5 लाख करोड़ की निवल खरीदारी की, जबकि पिछले वर्ष यह ₹6.1 लाख करोड़ थी (चार्ट II.5.7बी) ।

प्राथमिक बाज़ार में संसाधन जुटाना

II.5.20 इक्विटी बाज़ार के प्राथमिक खंड में, क्यूआईपी और अधिमानी आबंटन के ज़रिए संसाधन जुटाने की स्थिति 2025-26 के दौरान ₹2.2 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के बराबर ही था। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ), फॉलो-ऑन सार्वजनिक प्रस्तावों (एफ़पीओ) और राइट्स निर्गम के ज़रिए संसाधन जुटाने की स्थिति पिछले वर्ष के ₹2.1 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹2.3 लाख करोड़ हो गया (चार्ट II.5.8ए)। इस वर्ष के दौरान प्राथमिक बाज़ार में एफ़पीआई निवल खरीदार रहे। सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के ज़रिए म्यूचुअल फंड में औसत मासिक योगदान पिछले वर्ष के ₹24.1 हज़ार करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹29.1 हज़ार करोड़ हो गया (चार्ट II.5.8बी)।

विदेशी मुद्रा बाज़ार

II.5.21 2025-26 के दौरान आईएनआर में गिरावट का रुझान रहा और यह 9.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। 2025-26 की पहली छमाही के दौरान, यूएस डॉलर इंडेक्स में नरमी और यूएस द्वारा आपसी टैरिफ को निलंबित करने के कारण आईएनआर में शुरू में मज़बूती आई, और 2 मई 2025 को यह ₹83.75 प्रति यूएसडी के साथ साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। हालाँकि, बाद में सीमा पर तनाव बढ़ने, टैरिफ से जुड़ी चिंताओं और इक्विटी श्रेणी से एफ़पीआई के बाहर जाने के कारण इस पर दबाव बढ़ गया। आईएनआर, पहली छमाही के अंत में ₹88.79 प्रति यूएसडी पर बंद हुआ, जो 3.8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है (चार्ट II.5.9)।

II.5.22 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान, शुरू में एक सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद, आईएनआर पर बाद में कई विपरीत परिस्थितियों का दबाव पड़ा, जिनमें व्यापार से जुड़ी लगातार अनिश्चितताएँ और माल व्यापार घाटे का बढ़ना शामिल है। फरवरी के दौरान व्यापार के मोर्चे पर सकारात्मक

चार्ट II.5.7: व्यापक बाज़ार और संस्थागत निवेश

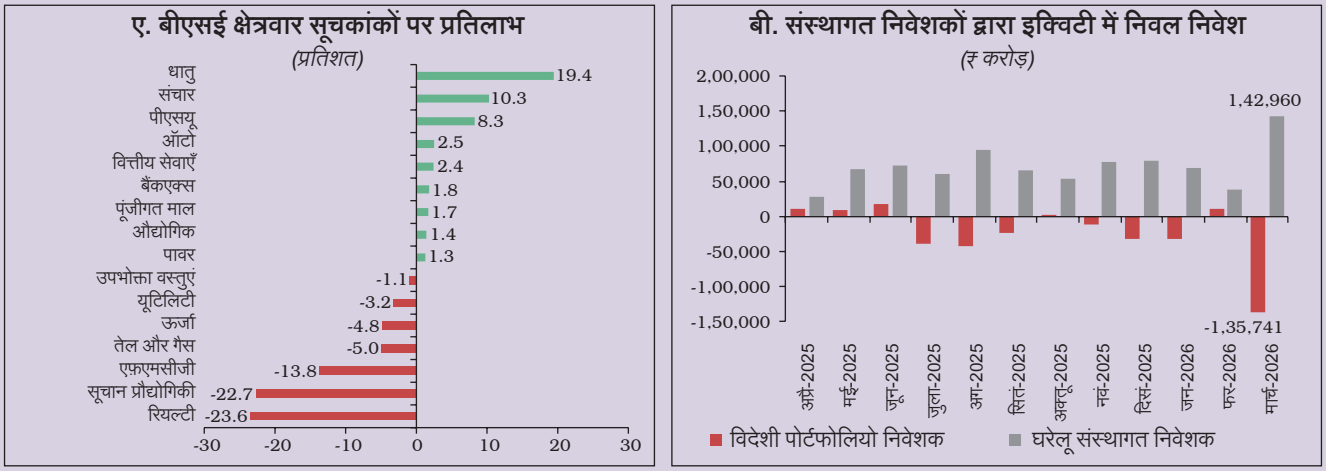

स्रोत: सेबी, एनएसडीएल और ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.5.8: संसाधन जुटाना

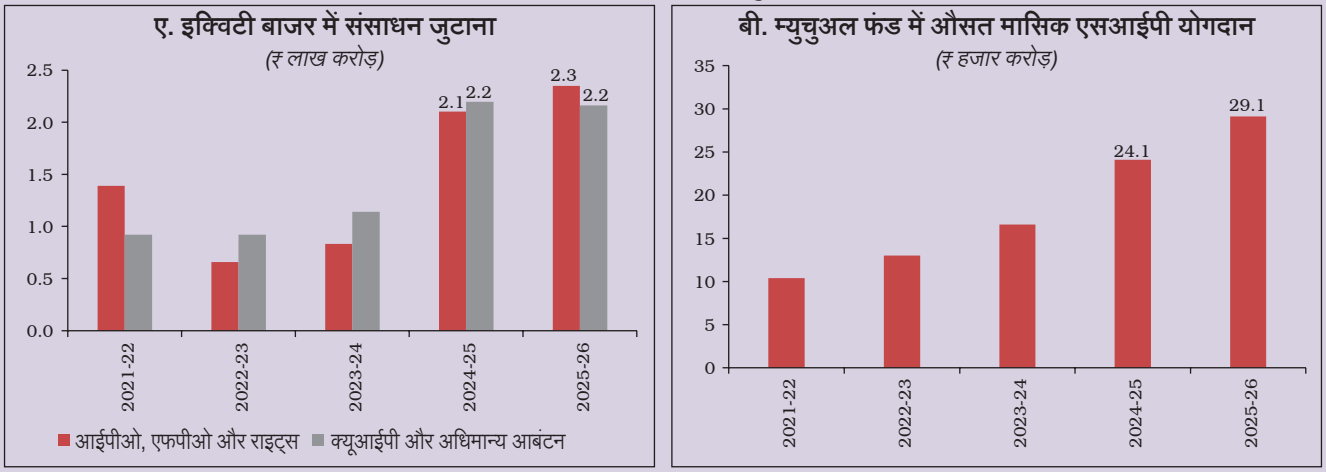

स्रोत: सेबी और एएमएफआई।

घटनाक्रमों के चलते आईएनआर ने अपनी कुछ गिरावट की भरपाई की। हालाँकि, मार्च में मध्य पूर्व में संघर्ष छिड़ने और उसके परिणाम स्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण जोखिम की स्थिति से इस पर फिर से दबाव बढ़ गया। एफ़पीआई के बाहर जाने और डॉलर इंडेक्स में मज़बूती आने का भी आईएनआर पर नकारात्मक असर पड़ा। छ2:2025-26 के लिए, आईएनआर 6.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹94.83 प्रति यूएसडी पर बंद हुआ।

चार्ट II.5.9: रुपये, यूएस डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और ईएम मुद्रा सूचकांक में उतार-चढ़ाव

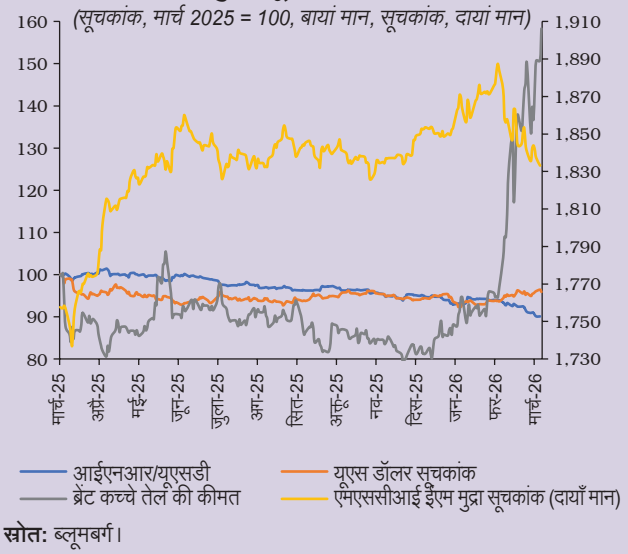

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

II.5.23 2025-26 के दौरान, नवंबर 2025 तक फॉरवर्ड प्रीमियम काफी हद तक ब्याज दर के अंतर के अनुरूप एक सीमित दायरे में रहा। हालाँकि, दिसंबर 2025 में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण इनमें उछाल आया और उसके बाद भी ये ऊँचे स्तर पर बने रहे। 2025-26 के दौरान, 40-मुद्रा नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की गिरावट आई।

निष्कर्ष

II.5.24 2025-26 के दौरान, वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, भारतीय वित्तीय बाज़ारों ने आघात–सहनीयता और व्यवस्थित गतिविधियाँ प्रदर्शित कीं। एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार दरें काफी हद तक नीतिगत रेपो दर और चलनिधि की बदलती स्थितियों के अनुरूप बनी रहीं। पहली तिमाही में सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल नरम रही, लेकिन बाद में राजकोषीय चिंताओं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और दिसंबर 2025 में दरों में कटौती के बाद आगे और नरमी की कम उम्मीदों के चलते यह फिर से सख्त हो गई। साल के दूसरे हिस्से में व्यापार से जुड़ी अनिश्चितता और पोर्टफोलियो इक्विटी के बाहर जाने के कारण आईएनआर में गिरावट का रुझान देखा गया। बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, वैश्विक वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह से भारतीय इक्विटी बाज़ारों के प्रभावित होने की उम्मीद है।

II.6 सरकारी वित्त

II.6.1 केंद्र सरकार ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप, 2025-26 (सं.अ.) में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफ़डी)[46] को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम करके और 2026-27 (ब.अ.) में इसे 4.3 प्रतिशत पर तय करके, राजकोषीय अनुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। केंद्र का जीडीपी-से-ऋण का अनुपात बजटीय रूप से 2025-26 (सं.अ.) के 56.1 प्रतिशत से गिरकर 2026-27 में 55.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.2 केंद्र सरकार ने 2025-26 (सं.अ.) में अपने जीएफ़डी को जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर सीमित रखा, जो 2024-25 के 4.8 प्रतिशत से कम है। 2025-26 के दौरान, राजकोषीय समेकन का कारण बजट से अधिक गैर-कर राजस्व और व्यय का युक्तिकरण रहा (सारणी II.6.1 और चार्ट II.6.1)।

II.6.3 2025-26 (सं.अ.) में राजस्व व्यय, 2024-25 की तुलना में 7.4 प्रतिशत बढ़ गया; इसका मुख्य कारण ब्याज

सारणी II.6.1: केंद्र सरकार का राजकोषीय प्रदर्शन

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (सं.अ.)	2026-27 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर-कर्ज कुल प्राप्तियां	22.1	24.6	27.9	30.8	34.1	36.5
	(9.4)	(9.1)	(9.3)	(9.3)	(9.5)	(9.3)
II. सकल कर राजस्व	27.1	30.5	34.7	38.0	40.8	44.0
	(11.5)	(11.4)	(11.5)	(11.5)	(11.4)	(11.2)
ए) प्रत्यक्ष कर	14.1	16.6	19.6	22.2	24.2	27.0
	(6.0)	(6.2)	(6.5)	(6.7)	(6.8)	(6.9)
बी) अप्रत्यक्ष कर	13.0	13.9	15.1	15.7	16.6	17.1
	(5.5)	(5.2)	(5.0)	(4.8)	(4.6)	(4.3)
III. निवल कर राजस्व	18.0	21.0	23.3	25.0	26.7	28.7
	(7.6)	(7.8)	(7.7)	(7.6)	(7.5)	(7.3)
IV. गैर-कर राजस्व	3.7	2.9	4.0	5.4	6.7	6.7
	(1.5)	(1.1)	(1.3)	(1.6)	(1.9)	(1.7)
V. गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियां	0.4	0.7	0.6	0.4	0.6	1.2
	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.1)	(0.2)	(0.3)
VI. कुल व्यय	37.9	41.9	44.4	46.5	49.6	53.5
	(16.1)	(15.6)	(14.8)	(14.1)	(13.9)	(13.6)
VII. राजस्व व्यय	32.0	34.5	34.9	36.0	38.7	41.3
	(13.6)	(12.8)	(11.6)	(10.9)	(10.8)	(10.5)
VIII. पूंजीगत व्यय	5.9	7.4	9.5	10.5	11.0	12.2
	(2.5)	(2.8)	(3.2)	(3.2)	(3.1)	(3.1)
IX. राजस्व घाटा	10.3	10.7	7.7	5.6	5.3	5.9
	(4.4)	(4.0)	(2.5)	(1.7)	(1.5)	(1.5)
X. सकल राजकोषीय घाटा	15.8	17.4	16.5	15.7	15.6	17.0
	(6.7)	(6.5)	(5.5)	(4.8)	(4.4)	(4.3)

ब.अ.: बजट अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

[46] इस अध्याय में, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सामान्य सरकार के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतकों की गणना सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला (2011-12 आधार वर्ष) का उपयोग करके की गई है।

चार्ट II.6.1: वर्ष 2025-26 में ब.अ. की तुलना में सं.अ. का राजकोषीय समेकन में योगदान

(जीडीपी का प्रतिशत)

ब.अ.: बजट अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान।

टिप्पणी: नकारात्मक योगदान, प्राप्तियों में कमी या व्यय में वृद्धि या जीडीपी में बजट अनुमान से संशोधित अनुमान तक अधोमुखी संशोधन को दर्शाता है क्योंकि ये बजटित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से गिरावट के कारण बनते हैं तथा दूसरी ओर, सकारात्मक योगदान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान में उच्च प्राप्तियां या कम व्यय को दर्शाता है, क्योंकि ये बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं।।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.6.2: प्रमुख करों का निष्पादन

(जीडीपी का प्रतिशत)

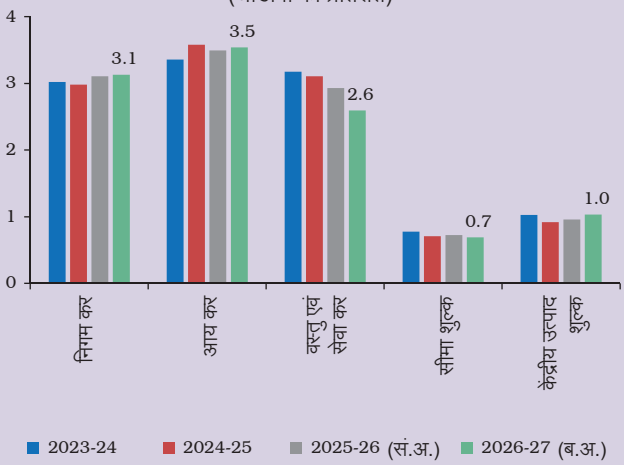

टिप्पणी: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का योग है। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2026[47] से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

भुगतान में वृद्धि और प्रमुख सब्सिडीयां थीं। प्रमुख सब्सिडीयों पर होने वाला व्यय, बजट में निर्धारित राशि से ₹46,327 करोड़ अधिक रहा; इसका मुख्य कारण खाद्य और उर्वरक सब्सिडीयों में हुई वृद्धि रहा ।

II.6.4 2025-26 (सं.अ.) में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 3.1 प्रतिशत रहा, हालांकि यह ₹25,335 करोड़ कम रहने पर भी बजट अनुमानों के अनुरूप है। 2025-26 (सं.अ.) में प्रभावी पूंजीगत व्यय मोटे तौर पर अपरिवर्तित [जीडीपी का 3.9 प्रतिशत] रहा, जो कि 2024-25 (जीडीपी का 4.0 प्रतिशत) में था।

II.6.5 2025-26 (सं.अ.) में, सकल कर आय में 7.4 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जिसका मुख्य कारण निगम कर से होने वाली आय में त्वरित संवृद्धि, और उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में दोहरे अंकों की संवृद्धि थी। यह सकल घरेलू उत्पाद का 11.4 प्रतिशत रहा, जो मोटे तौर पर 2024-25 के अनुरूप है (चार्ट II.6.2)।

II.6.6 2025-26 (सं.अ.) में निवल कर राजस्व में 7.0 प्रतिशत की संवृद्धि हुई। 2025-26 (सं.अ.) में गैर-कर राजस्व में 24.4 प्रतिशत की मज़बूत संवृद्धि दर्ज की गई, जो इसके बजट अनुमानों से ₹84,662 करोड़ अधिक है। 2024-25 में संकुचन के बाद, 2025-26 (सं.अ.) में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में मजबूती से सुधार हुआ [53.1 प्रतिशत की वृद्धि]। कुल मिलाकर, 2025-26 (सं.अ.) में कुल गैर-ऋण प्राप्तियों में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार का वित्त

II.6.7 केंद्र सरकार 2020-21 में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद से, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफ़डी को लगातार कम कर रही है (जीडीपी का 9.2 प्रतिशत) [सारणी II.6.1 और परिशिष्ट सारणी 6]। 2026-27 के लिए जीएफ़डी को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत पर निर्धारित करने के साथ, महामारी के बाद के दौर में देखी गई राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के जारी रहने की उम्मीद है।

II.6.8 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है। राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात तथा जीएफ़डी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे से मापी गई व्यय की गुणवत्ता में हाल के वर्षों में मोटे तौर पर गिरावट का रुझान जारी है, जो सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देता है (चार्ट II.6.3)।

[47] जीएसटी न्यूज़लेटर, जीएसटी परिषद सचिवालय, दिसंबर 2025, और पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), 3 सितंबर 2025 ।

चार्ट II.6.3: व्यय की गुणवत्ता

(प्रतिशत, बायां मान; अनुपात, दायां मान)

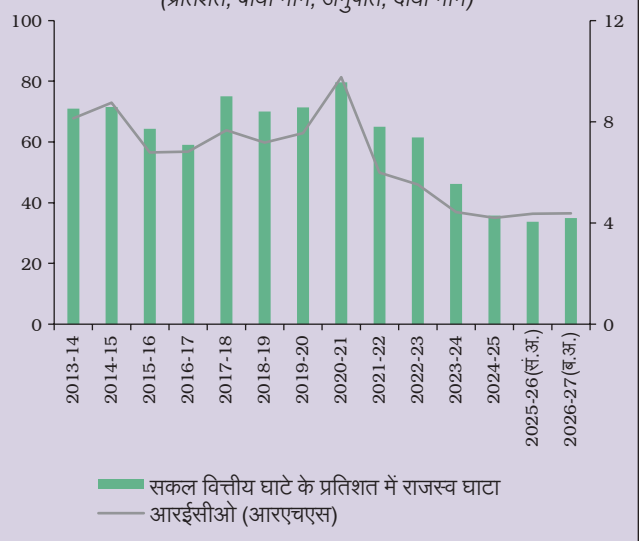

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और आरबीआई स्टाफ अनुमान ।

चार्ट II.6.4: कर राजस्व रुझान - केंद्र

(जीडीपी का प्रतिशत)

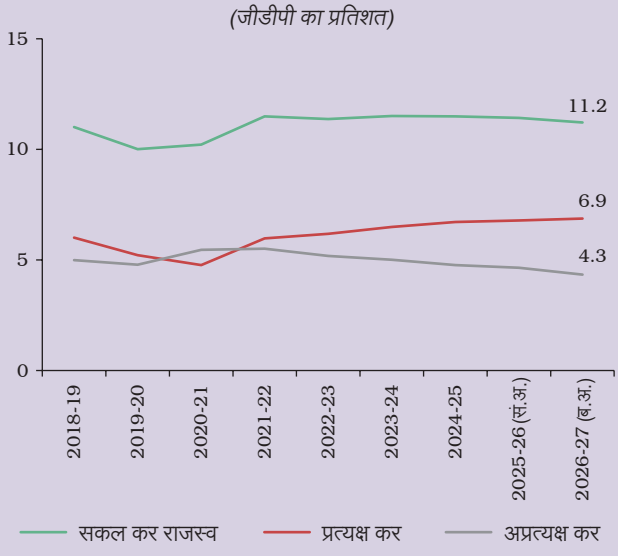

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज ।

II.6.9 सकल कर राजस्व के 2026-27 में मामूली रूप से घटकर जीडीपी के 11.2 प्रतिशत पर आने का बजट अनुमान है । अप्रत्यक्ष करों का बजट अनुमान 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.3 प्रतिशत पर कम रखा गया है, जिसका आंशिक कारण यह है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के लिए बजट आवंटन बंद कर दिया गया है (चार्ट II.6.4) ।

II.6.10 2026-27 के लिए सकल बाज़ार उधार ₹17.2 लाख करोड़ अनुमानित है, जो 2025-26 (सं.अ.) के ₹14.6 लाख करोड़ से अधिक है । 2026-27 (ब.अ.) के लिए निवल बाज़ार उधार ₹11.7 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.0 प्रतिशत) है (चार्ट II.6.5ए) । बाज़ार उधार और अल्प बचतें जीएफ़डी के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं (चार्ट II.6.5बी) ।

वर्ष 2025-26 में राज्यों का वित्त

II.6.11 2025-26 के लिए, राज्यों ने सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का बजट रखा था (सारणी II.6.2) । 22 राज्यों के अनंतिम लेखा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-फरवरी 2025-26 के दौरान, बजट अनुमानों के हिस्से

चार्ट II.6.5: बाजार उधार और जीएफडी वित्तपोषण

ए. बाजार उधार और जीएफडी

(जीडीपी का प्रतिशत)

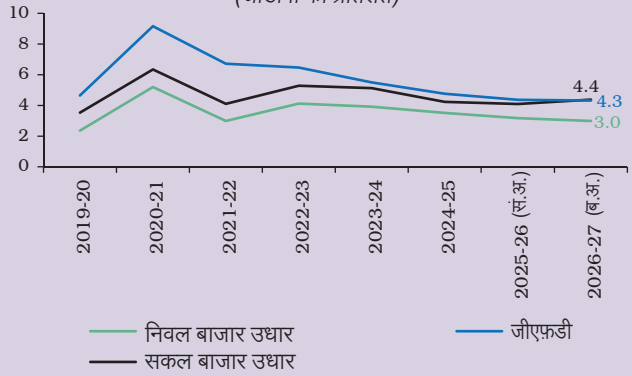

बी. जीएफडी वित्तपोषण के स्रोत

(जीडीपी का प्रतिशत)

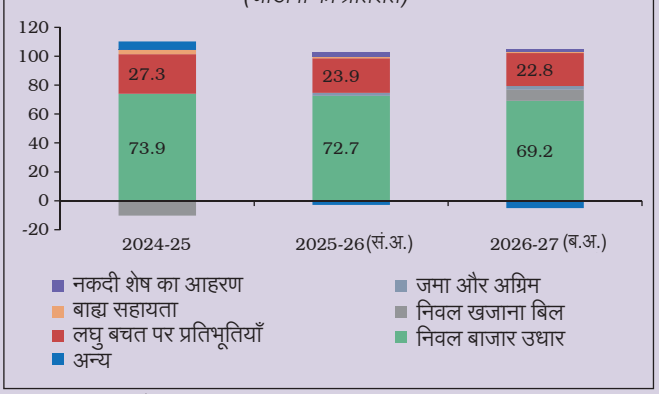

टिप्पणी: सकल और निवल बाज़ार उधार में स्विचिंग ऑपरेशन और प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद शामिल नहीं है ।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज ।

सारणी II.6.2: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजकोषीय स्थिति

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (सं.अ.)	2025-26 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6
I. गैर-कर्ज प्राप्तियां	32.5	36.6	39.5	46.0	51.8
	(13.8)	(13.6)	(13.1)	(14.0)	(14.5)
II. राजस्व प्राप्तियां	32.3	36.5	39.3	45.8	51.3
	(13.7)	(13.6)	(13.0)	(13.9)	(14.4)
III. गैर-कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5
	(0.1)	(0.04)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
IV. राजस्व व्यय	33.3	37.1	40.2	47.7	52.1
	(14.1)	(13.8)	(13.4)	(14.4)	(14.6)
V. पूंजीगत व्यय	5.8	6.7	8.1	9.9	11.4
	(2.4)	(2.5)	(2.7)	(3.0)	(3.2)
ए. पूंजीगत परिव्यय	5.3	6.0	7.5	9.1	10.6
	(2.3)	(2.2)	(2.5)	(2.7)	(3.0)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.4	0.7	0.6	0.8	0.8
	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.3)	(0.2)
VI. कुल व्यय	39.1	43.8	48.3	57.7	63.6
	(16.5)	(16.3)	(16.0)	(17.4)	(17.8)
VII. राजकोषीय घाटा	6.5	7.2	8.8	11.6	11.8
	(2.8)	(2.7)	(2.9)	(3.5)	(3.3)
VIII. राजस्व घाटा	1.0	0.6	0.9	1.9	0.8
	(0.4)	(0.2)	(0.3)	(0.6)	(0.2)
IX. प्राथमिक घाटा	2.3	2.6	3.7	6.0	5.5
	(1.0)	(1.0)	(1.2)	(1.8)	(1.5)

ब.अ.: बजट अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े, जीडीपी का प्रतिशत हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

के रूप में राज्यों का जीएफ़डी एक साल पहले के 64.3 प्रतिशत से बढ़कर 77.1 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी राजस्व प्रदर्शन में सुस्ती को दर्शाती है, जिसका मुख्य कारण राज्यों के जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह में आई कमी और केंद्र से मिलने वाले अनुदान में हुई कटौती है। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में धीमी गति से वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में मज़बूत संवृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2026-27 में राज्यों का वित्त

II.6.12 2026-27 के लिए 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनका समेकित जीएफ़डी-जीडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत अनुमानित है (सारणी II.6.3)। 2026-27 (ब.अ.) में राज्यों को सकल अंतरण में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है; यह मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अंतरण और पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के कारण है। राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण की योजना 2026-27 में भी जारी रहेगी, जिसके लिए कुल परिव्यय

सारणी II.6.3: राज्य सरकार वित्त 2026-27*: प्रमुख घाटा संकेतक

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

मद	2024-25	2025-26 (सं.अ.)	2026-27 (ब.अ.)
1	2	3	4
राजस्व घाटा	0.3	0.4	-0.1
सकल राजकोषीय घाटा	3.0	3.5	3.0
प्राथमिक घाटा	1.5	1.9	1.4

*: आंकड़े 24 राज्यों से संबंधित है, जिन्होंने 2026-27 के लिए अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है।
टिप्पणी: घाटे के संकेतकों में ऋणात्मक मान अधिशेष को दर्शाते हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

₹2 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है - यह 2025-26 (सं.अ.) के स्तरों की तुलना में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

II.6.13 सोलहवें वित्त आयोग (एफ़सी-XVI) की वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की रिपोर्ट ने केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में निरंतरता सुनिश्चित की है, साथ ही प्रदर्शन और वित्तीय अनुशासन के लिए प्रोत्साहनों को भी सुदृढ़ किया है। इसने विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत पर बरकरार रखा है ।

II.6.14 सोलहवें वित्त आयोग ने क्षैतिज अंतरण फ़ॉर्मूले को मध्यम रूप से पुनर्संतुलित किया है, जबकि इसके समता-केंद्रित मूल को बनाए रखा है (सारणी II.6.4) । जनसंख्या पर अधिक ज़ोर दिया गया है, जबकि क्षेत्रफल, आय असमानता और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को दिए गए भारांक को कम किया गया है । जहां एक ओर वन आवरण को दिया गया भारांक बरकरार रखा गया है, वहीं दूसरी ओर कर प्रयास के मानदंड को हटा दिया गया है ।आयोग ने एक नया मापदंड पेश किया है, जीडीपी में राज्यों का योगदान, जिसे 10 प्रतिशत का भार दिया गया है । यह भारत की विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं और राष्ट्रीय आर्थिक प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में राज्यों की भूमिका को मान्यता देने की आवश्यकता को दर्शाता है ।

II.6.15 अंतरण के पश्चात, राजकोषीय अनुशासन तथा राज्यों के मजबूत बजट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्व घाटा अनुदानों को समाप्त कर दिया गया है । आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा राजस्व घाटा मुख्य रूप से राजस्व जुटाने और व्यय प्रबंधन में मौजूद कमियों को दर्शाते हैं । इसलिए, आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कमियों को पूरा करने के लिए लगातार किए जाने वाले अंतरण राजकोषीय समायोजन के प्रोत्साहनों को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि केंद्र से मिलने वाले समर्थन की उम्मीदें, राज्यों द्वारा अपने स्वयं के राजस्व को बढ़ाने और खर्च को तर्कसंगत बनाने के प्रयासों को शिथिल कर सकती हैं ।

सामान्य सरकारी वित्त

II.6.16 सामान्य सरकार का जीएफ़डी 2024-25 (सं.अ.) में जीडीपी के 7.8 प्रतिशत से कम होकर 2025-26 (ब.अ.) में 7.2 प्रतिशत हो गया । ऋण-से-जीडीपी अनुपात 2025-26(ब.अ.) में मामूली बढ़कर 81.9 प्रतिशत होने का बजट अनुमान है, जिसका कुछ श्रेय राज्यों की बढ़ी हुई देनदारियों को जाता है। बाह्य देनदारियां वर्ष 2025-26 (ब.अ.) में लगातार कम 2.5 प्रतिशत पर बनी हुई हैं, जिसका अर्थ है कि विनिमय दर का जोखिम सीमित है (चार्ट II.6.6ए) ।

सारणी II.6.4: क्षैतिज न्यागमन मानदंड

(कुल का प्रतिशत)

आयाम	मानदंड	एफ़सी -XIII	एफ़सी -XIV	एफ़सी -XV	एफ़सी-XVI
		(2010-11 से 2014-15)	(2015-16 से 2019-20)	(2020-21 से 2025-26)	(2026-27से 2030-31)
1	2	3	4	5	6
आवश्यकता और लागत अक्षमता	जनसंख्या	25	27.5	15	17.5
	क्षेत्रफल	10	15	15	10
	वन आवरण	-	7.5	10	10
समता	आय अंतर / प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतर	-	50	45	42.5
	राजकोषीय क्षमता	47.5	-	-	-
निष्पादन	कर प्रयास	-	-	2.5	-
	राजकोषीय अनुशासन	17.5	-	-	-
	जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	-	-	12.5	10
	जीडीपी में योगदान	-	-	-	10

-: लागू नहीं।

टिप्पणी: एफ़सी-XIII के लिए, जनसंख्या का मापदंड 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित था। एफ़सी-XIV के लिए, 1971 की जनगणना के आंकड़ों को 17.5 प्रतिशत और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को 10 प्रतिशत भार दिया गया था। एफ़सी-XV और उसके बाद से, जनसंख्या का मापदंड 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है।

स्रोत: वित्त आयोग की रिपोर्टें।

चार्ट II.6.6: सामान्य सरकार के प्रमुख राजकोषीय संकेतक

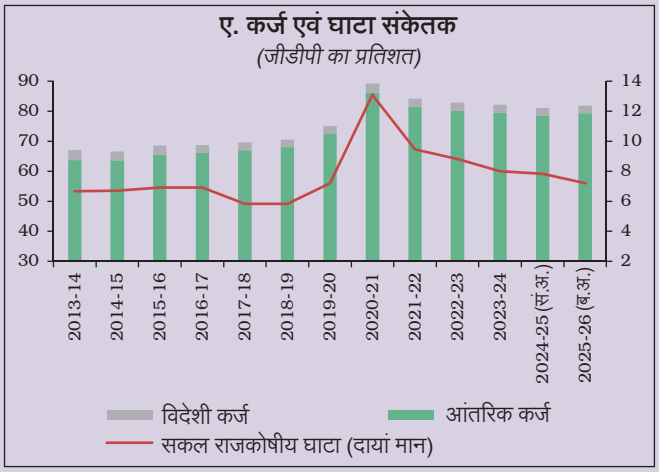

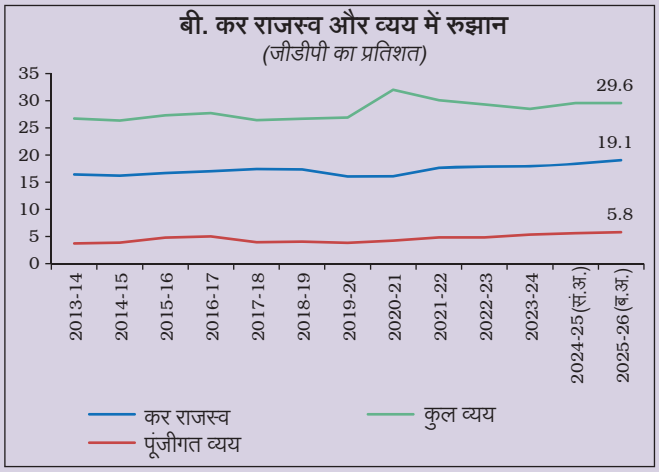

स्रोत: आरबीआई और केंद्रीय बजट दस्तावेज ।

II.6.17 सामान्य सरकार द्वारा जीएफ़डी में की गई कटौती को कर राजस्व में वृद्धि से समर्थन मिला, जो पिछले वर्ष के 18.4 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 (ब.अ.) में जीडीपी का 19.1 प्रतिशत हो गया । हालांकि, कुल व्यय का जीडीपी से अनुपात दोनों वर्षों में 29.6 प्रतिशत पर समान रहा । पूंजीगत व्यय 2025-26 (ब.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 5.8 प्रतिशत पर अधिक अनुमानित है [2024-25 में 5.6 प्रतिशत] (चार्ट II.6.6बी) ।

निष्कर्ष

II.6.18 केंद्रीय बजट 2026-27 ने महामारी के बाद के राजकोषीय समेकन के मार्ग को जारी रखा, जो मध्यम अवधि की संवृद्धि के लिए बेहतर संकेत है । 2026-27 में जीएफ़डी को जीडीपी का 4.3 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो 2025-26 (सं.अ.) में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत से कम है । खास बात यह है कि पूंजीगत व्यय पर बल बना हुआ है, जिसके 2026-27 में 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का बजट रखा गया है । सोलहवें वित्त आयोग ने प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों और दीर्घकालिक राजकोषीय उत्तरदायित्व पर नए सिरे से बल देते हुए, केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में निरंतरता सुनिश्चित की है ।

II.7 बाह्य क्षेत्र

II.7.1 बढ़ती वैश्विक नीतिगत अनिश्चितता और भू-राजनीतिक दबाव के बीच, निर्यात के विविधीकरण, सेवा व्यापार में निरंतर अधिशेष और स्थिर आवक विप्रेषण के प्रयासों के कारण भारत का बाह्य क्षेत्र व्यापक रूप से आघात सहनीय बना रहा। निवल पूंजी प्रवाह के चालू खाता घाटे (सीएडी) से कम होने के कारण, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई।

वैश्विक आर्थिक स्थितियां

II.7.2 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि 2025 में मामूली रूप से बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.7.1ए)। वैश्विक मुद्रास्फीति कम हुई, जिसने प्रमुख केंद्रीय बैंकों को नीतिगत दरों में कटौती करने के लिए प्रेरित किया गया। नियंत्रित मुद्रास्फीति दबाव और स्थिर मांग के साथ, वैश्विक व्यापार मात्रा (वस्तुएं और सेवाएं) 2025 में 5.1 प्रतिशत बढ़ गई (2024 में 3.6 प्रतिशत) [चार्ट II.7.1बी]। हालांकि, 2026 में, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के साथ, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 3.1 प्रतिशत[48] तक कमजोर होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में संघर्ष के कारण

[48] वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2026, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ।

चार्ट II.7.1: वास्तविक जीडीपी और वैश्विक व्यापार* मात्रा वृद्धि

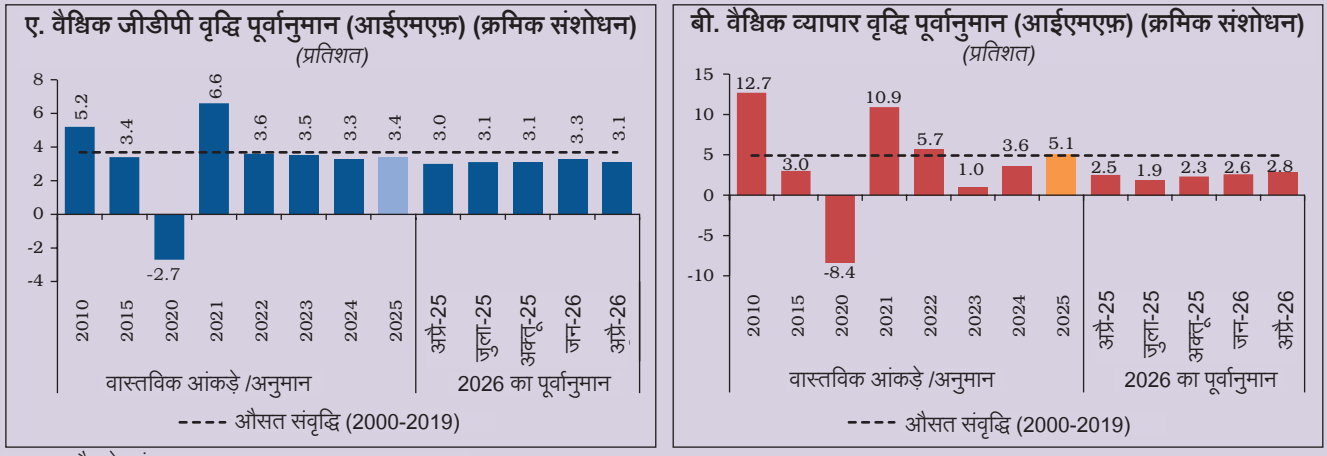

*: माल और सेवाएं।
स्रोत: डबल्यूईओ, आईएमएफ(अप्रैल 2026)।

उत्पन्न व्यवधान और जारी वैश्विक व्यापार संबंधी नीतिगत अनिश्चितताओं ने आगे के वैश्विक पण्य व्यापार दृष्टिकोण को धूमिल कर दिया है। सेवा व्यापार के तहत परिवहन और यात्रा क्षेत्रों में भी धीमी संवृद्धि की उम्मीद है। परिणामस्वरूप, 2026 में वैश्विक व्यापार मात्रा संवृद्धि में गिरावट आ सकती है।

II.7.3 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने 2025-26 के दौरान ऋण खंड द्वारा समर्थित मजबूत निवल पोर्टफोलियो अंतर्वाह दर्ज किया। पश्चिम एशिया में संघर्ष की बजह से लगातार जारी वैश्विक अनिश्चितता के कारण इक्विटी खंड में निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया (चार्ट II.7.2ए)। वर्ष 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) बढ़ गया, जिसमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवल अंतर्वाह 43 प्रतिशत बढ़ गया, जिसका नेतृत्व यूरोप और वित्तीय केंद्रों[49] ने किया (चार्ट II.7.2बी)। इसके विपरीत, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवल एफडीआई अंतर्वाह में 2025 में 2 प्रतिशत की गिरावट आई।

चार्ट II.7.2: ईएमई के लिए पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह और वैश्विक एफ़डीआई रुझान

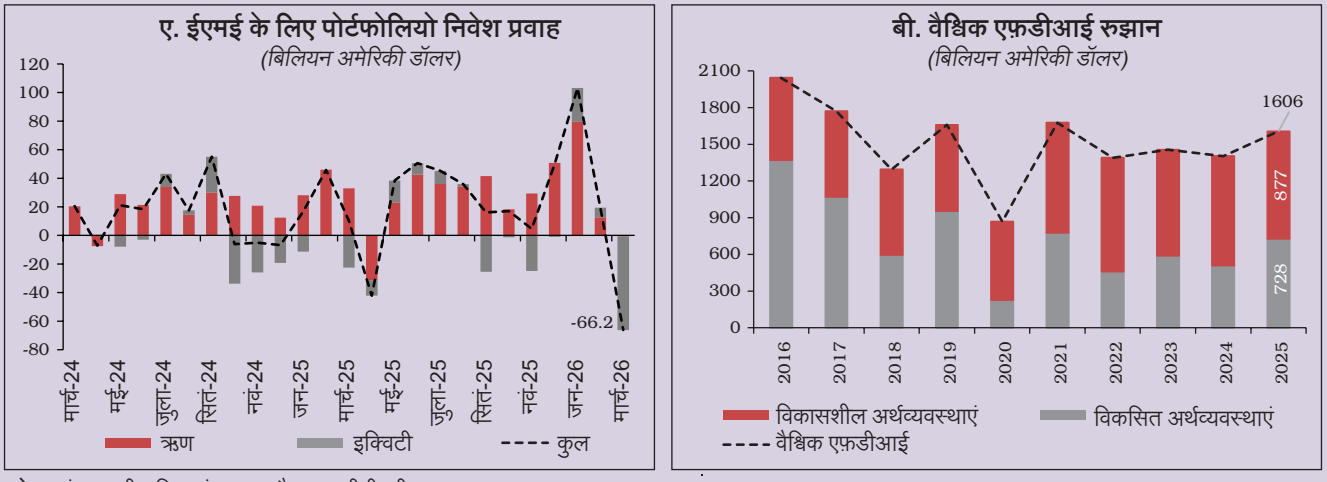

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान; और यूएनसीटीएडी।

[49] वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर, जनवरी 2026, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)।

पण्य व्यापार

II.7.4 टैरिफ संबंधी अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत के पण्य वस्तु निर्यात और आयात में (मूल्य के संदर्भ में) 2024-25 की तुलना में 2025-26 में अधिक तेज़ी से विस्तार हुआ (सारणी II.7.1)।

II.7.5 2025-26 में पण्य निर्यात में विस्तार का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक सामान; इंजीनियरिंग सामान; मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद; समुद्री उत्पाद; और अभ्रक, कोयला तथा अन्य अयस्क व खनिज (जिनमें प्रसंस्कृत खनिज भी शामिल हैं) में हुई संवृद्धि रही; जबकि पेट्रोलियम उत्पाद; रत्न और आभूषण; चावल; प्लास्टिक और लिनोलियम; तथा सूती और हथकरघा उत्पादों में संकुचन देखा गया (चार्ट II.7.3)।

सारणी II.7.1: भारत का पण्य वस्तु व्यापार

	बिलियन अमेरिकी डॉलर में मूल्य				संवृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)			
	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्यात								
ति1	121.0	103.9	114.0	111.6	26.6	-14.1	9.8	-2.2
ति2	110.7	107.2	99.6	107.9	7.8	-3.2	-7.0	8.3
ति3	104.6	105.6	108.7	110.2	-2.1	1.0	3.0	1.4
ति4	114.8	120.4	115.3	112.0	-1.9	4.9	-4.3	-2.8
वार्षिक	451.1	437.1	437.7	441.7	6.9	-3.1	0.1	0.9
आयात								
ति1	183.5	159.7	172.2	180.3	44.5	-13.0	7.8	4.7
ति2	189.0	169.4	186.7	196.0	28.1	-10.4	10.2	5.0
ति3	176.1	174.7	187.5	204.2	5.4	-0.8	7.3	8.9
ति4	167.3	170.2	173.9	194.5	-2.5	1.7	2.3	11.9
वार्षिक	716.0	674.0	720.5	775.0	16.8	-5.9	6.9	7.6
व्यापार शेष								
ति1	-62.6	-55.8	-58.1	-68.7				
ति2	-78.3	-62.2	-87.1	-88.0				
ति3	-71.5	-69.1	-78.7	-94.0				
ति4	-52.6	-49.7	-58.6	-82.5				
वार्षिक	-264.9	-236.9	-282.8	-333.2				

टिप्पणी: संख्याओं के पूर्णांकन के कारण, तिमाही आंकड़ों का योग वार्षिक आंकड़ों के बराबर नहीं है।
स्रोत: डीजीसीआईएस ।

चार्ट II.7.3: निर्यात संवृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान (2024-25 की तुलना में 2025-26)

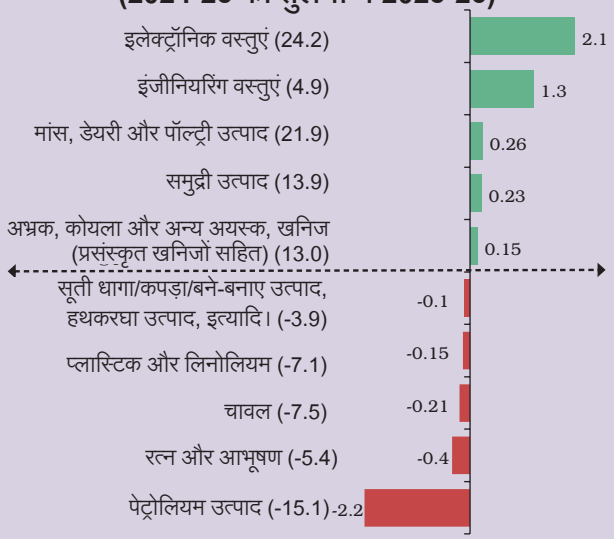

स्रोत: डीजीसीआईएस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान ।

II.7.6 भारत की शीर्ष निर्यात वस्तुओं में, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में सबसे तेज़ संवृद्धि दर्ज की गई, हालाँकि यह पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। इस संवृद्धि का मुख्य कारण मोबाइल फ़ोन का निर्यात रहा, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कुल निर्यात का लगभग 61 प्रतिशत है और जिसे अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों से छूट दी गई (चार्ट II.7.4)।

चार्ट II.7.4: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में मजबूत संवृद्धि

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

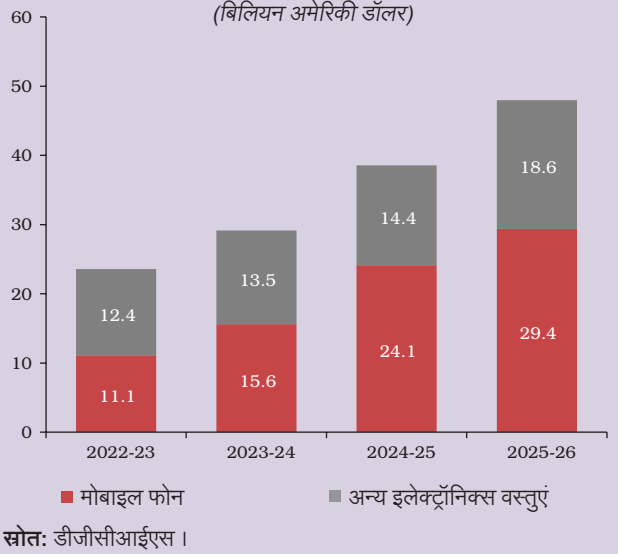

स्रोत: डीजीसीआईएस ।

II.7.7 2025-26 के दौरान, ऊँचे टैरिफ़ के कारण अमेरिका को भारत के पण्य निर्यात में संवृद्धि की गति धीमी हो गई। अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान अमेरिका के लिए निर्यात में सकारात्मक संवृद्धि उच्च टैरिफ की संभावना के चलते अग्रिम लोडिंग और उन क्षेत्रों में निर्यात में संवृद्धि के कारण हुई, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से मुक्त थे। इसके बाद, नवंबर 2025 को छोड़कर, सितंबर 2025 से अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट देखी गई। व्यापार के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के तहत, 2025-26 में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार का स्थान ले लिया।

II.7.8 2025-26 में पण्य आयात में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, और मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और नॉन-इलेक्ट्रिकल रहे। क्रूड पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, कोयला, कोक और ब्रिकेट, दालें, लोहा और इस्पात, तथा कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों ने आयात संवृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट II.7.5) ।

II.7.9 आयात की मात्रा में संवृद्धि के बावजूद, 2025-26 में तेल की कीमतों में नरमी के कारण पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट्स के आयात का मूल्य (जो 2025-26 के दौरान कुल पण्य आयात का 22.4 प्रतिशत था) घट गया (चार्ट II.7.6ए)। इस वर्ष भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस और इराक की

चार्ट II.7.5: आयात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान
[वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26]
(प्रतिशत बिंदु)

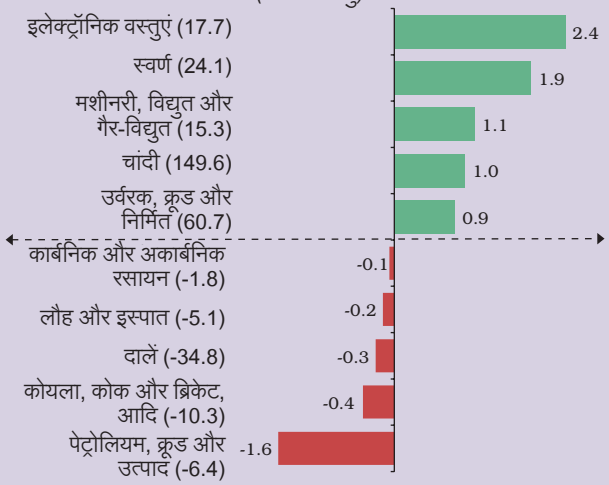

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े संबंधित वस्तुओं की संवृद्धि दर हैं ।
स्रोत: डीजीसीआईएस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान ।

हिस्सेदारी कम हो गई, जबकि सऊदी अरब, यूएई और यूएस की हिस्सेदारी बढ़ गई (चार्ट II.7.6बी)।

II.7.10 2025-26 में सोने के आयात का मूल्य बढ़ गया; सोने के आयात की मात्रा में आई कमी का प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई संवृद्धि के कारण समाप्त हो गया (चार्ट II.7.7)।

II.7.11 2025-26 में पण्य वस्तु व्यापार घाटा बढ़ गया, जिसमें तेल घाटा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा (चार्ट II.7.8ए)। प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में, चीन और स्विट्ज़रलैंड के साथ

चार्ट II.7.6: पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल)

ए: पीओएल आयात
(बिलियन अमेरिकी डॉलर, बायां मान; मिलियन टन, दायां मान)

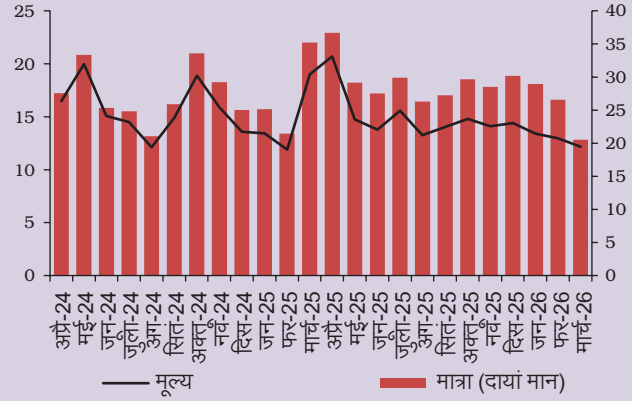

बी: कच्चे तेल आयात के प्रमुख स्रोत
(प्रतिशत)

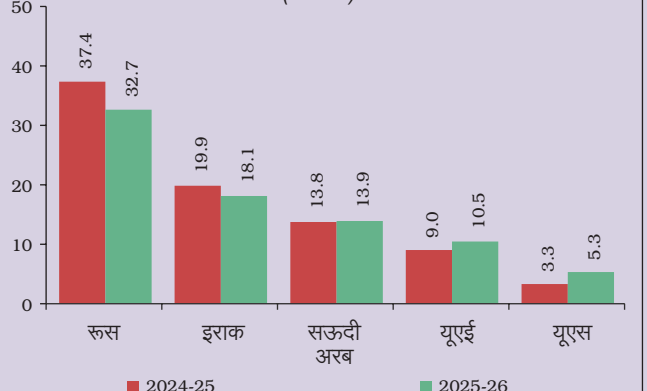

स्रोत: डीजीसीआईएस ।

चार्ट II.7.7: स्वर्ण आयात

(बिलियन अमेरिकी डॉलर, बायां मान; टन, दायां मान)

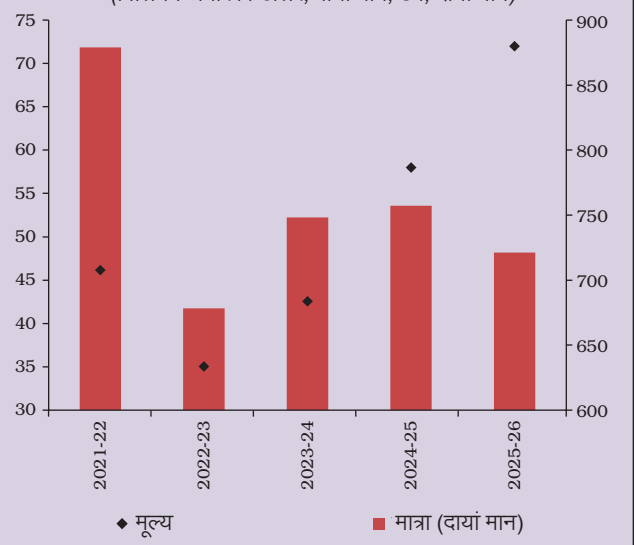

स्रोत: डीजीसीआईएस ।

व्यापार घाटा बढ़ गया, जबकि 2025-26 में स्पेन के साथ व्यापार अधिशेष में सुधार हुआ [चार्ट II.7.8बी]।

II.7.12 अप्रैल 2026 तक, भारत ने 24 विदेशी व्यापार समझौतों (एफ़टीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। नए व्यापार गठबंधनों के साथ व्यापार विविधीकरण के प्रयासों को तेज़ करते हुए, भारत ने 24 जुलाई, 2025 को यूनाइटेड किंगडम के साथ एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए), 18 दिसंबर, 2025 को ओमान के साथ एक व्यापक आर्थिक और साझेदारी समझौता (सीईपीए), और 27 अप्रैल, 2026 को भारत-न्यूजीलैंड एफ़टीए पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते अभी लागू होने बाकी हैं। यूरोपीय संघ के साथ एफ़टीए पर बातचीत भी 27 जनवरी 2026 को पूरी हो गई ।

अज्ञात मदें

II.7.13 भारत के अज्ञात व्यापार से प्राप्तियाँ - जिसमें सेवाओं, आय और अंतरणों में सीमा-पार लेनदेन शामिल हैं - वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान मज़बूत बनी रहीं। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान निवल सेवा निर्यात में 15.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मज़बूत संवृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाएं रही (जो सेवा निर्यात का 77.8 प्रतिशत हैं) [चार्ट II.7.9]। अन्य प्रमुख सेवाओं में, परिवहन से प्राप्तियों में 7.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण समुद्री माल ढुलाई[50] में कमी रहा। यात्रा सेवाओं के निर्यात में भी गिरावट आई, जो इस अवधि के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी को दर्शाता है। आगे

चार्ट II.7.8 : भारत का पण्य वस्तु व्यापार घाटा बढ़ोतरी

ए. कुल व्यापार संतुलन और तेल व्यापार संतुलन

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

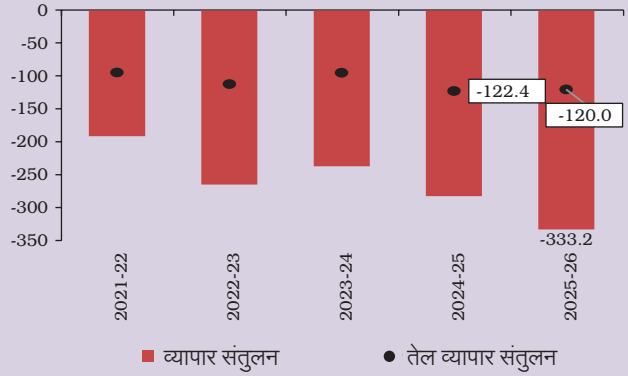

बी. भारत के व्यापार संतुलन में परिवर्तन के स्रोत
[वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26]

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

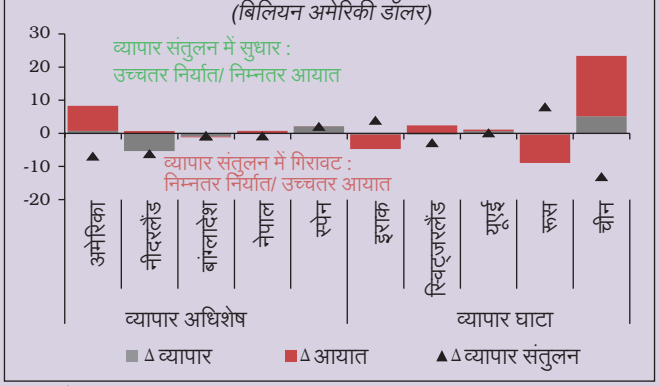

टिप्पणी: एक सकारात्मक Δनिर्यात/ Δआयात का अर्थ अधिकतम निर्यात/आयात है और यह विलोमत: भी सही है।
स्रोत: डीजीसीआईएस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान ।

[50] महामारी के बाद के दौर (2021-22 से 2024-25) में, भारत के कुल परिवहन सेवाओं के निर्यात में समुद्री परिवहन का हिस्सा औसतन लगभग 66.0 प्रतिशत रहा । समुद्री परिवहन के अंतर्गत, समुद्री माल-भाड़ा प्राप्तियों का हिस्सा लगभग 71.0 प्रतिशत रहा । अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान समुद्री माल ढुलाई में आई गिरावट की वजह वैश्विक व्यापार नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितताएँ और भू-राजनीतिक तनाव रहे ।

चार्ट II.7.9 : भारत के सेवा निर्यात की संरचना

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

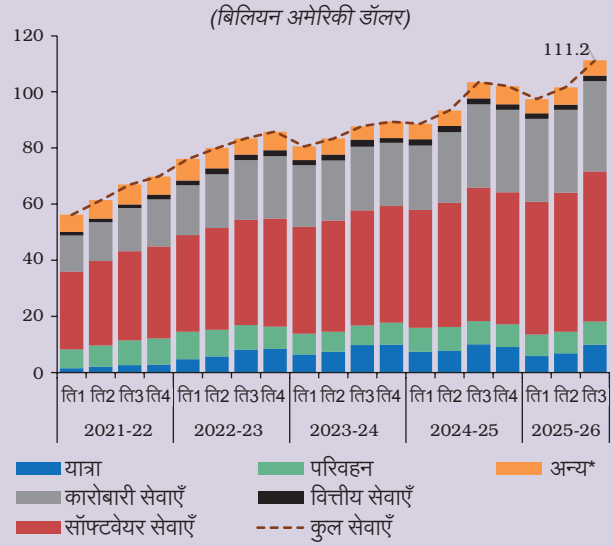

*: अन्य में बीमा सेवाएं और संचार सेवाएं शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

चलकर, गार्टनर[51] द्वारा अनुमानित मज़बूत वैश्विक आईटी खर्च, भारत के सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात के लिए अच्छा संकेत है।

II.7.14 निजी अंतरण प्राप्तियों में—जो मुख्य रूप से विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजे गए धन (विप्रेषण) को दर्शाती हैं—अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 10.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मज़बूत संवृद्धि दर्ज की गई (अप्रैल-दिसंबर 2024 में यह 16.2 प्रतिशत थी)। भारत में 200 अमेरिकी डॉलर की राशि विप्रेषण के रूप में भेजने की औसत लागत 2025 की तीसरी तिमाही में, एक वर्ष पहले के समान, 5.3 प्रतिशत रही; यह वैश्विक औसत लागत 6.4 प्रतिशत से तो कम है, लेकिन फिर भी 2030 तक के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के 3 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है।

II.7.15 अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान प्राथमिक आय लेखा[52] में निवल बहिर्गमन 37.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2024 के 36.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। यह इसी अवधि में आवक एफडीआई के चलते लाभांश भुगतान और पुनर्निवेशित आय में हुई वृद्धि को दर्शाता है।

II.7.16 निवल सेवा प्राप्तियों और श्रमिकों के विप्रेषण की तेजी ने पण्य व्यापार घाटे में हुई बढ़ोतरी को बड़ी हद तक संतुलित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) 30.2 अरब अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) तक सीमित रहा, जबकि एक वर्ष पहले की समान अवधि में यह यह 36.7 अरब अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) था (चार्ट II.7.10)।

बाह्य वित्तपोषण

II.7.17 अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए वैश्विक माहौल चुनौतीपूर्ण बना रहा।इस पृष्ठभूमि में, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान निवल पूंजी प्रवाह में (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) नरमी आई और यह चालू खाता घाटे से कम रहा; जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान भुगतान संतुलन के आधार पर (मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर) विदेशी मुद्रा भंडार में 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई (चार्ट II.7.11 और परिशिष्ट सारणी 7)।

चार्ट II.7.10: सेवाओं और आवक अंतरण द्वारा समर्थित चालू खाता शेष

(जीडीपी का प्रतिशत)

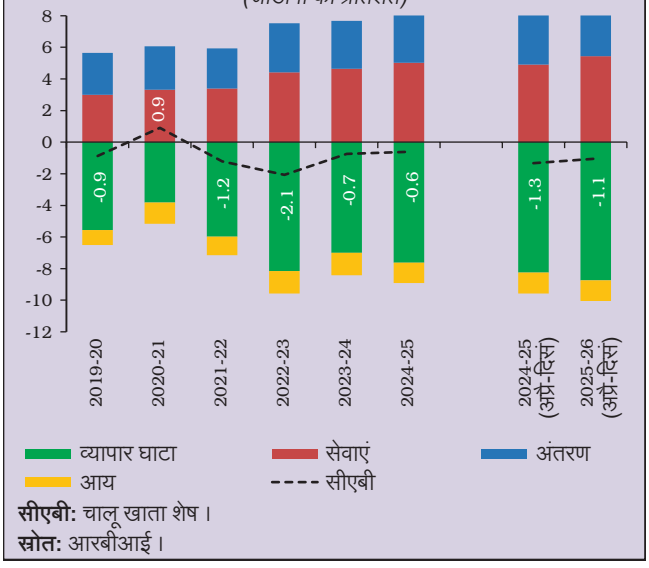

सीएबी: चालू खाता शेष।

स्रोत: आरबीआई।

[51] 'गार्टनर का अनुमान: 2026 में दुनिया भर में आईटी खर्च 13.5 प्रतिशत बढ़कर कुल $6.31 ट्रिलियन हो जाएगा', प्रेस विज्ञप्ति, गार्टनर इंक., 22 अप्रैल 2026।

[52] सीमा-पार निवेश से होने वाली आय और कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो घरेलू निवासी संस्थाएँ शेष दुनिया से अर्जित करती हैं या उन्हें भुगतान करती हैं।

चार्ट II.7.11: चालू खाता घाटे का वित्तपोषण

(जीडीपी का प्रतिशत)

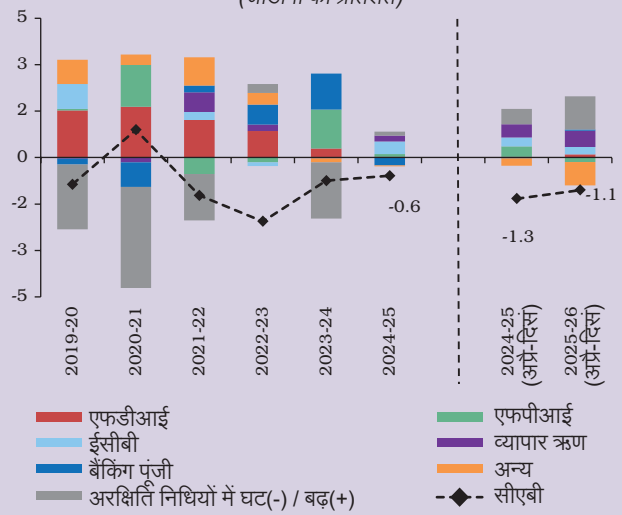

सीएबी: चालू खाता शेष ।
स्रोत: आरबीआई ।

II.7.18 पूंजी प्रवाह के अंतर्गत, 2025-26 के दौरान, सकल और निवल दोनों आधारों पर एफ़डीआई शीर्ष पर बना रहा (सारणी II.7.2)। एफ़डीआई मार्केट्स[53] के अनुसार, वैश्विक स्तर पर, 2025-26 के दौरान ग्रीनफील्ड एफ़डीआई घोषणाओं के मामले में भारत, अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रहा।

II.7.19 2025-26 के दौरान, भारत में एफ़डीआई इक्विटी प्रवाह में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का रहा, इसके पश्चात विनिर्माण क्षेत्र[54] का स्थान रहा। एफ़डीआई के मुख्य स्रोत देशों यानी सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, जापान, नीदरलैंड और यूएई ने इस प्रवाह में लगभग चौथे-पांचवे हिस्से का योगदान दिया। इस अवधि के दौरान भारत से बाहर जाने वाले एफ़डीआई में भी बढ़ोतरी हुई, तथा सिंगापुर, अमेरिका, यूएई और मॉरीशस इसके प्रमुख गंतव्य रहे। वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं; विनिर्माण; और थोक/खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल—ये भारत के बाहर जाने वाली एफ़डीआई के मुख्य क्षेत्र रहे।

II.7.20 2025-26 के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) में 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्गमन दर्ज किया गया, जिसका प्रमुख कारण इक्विटि खंड रहा (सारणी II.7.2)। सिर्फ़ मार्च 2026 में ही, 28 फरवरी 2026 को पश्चिम एशिया में संघर्ष छिड़ने के कारण, निवल एफ़पीआई बहिर्गमन 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। कर्ज क्षेत्र में 2025-26 में 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मामूली अंतर्वाह देखा गया, जो अनिश्चित वैश्विक माहौल के बीच सुरक्षित

सारणी II.7.2: पूंजी प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मदें	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5
1. निवल एफ़डीआई (1.1 - 1.2)	28.0	10.2	1.0	7.7
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1 - 1.1.2)	42.0	26.8	29.1	40.9
1.1.1 सकल अंतर्वाह	71.4	71.3	80.6	94.5
1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	29.3	44.5	51.5	53.6
1.2 निवल जावक एफडीआई	14.0	16.7	28.2	33.3
2. भारत में निवल एफ़पीआई	-4.8	44.6	3.3	-16.5
3. भारत में निवल ईसीबी	-4.1	3.5	18.5	12.0
4. **अनिवासी जमाराशियां**	9.0	14.7	16.2	14.4
4.1 अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	2.5	4.2	4.7	7.9
4.2 अनिवासी साधारण खाता	4.0	4.2	4.4	5.5
4.3 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	2.4	6.4	7.1	0.9

टिप्पणी: कॉलम 5 में भारत में निवल एफ़पीआई के आंकड़े एनएसडीएल से लिए गए है। पिछले वित्तीय वर्षों के एफ़पीआई आंकड़े बीओपी पर आधारित है ।
स्रोत: आरबीआई; और एनएसडीएल ।

[53] एफ़डीआई मार्केट्स 2003 से दुनिया भर के सभी बाज़ारों और क्षेत्रों में ग्रीनफ़ील्ड एफ़डीआई को वास्तविक समय में ट्रैक करने वाला एक प्रमुख ऑनलाइन डेटाबेस है ।

[54] सेवा क्षेत्र—जिसमें कंप्यूटर, वित्तीय, संचार और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं—का 2025-26 के दौरान कुल एफ़डीआई इक्विटी प्रवाह में लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा रहा; जबकि 2021-22 से 2024-25 के दौरान इसका औसत हिस्सा 38 प्रतिशत था ।

सारणी II.7.3:बाह्य भेद्यता संकेतक (मार्च अंत)

(प्रतिशत, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो)

संकेतक	2013	2023	2024	2025	दिसंबर-अंत 2025
1	2	3	4	5	6
1. बाह्य कर्ज़ और जीडीपी अनुपात#	22.4	19.6	19.2	19.8	20.4
2. कुल ऋण और अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	20.6	19.1	18.3	19.7
3. कुल ऋण और अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	44.0	43.4	41.2	43.2
4. रियायती ऋण और कुल ऋण का अनुपात	11.1	8.2	7.4	6.9	7.0
5. कुल ऋण और आरक्षित मुद्रा का अनुपात	71.3	92.7	96.6	90.8	89.8
6. आरक्षित मुद्रा और अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	22.2	19.7	20.1	21.9
7. आरक्षित मुद्रा और अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	47.4	44.9	45.4	48.1
8. आयात का रिज़र्व कवर (महीनों में)*	7.0	9.6	11.3	11.0	10.8
9. ऋण सेवा अनुपात (चालू प्राप्तियों के लिए ऋण सेवा)@	5.9	5.3	6.7	6.6	5.8
10. विदेशी ऋण (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	623.9	668.9	736.4	765.5
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) [बिलियन अमेरिकी डॉलर]	-326.7	-367.0	-361.3	-329.1	-260.5
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-11.6	-10.5	-9.0	-7.1
13. सीएबी/जीडीपी अनुपात@	-4.8	-2.1	-0.7	-0.6	-1.1

#: 2023 से आगे के अनुपात, आधार वर्ष 2022-23 के साथ जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला पर आधारित हैं।
*: नवीनतम चार तिमाहियों के पण्य वस्तु आयात के आधार पर, बीओपी आंकड़ों में प्रकाशित।
@: कॉलम 6 से संबंधित आंकड़े अप्रैल-दिसंबर 2025 के हैं।
स्रोत: आरबीआई और भारत सरकार।

आस्तियों के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। इक्विटी की बिकवाली में मुख्य योगदान सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और तेज़ गति से बिकने वाले उपभोक्ता सामान क्षेत्रों का रहा। अंतर्वाह मुख्य रूप से पूंजीगत सामान, धातु और खनन, और दूरसंचार क्षेत्रों में दर्ज किया गया।

II.7.21 2025-26 के दौरान, भारत में निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार अंतर्वाह पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया। ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग के अलावा, ईसीबी का उपयोग पिछले ईसीबी के पुनर्वित्तपोषण, पूंजीगत वस्तुओं के आयात और नई परियोजनाओं के लिए किया गया। एफ़सीएनआर(बी) जमाओं के तहत निवल अंतर्वाह में गिरावट के कारण, 2025-26 के दौरान अनिवासी जमाओं के तहत निवल अंतर्वाह भी पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया।

प्रमुख भेदता संकेतक

II.7.22 भारत के प्रमुख बाह्य क्षेत्र भेदता संकेतक, जैसे कि बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात, ऋण सेवा अनुपात और निवल आईआईपी जीडीपी अनुपात, दिसंबर 2025 के अंत में नियंत्रित स्तर पर बने रहे (सारणी II.7.3)। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार ने बाह्य जोखिमों और उनके प्रसार-प्रभावों को कम करने के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच प्रदान किया। मुद्रा भंडार ने लगभग 11 महीनों के पण्य वस्तु आयात[55] (भुगतान संतुलन आधार पर) के लिए सुरक्षा प्रदान की, जबकि दिसंबर 2025 के अंत में कुल बाह्य ऋण के मुकाबले मुद्रा भंडार का अनुपात लगभग 90 प्रतिशत बना रहा।

निष्कर्ष

II.7.23 पण्य वस्तु व्यापार घाटे के बढ़ने के बावजूद, 2025-26 के दौरान भारत की बाह्य क्षेत्र भेदता कम बनी रही, जिसे सेवाओं के निर्यात और निजी अंतरण प्राप्तियों में लगातार संवृद्धि से समर्थन मिला। हालांकि, निवल पूंजी प्रवाह बाह्य वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने में पीछे रह गया और पोर्टफोलियो प्रवाह में शुद्ध बहिर्वाह देखने को मिला, फिर भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और बाह्य ऋण देनदारियों के रूप में मौजूद मजबूत बफ़र्स ने बाह्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना जारी रखा, जिससे समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में योगदान मिला।

[55] मार्च 2026 के अंत में, वस्तुओं और सेवाओं के लिए लगभग नौ महीने का आयात कवर था।